राष्ट्रीय छात्रशक्ति

अगस्त १९७८ मूल्य एक रुपया

* शिक्षा क्षेत्र में वामपंथी राजनीति
* राजस्थान में छात्र आन्दोलन
* दिल्ली विश्वविद्यालय : [illegible] जारी

With Best Compliments

From

GRAMS : "WIREPLANT"

OFFICE : 59 17 07

FACTORY : 59 34 49

Refrigeration & Machinery Corporation

SPECIALISTS FOR :

* WIRE DRAWING MACHINERY
* DRAW BENCHES

&

* ROLLING MILL EQUIPMENTS

FACTORY & OFFICE :

DR. RAJENDRA PRASAD ROAD, OPP. JAWAHAR TALKIES

MULUND, BOMBAY-400 080

इस अंक में

१५ अगस्त पर श्री अरविन्द का राष्ट्र के नाम सन्देश		३१
शिक्षा क्षेत्र में वामपंथी राजनीति	—प्रकाश मेहता	६
शिक्षक : वेतनभोगी या बुद्धिजीवी	—ओमप्रकाश कोहली	२०
महाराष्ट्र में ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान	—ज्योति दाते	२४
वन्दे मातरम की गूंज और फांसी की वह रात	—राष्ट्र प्रकाश	२२

मत	व्यक्तिवाद का जहर — अरुण जेटली	५
दृष्टिकोण	अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन का आधार — प्रो० बाल आप्टे	४२
भेंटवार्ता	केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से अरुण-जेटली की बातचीत	२५
विशेष रिपोर्ट	राजस्थान में छात्र आन्दोलन — सुनील भार्गव	८
परिचर्चा	राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन : आम सहमति के बिन्दु — प्रस्तोता : आनन्द भारती	२६
रपट	राजस्थान विश्वविद्यालय : हमलावर कौन है ?	१४
	दिल्ली विश्वविद्यालय : इमरजेंसी जारी है	१२
	पटना विश्वविद्यालय : तालाबन्दी और परीक्षा	१५
	बंबई विश्वविद्यालय : भाषा की राजनीति	१५
	गोरखपुर विश्वविद्यालय : महाविद्यालयों का बोझ	१६
	उग्रपंथियों का शिकार मिथिला विश्वविद्यालय	१६
	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा का सवाल	१७
शिक्षा	शिक्षा मंत्रियों का दिल्ली सम्मेलन	१७
	हरियाणा : दस धन दो पर बहस जारी	१७
	उत्तर प्रदेश : उपकुलपतियों का एक और सम्मेलन	१८
जिसकी चर्चा है	युवकों को पथभ्रष्ट करने का रूसी कुचक्र हवाना सम्मेलन	३१
अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि		३४
	अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और युवा आंदोलन — ब्रजमोहन मलिक	
	हवाना सम्मेलन : के०जी०बी० का एक आप्रेशन	
कविता	विवेकानन्द, अनिल कुमार 'मधुकर' सुनील जैरथ	३६
खेल संसार	राजस्थान में खेल परिषद का पुनर्गठन — संदीप भार्गव	३७
युवजन— ३८;	कॉफी हाउस से — ३६;	पाठकों के पत्र — ४

शुल्क की दर

वार्षिक	...	...	१० रुपये
त्रिवार्षिक	...	...	२५ रुपये
आजीवन	...	...	१०० रुपये

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधि मासिक

□ वर्ष १ □ अंक ३ □ अगस्त, १९७४

अपनी बात

'राष्ट्रीय छात्र शक्ति' का तीसरा अंक आपके हाथों में है। इससे पूर्व के दो अंकों का देश के कोने-कोने से पाठकों ने स्वागत किया है—यह हमें नित्य प्राप्त हो रहे अनेक पाठकों के पत्र से प्रगट है। जिन पाठकों ने अपने पत्र हमें भेजे हैं, उन सभी के हम अत्यन्त आभारी हैं।

अधिकांश पाठकों का विचार है कि शिक्षा क्षेत्र की विविध समस्याओं वाली एक राष्ट्रीय पत्रिका का देश में अभाव रहा है—'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' ने इस कमी को पूरा कर दिया है। कई पाठकों ने अपने अनेक सुझाव भेजे हैं तथा इस पत्रिका के स्वरूप और स्तर को बनाए रखने की हमसे अपेक्षा की है। इस संबंध में हमें इतना ही कहना है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के स्तर को बनाए रखने का हमने निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त अपने सीमित साधन में पाठकों के अधिक से अधिक सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे।

प्रत्येक अंक में कुछ न कुछ सम-सामयिक सामग्री प्रकाशित करने के सुझाव को सहर्ष स्वीकार करते हुए इस अंक में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर महर्षि अरविन्द द्वारा प्रथम पन्द्रह अगस्त पर दिया गया अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्देश प्रकाशित किया गया है। अमर शहीद खुदीराम बोस के क्रान्तिकारी जीवन पर प्रकाश डालने वाला एक लेख उनकी पुण्य स्मृति में दिया जा रहा है।

"राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन : आम सहमति के बिन्दु" विषय पर परिचर्चा की प्रथम किस्त इस अंक में प्रस्तुत है। अगले अंकों में भी यह परिचर्चा जारी रहेगी। इस विषय पर पाठकों की राय आमन्त्रित है। ३० अगस्त तक प्राप्त आपके विचारों को प्रकाशित किया जाएगा।

जुलाई के अंक में प्रकाशित 'कहानी एक भ्रष्ट वाइसचान्सलर की' के संबंध में अनेक पाठकों ने हमें पत्र लिखकर अन्य विश्वविद्यालयों में फैले भ्रष्टाचार के मामलों को प्रकाशित करते रहने का आग्रह किया है। इस कार्य को पाठकों के सहयोग से ही सम्पादित करते रहने में हम समर्थ हो सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की कई घोर अनियमितताओं को उजागर करने वाला एक लेख इस अंक में दिया गया है। एक जांच आयोग ने मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सही पाया है। इस सम्बन्ध में जानकारी सितम्बर अंक में प्रकाशित होगी।

विश्वास है पाठक अपना स्नेह बनाये रखेंगे तथा अपने सुझावों से हमें बराबर अवगत कराते रहेंगे।

सम्पादक
अरुण जेटली

प्रबन्ध सम्पादक
महावीर दत्त गिरि

सम्पर्क हेतु :
'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' हिन्दी मासिक
२६, बंगलो मार्ग, कमलानगर, दिल्ली-११०००७

पाठकों के पत्र

सराहनीय प्रयास

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का जून और जुलाई अंक पढ़ने को मिला। शैक्षणिक तथ्यों को जिस ढंग से आपने सम्पादित किया है वह निःसन्देह इस बात की पुष्टि करता है कि 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' शिक्षा क्षेत्र की सही प्रतिनिधि पत्रिका है। दोनों ही अंकों में इस बात के प्रयास में सार्थकता है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में शैक्षणिक ढांचे को सही आकृति प्रदान करने के लिए राजनैतिक स्वार्थ एवं सत्ता के लोभ पर करारा प्रहार किया गया है। शैक्षणिक क्षेत्र में प्रशासन के नाम पर दुराचार, छात्र अशांति, संपूर्ण क्रान्ति के राजनैतिक घोंस को बाखूबी प्रस्तुत किया गया है। आवरण, साज-सज्जा सराहनीय है। पत्रिका की प्रगति के लिए शुभकामनाओं सहित मेरी बधाई स्वीकार करें।

डा० दीनानाथ सिंह
प्राध्यापक, दयानन्द महाविद्यालय,
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

शिक्षा क्षेत्र को सही आयाम

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के प्रथम अंक को पढ़कर सचमुच ऐसा लगा कि यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में शीघ्र सफल होगी। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में शिक्षा क्षेत्र को सही आयाम दे सकने में पत्रिका उपयोगी सिद्ध होगी। मैं कहना चाहूंगा कि पत्रिका में पाठकों के लिए एक स्तंभ अवश्य रखा जाय।

अनिल कान्त मिश्र
दरभंगा (बिहार)

प्रतिनिधि पत्रिका

मुझे जुलाई अंक प्राप्त हुआ। देश के समस्त विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी देने वाली एवं विद्यार्थियों की समस्याओं को सामने रखने वाली वास्तव में यही एक पत्रिका सामने आयी है। मैं इस पत्रिका की दिनोंदिन उन्नति के लिए कामना करता हूं एवं उम्मीद करता हूं कि इस पत्रिका का निरन्तर विकास होता रहेगा।

राजकृष्ण अग्रवाल
भाभा होस्टल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

हरद्वारी लाल

जुलाई अंक में 'कहानी एक भ्रष्ट वाइस-चांसलर की' शीर्षक से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के उपकुलपति हरद्वारी लाल के काले कारनामों का पर्दाफाश करके वास्तव में आपने साहसिक कार्य किया है। इससे मेडिकल कालेज के आन्दोलनकारी छात्रों का मनोबल बढ़ा है। हरद्वारी लाल जैसे अनेक उपकुलपति इस देश में होंगे। आशा है 'राष्ट्रीय-छात्रशक्ति' उन सबका पर्दाफाश करेगी जिससे शिक्षा क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके।

अनिल शर्मा
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण

जुलाई अंक में हरद्वारी लाल पर जो सामग्री प्रस्तुत की है वह अधूरी है। हरद्वारी लाल देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। जो राज्य सरकार एक मामूली उपकुलपति से इतना डरे कि उसे जो चाहे सो करने के लिए विश्वविद्यालय में छोड़ दे, उस सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस जनता पार्टी ने शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने की बात कही थी, उसी की सरकार अब भ्रष्ट अधिकारियों को केवल शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं अपितु सभी क्षेत्रों में संरक्षण दे रही है।

पंकज कुमार
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय
रोहतक (हरियाणा)

छात्रों की आकांक्षाओं पर कुठाराघात

जुलाई अंक में 'उत्तर प्रदेश में छात्र अशान्ति' पर विशेष रिपोर्ट और जून अंक में 'बिहार में छात्र आन्दोलन' पर विशेष रिपोर्ट दोनों को ही एक साथ पढ़ने का मौका मिला। इतनी गम्भीर और सन्तुलित सामग्री प्रकाशित करने के लिए मैं 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' परिवार को बधाई देता हूं। बिहार आन्दोलन मुख्यतः छात्रों ने चलाया था और उस आन्दोलन के परिणामस्वरूप सत्ता में आयी जनता पार्टी ने छात्रों की आकांक्षाओं पर कुठाराघात प्रारम्भ कर दिया है। सत्ता के लोभ में कुछ नेताओं के दिग्भ्रमित होने के कारण छात्र शक्ति को बिखरने का खतरा हो गया है। 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' मासिक ने देश भर के छात्रों को एक मंच प्रदान कर उनकी आशाओं को पुनः संगठित करने का प्रयास किया है। मैं इस पत्रिका की प्रगति की कामना करता हूं।

विश्वास कुमार सिंह
शोध छात्र, समाज शास्त्र विभाग
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

निष्पक्ष और रोचक

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के प्रथम अंक का मुख पृष्ठ छात्रों-युवाओं को अपनी संगठित ताकत का बोध कराता है। संगठित ताकत का बोध इसलिए हुआ कि पत्रिका में अनेक छात्र-युवा संगठनों तथा अन्य विचारधारा वाले राजनैतिक नेताओं के विचारों को निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया गया है। जुलाई अंक पहले अंक से अधिक रोचक है। 'बन्द करो यह रैगिंग' लेख बेहद पसन्द आया।

सुरेश श्रीवास्तव
सागर विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश)

नानाजी देशमुख का आदर्श

जून का प्रथम अंक गंभीरतापूर्वक पूरा पूरा पढ़ गया। 'छात्र संसद' की परिचर्चा अच्छी लगी। श्री नानाजी देशमुख से श्री महावीर दत्त गिरि की भेंट वार्ता भी बहुत अच्छी लगी। श्री नानाजी देशमुख इस प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाये कि युवकों को रचनात्मक कार्य के लिए वह किस आदर्श से प्रेरित करेंगे? बिहार के छात्र आन्दोलन पर विशेष रिपोर्ट भी जानकारी पूर्ण रहा।

रवीन्द्र नाथ शर्मा
जबलपुर (मध्य प्रदेश)

विचारणीय मुद्दा

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के दोनों अंक पढ़ने को मिले। छात्रों को अपनी एक पत्रिका की कमी एक लम्बे अरसे से महसूस हो रही थी। आपने जो पत्रिका निकाली है। उसने इस कमी को पूरा कर दिया है। जून के अंक में 'रचनात्मकता की बजाय विध्वंस को प्राथमिकता क्यों' शीर्षक लेख में लेखक श्री राष्ट्रप्रकाश ने कुछ विचारणीय मुद्दे उठाये हैं। उन पर विचार किया ही जाना चाहिए।

सुधाकर गोस्वामी
भीलवाड़ा (राजस्थान)

मत

व्यक्तिवाद का जहर

□ अरुण जेटली

जनता पार्टी टूटने से बच गयी है पर जनता टूटती जा रही है। जनता ने जनता पार्टी को अपना वोट इसलिए दिया कि इन्दिराशाही की दूषित राजनीति में स्वच्छता आयेगी तथा राजनीति विचारधाराओं और सिद्धान्तों के टकराव की होगी न कि व्यक्तिवाद की। पर इन आशाओं के विपरीत जनता के साथ धोखा हुआ है। श्री मोरारजी देसाई और श्री चरणसिंह दोनों ही जनता के साथ विश्वासघात करने के दोषी है।

श्री चरणसिंह की राजनीति व्यक्तिवाद से प्रभावित रही है। वह किसानों के नाम पर जातिवाद का सहारा लेने से हिचकते नहीं हैं। उनकी राजनीति उनके व्यक्तित्व के आसपास घूमती है। उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ही अनेक अवसरवादी तत्व उनके सलाहकार बनते हैं। चौधरी साहब ने जबसे कांग्रेस छोड़ी तब से लेकर अब तक न जाने कितने सलाहकार उन्हें धोखा दे चुके है जिनमें श्यामलाल यादव, मोहनसिंह, पृथ्वीनाथ सेठ, जयरामवर्मा, ब्रह्मदत्त, सत्यपाल मलिक, वीरेन्द्र वर्मा के नाम उल्लेखनीय है। शायद यही हाल उनके वर्तमान सलाहकारों का भी है।

भूतपूर्व भारतीय लोकदल से सम्बन्धित चार कैबिनेट स्तर के तथा आठ राज्य मन्त्री थे। उनमें से आधे भी आज चौधरी चरणसिंह के साथ नहीं हैं। अपने सलाहकारों के चयन में चौधरी साहब हमेशा बचकानी भूल करते रहे है।

इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्री राजनारायण के सार्वजनिक व्यवहार से जनता बेहद नाराज थी। जनता पार्टी के आन्तरिक मामलों पर सार्वजनिक भाषण देना उनकी दिनचर्या का एक अंग बन चुका था। श्री चरणसिंह की भूल यह थी कि उन्होंने श्री राजनारायण को ऐसा करने से रोका नहीं बल्कि वह उनको बढ़ावा ही देते रहे। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल को नपुंसक कह देना, श्रीमति गान्धी की गिरफ्तारी के मसले को मन्त्रिमण्डल में न उठाकर समाचार पत्रों में उस पर वक्तव्य देना, बार-बार अपने त्याग पत्र एवं दल के विघटन की धमकी देना चौधरी चरणसिंह का अशोभनीय व्यवहार था। इस व्यवहार के परिणाम से उन्होंने सबक सीखा है— उनके व्यवहार में बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

जनता पार्टी के आन्तरिक संघर्ष के लिए प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई भी दोषी है। आन्तरिक संघर्ष के दौरान जब युद्ध विराम का प्रयास चल रहा था तो समाचार पत्रों के माध्यम से दो बार वक्तव्य देकर श्री देसाई ने युद्ध विराम के प्रयास को विफल करने की चेष्टा की। कोटा में उन्होंने कहा कि श्री राजनारायण चाहें तो दल छोड़ सकते हैं और श्रीनगर में वक्तव्य दिया कि वे स्वयं श्री चरणसिंह से नहीं मिलेंगे। इन दोनों ही बातों से पार्टी के भीतर तनाव को बढ़ावा मिलता है। श्री देसाई पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनके द्वारा यह घोषणा कि "मैं गलती नहीं कर सकता," आन्तरिक झगड़ों में फंसी जनतापार्टी की एकता के लिए हानिकारक है।

राजनैतिक कारणों से प्रेरित व्यवहार की सीमा यह थी कि श्री देसाई और चौधरीसाहब दोनों ने ही व्यक्तिवाद के झगड़े को वैचारिक रंग देने का पूरा प्रयास किया। चौधरी साहब का यह आरोप है कि पार्टी का विवाद गांधीवाद और नेहरूवाद का है, शहर और गांव का है। आर्थिक नीतियों को लेकर तथा श्रीमतिगान्धी की गिरफ्तारी और कांति देसाई के विरुद्ध जांच आयोग के प्रश्नों को लेकर भी विवाद है। लेकिन यह सब एक बहाना ही प्रतीत होता है। चौधरी चरण सिंह द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतियों को जनता पार्टी ने पहले ही बहुमत से स्वीकार कर लिया है। दूसरी बातों को उन्होंने पार्टी या मन्त्रिमण्डल के समक्ष कभी उठाया ही नहीं।

वस्तुतः सारा विवाद श्री राजनारायण की दल विरोधी गतिविधियों को लेकर आरंभ हुआ था। और श्री राजनारायण को रोकने के स्थान पर चौधरी साहब उनको बढ़ावा देते रहे। लेकिन इन दोनों नेताओं के इन दो आरोपों में कुछ सच्चाई है कि पार्टी के संगठनात्मक चुनावों को रोके रखने का योजनाबद्ध प्रयास चल रहा है और यह कि जब कई राज्यों में दल विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था तो श्री देसाई और श्री चन्द्रशेखर चुप थे। श्री चन्द्र भानु गुप्ता, श्री कृष्णकांत, श्री रामधन आदि ने जो वक्तव्य दिये वे स्पष्टतः दल विरोधी थे। हरिजनों पर तथाकथित सरकारी अत्याचार के मामले को विश्व न्यायालय में ले जाने की श्री रामधन धमकी देते रहे। श्री चन्द्रभानु गुप्ता अविभाजित कांग्रेस पार्टी के पुनः निर्माण के लिए प्रयास करते रहे और मध्यप्रदेश में तो कई विधायक अपनी ही जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने की धमकी देते रहे। इन सभी अवसरों पर प्रधान मन्त्री और पार्टी के अध्यक्ष बिलकुल चुप थे। अतः श्री देसाई और श्री चन्द्रशेखर का यह कहना गलत है कि श्री चरण सिंह के विरुद्ध यह अनुशासनहीनता की कारवाई की गई है। अनुशासनहीनता पर यह उनकी दोहरी नीति है। अनुशासनहीनता को रोकने में पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर और प्रधानमन्त्री श्री देसाई दोनों ही असफल रहे। इसका कारण यही है कि ये दोनों नेता अभी तक गुट नेता के रूप को अपनाये हुए हैं।

इस सारी कीचड़ में आशा की किरण वे लोग थे जो दल की एकता बनाये रखने का पूरा प्रयास करते रहे। जनता पार्टी की असफलता उन लोगों को मजबूत करेगी जो इस धारणा को स्वीकार कराना चाहते हैं कि आपात स्थिति में ही यह देश चल सकता है। जनता पार्टी की एकता बनाये रखने के लिए इससे सहानुभूति रखने वाली अन्य सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को जनता पार्टी पर अपना दबाव बढ़ाना होगा।

•••

शिक्षा क्षेत्र में वामपंथी राजनीति

प्रबाल मैत्र

भारत में शिक्षा क्षेत्र में वामपंथी राजनीति का अभी तक का चरित्र देश और शिक्षा क्षेत्र के लिये तो घातक साबित हुआ ही है, साथ ही उसने 'वामपंथ' के साथ भी जबरदस्त धोखा किया है। मौकापरस्ती के हाथों में किसी 'क्रांतिकारी पथ' की कैसी दुर्गति होती है — शिक्षा क्षेत्र में वामपंथी गतिविधियां उसकी ज्वलंत मिसाल हैं।

मैकाले को बनाये रखने का श्रेय

भारत में स्वयं को वामपंथी खिताब से विभूषित करने वाले दो तबके हैं पहला कम्युनिस्ट और दूसरा सोशलिस्ट। चूंकि दोनों तबकों की मान्यता यह रही है कि भारत में उनके सपनों की क्रांति की रहनुमाई करने के लिये बुद्धिजीवियों का 'अग्रगामी दस्ता' जरूरी है, इसलिये दोनों वामपंथी तबकों ने शिक्षाक्षेत्र में अन्दर तक पुसपैठ करने का प्रयास किया है और इस कोशिश में वे कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। यह बात दीगर है कि क्रांति का 'अग्रगामी दस्ता' बनने के बजाय वे खुद व्यवस्था के पिछलग्गू बन गये। लेकिन इतने पर भी उन्हें इस बात की तो सफलता मिली ही है कि उन्होंने संपूर्ण शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया है। अगर मैकाले को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने बाबू पैदा करने के कारखाने खोले तो आजादी के बाद शिक्षा क्षेत्र में चल रही वामपंथी राजनीति को ही यह श्रेय मिलना चाहिये कि यह वैसी ही बनी हुई है जैसा कि मैकाले ने चाहा था।

शिक्षा क्षेत्र में राजनीति घुसाने की पहली कोशिश कम्युनिस्टों ने ही की। देश को आजादी मिलने के पहले शिक्षा क्षेत्र के लोग अध्यापक तथा छात्र अवश्य राजनीति में सक्रिय थे, वे आजादी की लड़ाई में जोर शोर से हिस्सा ले रहे थे। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में राजनीति की घुसपैठ नहीं हुई थी। कांग्रेस की छतरी के नीचे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में काम करते जब कम्युनिस्टों और उनके कुछ मार्गदर्शकों को लगा कि अब कम्युनिस्टों के जड़ मजदूर तबके में कुछ कुछ जम गये हैं तो उन्होंने बुद्धिजीवी यानी शिक्षित वर्ग में काम करने की योजना बनाई। इसी दौरान अंग्रेज सरकार ने आजादी के आन्दोलन में दरार डालने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी पर से प्रतिबन्ध हटा लिया। हालांकि कम्युनिस्टों के अनुसार क्रांति के सैनिक यानी मजदूर वर्ग अभी संगठित नहीं हो सका था लेकिन तो भी वे जोर शोर से क्रांति का 'हरावल दस्ता' तैयार करने यानी शिक्षित वर्ग में अपनी जड़ जमाने में लग गये।

राजनीति के चार हिस्से

इस दृष्टि से अपनायी जाने वाली रणनीति के चार हिस्से थे—

(१) आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ रहे छात्रों को मार्क्सवाद में दीक्षित किया जाय।

(२) चूंकि भारत में आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की प्रतिष्ठा है, इसलिये वहां से लौटने के बाद ये कालेजों और विश्वविद्यालयों में घुसपैठ करें।

(३) इस घुसपैठ के बाद शोध के नाम पर विभिन्न विषयों को विशेष कर समाजशास्त्र से संबंधित विषयों को मार्क्सवादी रंग में रंगने की कोशिश की जाय।

(४) अध्यापकों और छात्रों के संगठन बनाये जायं और छात्रसंघों तथा अध्यापक संघों पर कब्जा किया जाय।

शुरुआत के दिनों में आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भारतीय छात्रों से संपर्क साधने का काम करने वाले इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव स्व० श्री दत्त स्वयं बहुत ही बुद्धिमान थे इसलिये उन्हें इस काम में कठिनाई नहीं हुई। बाद में उन्हें स्व० श्री वी० के० कृष्णमेनन जैसे सहयोगी मिल गये और आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को मार्क्सवादी रंग में रंगा जाने लगा। ये वह छात्र थे जो या तो अपनी-अपनी मेधा के कारण छात्र वृत्ति लेकर अथवा धनी घर के होने के कारण अपने पैसे से पढ़ने जाते थे और भारत लौटने के बाद बौद्धिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिष्ठा मिलने वाली थी और महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने वाले थे। रणनीति का यह हिस्सा काफी हद तक कामयाब रहा। हर साल कभी तीन महीने कभी ६ महीने के लिये भी दत्त भी भारत आने लगे और कलकत्ता तथा बम्बई में अपने चेलों की मदद से बुद्धिजीवियों को मुड़ने का प्रयास करते रहे।

यह स्वाभाविक था कि आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर लौटे छात्रों को विश्वविद्यालयों और कालेजों में जगह मिली। ये अध्यापक बड़ी सावधानी से इस कोशिश में लग गये कि भारत में कम से कम समाज शास्त्र के अध्ययन को लाल रंग में रंग दिया जाय। नये-नये ये अध्यापक विभिन्न स्थानों की कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा भाषण करने के लिये बुलाये जाते थे, उनकी खबरें छापी जाती थीं। रूस से मिल रही आर्थिक मदद के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के पास दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं की अच्छी खासी शृंखला थी जिनमें इन लोगों का प्रचार होने लगा। इनके पेपरों पर बहसों का सिलसिला चलाया जाने लगा और कई लोग अल्पायु में ही स्थापित हो गये।

लेकिन इसी जगह पर जल्दबाजी में इन लोगों द्वारा एक बड़ी गड़बड़ी हो गयी जिसका दुष्परिणाम शिक्षा क्षेत्र को आज तक भुगतना ही पड़ रहा है। मार्क्सवाद भी इस जल्दबाजी के परिणामों से अछूता नहीं है। इन मार्क्सवादी अध्यापकों में से अधिकांश धनी और उच्च मध्यवर्गीय परिवारों के थे और उनमें से कइयों ने गरीबी का वर्णन केवल मार्क्स की किताबों में पढ़ा था। भारतीय इतिहास, अर्थशास्त्र आदि की उनकी जानकारी भी यूरोपीयों द्वारा लिखी पुस्तकों तक ही सीमित थी। इसीलिए मध्यम और उच्च वर्गीय मानसिकता से ग्रस्त अंग्रेजी पुस्तकों को रटकर विद्वान हुए अध्यापकों ने भारतीय शोध को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां केवल भ्रम ही भ्रम था, मार्क्सवादी रणनीति

का पहला शिकार भारतीय बोध हुआ। फलस्वरूप आज हम इस स्थिति में पहुंच गये है कि मार्क्सवादी प्रभाव के कारण न तो हम देश का सांस्कृतिक कारण तय कर पा रहे है और न ही आर्थिक समस्याओं का समाधान खोज पा रहे है। समकालीन भारतीय चिन्तन को दल-दल में ढकेल देने में वामपंथियों की इस रणनीति को पर्याप्त सफलता मिली है।

आजादी के बाद स्व० नेहरू जी के रूस प्रेम के कारण सहयोग का जो दौर शुरू हुआ उसके चलते कम्युनिस्टों को अपनी दूसरी रणनीति को पूरा करने यानी मार्क्सवादी कहे जाने वाले लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने में सफलता मिली। श्रीमती गांधी का कार्यकाल आते आते यह चरम सीमा पर पहुंच गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महत्वपूर्ण पदों पर रूस भक्त आसीन हो गये और अपने अधिकारों का उपयोग कर उन्होंने अपने चहेतों को विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्त करना प्रारम्भ किया। शैक्षणिक योग्यता से अधिक महत्व इस बात को दिया जाने लगा कि अमुक व्यक्ति वामपंथी है या नहीं। वामपंथ के प्रति अधिकारियों के इस रूझान का फायदा उठा कर कई मौकापरस्तों ने अपने चोले रंग डाले और कम योग्य होते हुए भी महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गये। इसके दो कुपरिणाम हुए (१) मेधावी छात्र पीछे पड़ कर निरुत्साहित हो गये। (२) वामपंथी बौद्धिकों में अभी तक मध्यमवर्गीय यूरोपीय मानसिकता ही थी, अब उसमें चापलूसी और मौकापरस्ती भी शामिल हो गयी। तथाकथित वामपंथी अध्यापक और वाइसचांसलर अध्ययन अध्यापन (जो वैसे भी बस में नहीं था) छोड़कर पदोन्नति के लिए जोड़-तोड़ और भागदौड़ करने लगे। शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन में कोई प्रगति नहीं हुई और भ्रष्टाचार फलने फूलने लगा।

छात्र संगठनों पर कब्जा

आजादी के तुरन्त बाद कम्युनिस्ट पार्टी देश की युवा शक्ति को अपने चंगुल में लेने की कोशिश में लगी और उसमें वह कुछ हद तक सफल भी हुई क्योंकि आजादी के बाद दूसरा कोई प्रभावी छात्र-संगठन नहीं था और छात्र कम्युनिस्टों की 'क्रांतिकारी' लफ्फाजी में आसानी से फंस जाते थे। विद्यार्थियों में संगठन बनाने और छात्रसंघों पर कब्जा करने का कम्युनिस्टों का सिलसिला कई साल तक चलता रहा तब छात्रों के समझ में आया कि कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का उद्देश्य अपनी पार्टी का कैडर तैयार करना और युवा आन्दोलन को दिग्भ्रमित करना है। छात्रों की समस्या से उसका कोई लेना देना नहीं। आल इंडिया स्टूडेन्ट फेडरेशन का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने कभी भी 'बाबू पैदा करने वाली' शिक्षा पद्धति को बदलने की आवाज उठाने के बदले कभी 'अमरीकियों वियतनाम छोड़ो' और कभी 'दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद हटाओ' नारा देकर, जुलूस निकाल कर संतोष कर लिया। भारत के छात्रों युवकों की बुनियादी समस्याओं से उनका ध्यान वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका की ओर हटाने की कोशिश कर छात्रों के बीच घुसे कम्युनिस्ट वामपंथियों ने यथास्थितिवाद को बनाये रखने का प्रयास अभी तक किया है। छात्रों की बुनियादी मांगों—बेरोजगारी, मैस, होस्टल व्यवस्था आदि के संबंध में चल रहे आन्दोलनों को अधिकारियों के साथ मिलकर नाकाम करने की कम्युनिस्ट वामपंथी छात्र नेताओं की कोशिशों के उदाहरण भी कम नहीं है।

लगभग यही स्थिति अध्यापकों के बीच काम कर रहे कम्युनिस्टों की रही है। आजादी के बाद अध्यापकों ने शिक्षा नीति में परिवर्तन के संबंध में गंभीरता से सोचना शुरू किया था। लेकिन यथास्थितिवाद को बनाये रखने के इरादे से कम्युनिस्टों ने शिक्षक संगठनों को ट्रेड यूनियनों में बदल दिया और ये संगठन वेतन बढ़ाने की मांग में उलझा दिये गए। वामपंथी राजनीति की मौका परस्ती ने ऐसा रंग दिखाया कि आज संपूर्ण क्षेत्र यथास्थितिवाद का गढ़ बन गया है और देश की सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप किसी भी परिवर्तन का सबसे जोरदार विरोध कम्युनिस्ट तबकों की ओर से ही हुआ। अभी पिछले वर्ष वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) की कुछ प्रयोगशालाओं को संबंधित औद्योगिक मंत्रालयों से जोड़ने के विरोध में सबसे अधिक मुखर स्वर वामपंथी मौका परस्तों का था।

सोशलिस्टों की घुसपैठ

वामपंथियों का सोशलिस्ट तबका भी शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय रहा है। सन ४६-४७ के आसपास स्व० डा० राम मनोहर लोहिया को यह अहसास हुआ कि देश की युवाशक्ति का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आसानी से किया जा सकता है और इसमें घुसपैठ की जा सकती है। सोशलिस्ट पार्टी के कई सम्मेलनों में डा० लोहिया शिक्षा क्षेत्र में सोशलिस्टों के घुसपैठ की जोरदार वकालत करते रहे। उन्होंने खुद भी इस दृष्टि से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपना अड्डा बनाया। 'मुक्त चिन्तन' की वकालत करने वाले सोशलिस्टों में जीवन और समाज के प्रति समुचित दृष्टिकोण का अभाव होने के कारण वे शिक्षा क्षेत्र को कोई भी दिशा दे सकने में असफल रहे। इतना जरूर हुआ कि भविष्य में राजनीति को अपना पेशा बनाने वाले छात्र और अध्यापक उनके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो गये। इन सबने मिलकर वैचारिक और प्रशासनिक तौर पर अराजकता को जन्म दिया और उस अराजकता की सीढ़ी पर चढ़कर अपनी राजनीतिक मंजिलों पर पहुंचते गये।

चूंकि हर वामपंथी लफ्फाजी की आवाज क्रान्तिकारी होती है इसलिए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों प्रकार के वामपंथी शुरूआत के दिनों में समाज को बरगलाने में सफल रहे लेकिन थोड़े ही दिनों में इनकी मौकापरस्ती का पर्दाफाश होने लगा। आज स्थिति यह है कि शिक्षा क्षेत्र में वामपंथी राजनीति प्रभावी न होने के बावजूद मौके पर बैठे उनके लोगों के विरोध के कारण शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन और सुधार कठिन हो गया है। वामपंथी राजनीति ने शिक्षा क्षेत्र को इतना खोखला बना दिया है कि हल्का-सा धक्का भी उसे ध्वस्त कर देने के लिए काफी है।

□□□

विशेष रिपोर्ट

आपातकाल के बाद राजस्थान में छात्र आन्दोलन

सुनील भार्गव

आपातकाल की समाप्ति के पश्चात देश के शिक्षा जगत में जड़ता की स्थिति से निकलने की सम्भावनाओं का प्रबल सूत्रपात हुआ था। जनता पार्टी जन आकांक्षाओं के प्रतिबिम्ब स्वरूप सत्ता में आई। फलस्वरूप परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाले छात्र-युवा मानस में आशा की लहर उत्पन्न हुई। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा० प्रताप चन्द्र चन्दर ने शिक्षा पद्धति की जड़ता एवं शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के प्रति अपने आपको सजग एवं चैतन्य घोषित किया जिसका शिक्षा जगत में जोरदार स्वागत किया गया। किन्तु जनता शासन के एक वर्ष के क्रियाकलापों को देखकर यह आशा मुरझा गई है। राजस्थान का छात्र-युवा जगत इस स्थिति से अत्यन्त प्रभावित है। परिवर्तन की आकांक्षा उन्हें लुप्त होती दिखाई दे रही है। परस्पर टूट, जातीयता एवं क्षेत्रीयता का जहर, सामाजिक दायित्व बोध का अभाव उन्हें यह सोचने को बाध्य करता है कि क्या इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिये छात्र-युवकों ने संघर्ष किया था?

उपकुलपतियों का त्यागपत्र

राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में यह सत्र कुछ सरगर्मी के साथ प्रारम्भ हुआ। आपातकाल के दौरान तानाशाही शक्तियों का पोषण कर मनमाने ढंग से व्यवहार करने वाले उपकुलपतियों के विरुद्ध सत्र के प्रारम्भ में ही राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों (राजस्थान, उदयपुर एवं जोधपुर) में विद्यार्थी परिषद की पहल पर आवाज बुलन्द की गई जिससे घोर अनियमितताओं एवं भ्रष्ट आचरण करने वाले उपकुलपतियों को न स्वीकार करने की छात्र चेतना का एक हल्का-सा आभास हुआ। छात्रों एवं शिक्षकों के आन्दोलन के फलस्वरूप तीनों विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसा आभास हुआ कि छात्र वर्ग एक संगठित प्रयास करके समग्र परिवर्तन की दिशा में अपने आपको लगायेगा किन्तु जिस प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु जातीयता एवं क्षेत्रीयता के खेमों में छात्रों का नेतृत्व वर्ग विभाजित हुआ उससे आम विद्यार्थियों के मन में टीस एवं घुटन का वातावरण बना। छात्र-युवा संगठन अपने नित् राजनैतिक संगठनों के आधार पर बंट गये, सत्तारूढ़ जनता पार्टी भी अपने आपको जातीयता के अभिशाप से बचा पाने में पूर्णरूप से असफल रही और परिणामस्वरूप जातीयता के आधार पर दो बड़े खेमों में बंट गई। जातीयता के आधार पर राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का एक कुत्सित कुचक्र प्रारम्भ हुआ। राजस्थान का छात्र समुदाय भी दो जातीय खेमों में बंट गया। व्यक्तिगत नेतागिरी की महत्वाकांक्षा से अनुप्रेरित तत्वों को इस जातीयता एवं क्षेत्रीयता के आधार पर छात्रों को एकत्रित कर अपने दूषित लक्ष्य सिद्ध करने का अवसर हाथ लगा और सत्ताभिमुख राजनैतिक दलों के छात्र संगठनों (युवा जनता, एस० एफ० आई०, ए० आई० एस० एफ०, एन० एस० यू० आई०) ने इसे प्रश्रय देकर प्रबल एवं समर्थ बनाने का प्रयास किया। पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही एकमात्र ऐसा छात्र संगठन था जो इस जातीयता के चक्र को तोड़कर अपने कार्यक्रमों के प्रति सजग एवं सचेत रहा।

जातिवाद की राजनीति

सत्ता परिवर्तन के पश्चात व्यवस्था परिवर्तन एवं शैक्षणिक सुधार के लिए अपनी निश्चित भूमिका के अनुरूप किसी समन्वित प्रयास का अभाव अनेक विसंगतियों के कारण पूरे प्रान्त में रहा। परीक्षा की तिथियों को बदलने, होस्टल, लाइब्रेरी, कोष, स्वास्थ्य केन्द्र आदि की सुविधा, परीक्षा परिणामों की शीघ्र घोषणा, मैकिंग एवं ग्रेडिंग प्रणाली को दोषमुक्त करने, परिवहन सुविधाएं सुलभ बनाने आदि के लिए किये गये छुटपुट आंदोलनों के अतिरिक्त कोई विशेष बड़ी हलचल पूरे प्रदेश में नहीं दिखाई दी। कुछ चंद गिने-चुने छात्रों द्वारा व्यक्तिगत एवं जातीय नेतृत्व को प्रभावशाली सिद्ध करने के प्रयास में कुलपति के घेराव, कुलपति कार्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, धरना देने, बसों के अपहरण आदि की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई। किन्तु छात्रों के व्यापक समर्थन के अभाव में कोई उल्लेखनीय एवं निर्णायक आन्दोलन का सूत्रपात नहीं हो पाया। सत्तारूढ़ दल के कुछ जातीय नेताओं ने इस स्थिति को भड़काने तथा अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की और बहुत हद तक तो वे इसमें सफल भी हुए। राजस्थान के छात्रों के दुर्भाग्य की शृंखला में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और जुड़ गया। तीनों विश्वविद्यालय वर्ष भर अराजकता, अशान्ति और हिंसा के केन्द्र बने रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० ओमप्रकाश माथुर को अपनी प्रशासनीय अक्षमता एवं विश्वविद्यालय छात्रसंघ के विवाद में एकपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने के कारण अपने पद से अलग होना पड़ा। उदयपुर विश्वविद्यालय में एक जाति विशेष का पोषण करने एवं छात्र समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहने तथा अनियमितताओं के आरोपों के कारण श्री लाम्बा को त्यागपत्र देकर जाना पड़ा। जोधपुर विश्वविद्यालय में तो इस सत्र में उपकुलपति बदलने का एक दौर ही चल पड़ा। सत्र के प्रारम्भ में नियुक्त उपकुलपति श्री गोयल अपना दायित्व निभाने में असफल रहे। फलस्वरूप छात्रों एवं शिक्षकों दोनों का उन्हें कोपभाजन बनना पड़ा। दिल्ली से आये श्री भाटिया एक महीना भी मुश्किल से निकाल पाये और अपने आपको

- जातीयता एवं क्षेत्रीयता की भावना से दिग्भ्रमित एवं विभाजित छात्र समुदाय।
- जातिवादी राजनैतिक नेताओं के हित पोषण में संलग्न—किंकर्तव्यविमूढ़।
- समन्वित प्रयास के अभाव में आन्दोलन की संभावनाएं धूमिल।

असमर्थ पाकर पद त्याग कर चले गये। राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में अपनी प्रशासनिक क्षमता एवं सूझ-बूझ का प्रदर्शन करने वाले राजस्थान कालेज के शिक्षा निदेशक श्री नवरत्न मल कोठारी भी जोधपुर में अपने कौशल नहीं दिखा पाये।

भूतपूर्व न्यायाधीश की असफलता

राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री वेद पाल त्यागी को सत्र के अन्त में बहुत आशाओं के साथ लाया गया लेकिन वे भी तीन के तेरह करने में कामयाब नहीं हो सके। आने के साथ ही जिस प्रकार की घोषणाएं उन्होंने की उससे प्रतीत हुआ कि वे कुछ कर पाने में समर्थ होंगे। श्री वेदपाल त्यागी को पद ग्रहण करते ही छात्रों के एक वर्ग का घेराव सहना पड़ा। ३१ तथाकथित विश्वविद्यालय छात्रों को गिरफ्तार किया गया। छात्र दो खेमों में बंट गये और ऐसा प्रतीत हुआ कि टकराव की स्थिति बनेगी। नये कुलपति की स्थिति डांवाडोल हो गई किन्तु विद्यार्थी परिषद की निष्पक्ष सन्तुलनकारी भूमिका ने छात्रों को आंतरिक टकराव की स्थिति से उबारा। श्री वेदपाल त्यागी ने अपनी घोषणा के ठीक विपरीत आचरण करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विधि की परीक्षाओं की तिथियों को बार-बार आगे बढ़ाया। विश्वविद्यालय में अराजकता अशान्ति एवं हिंसा की वारदातों को रोक पाने में भी त्यागी बिल्कुल असफल रहे। छात्रावासों एवं परिसर में मारपीट की घटनाओं को भी त्यागी की निर्णय नहीं लेने की प्रवृत्ति से बल मिला। छात्रों एवं अध्यापकों के अनेक लिखित ज्ञापनों एवं प्रदर्शनों के बाद भी स्थिति को टालने का प्रयास किया गया जिससे स्थिति बदतर होती चली गई। आज भी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण के स्थान पर गुण्डागर्दी और आतंक का वातावरण व्याप्त है। जोधपुर विश्वविद्यालय में श्री कपूर को सत्र के अन्त में उपकुलपति पद का भार सौंपा गया जिन्होंने गत अनेक सत्रों से बिगड़ती आ रही परीक्षाओं की सारणी को ठीक करने की उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। समय पर परीक्षाएं हों, इस हेतु वे स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ गये। अध्यापकों का पूरा-पूरा सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ और अन्ततः एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्हें प्राप्त हुई। उदयपुर विश्वविद्यालय में अभी स्थायी उपकुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाई है। श्री तलवार वहां पर अस्थाई कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं।

विद्यार्थी परिषद की भूमिका

राजस्थान में वैचारिक आधार पर रचनात्मक कार्यक्रमों, नियोजित चिन्तन, विभिन्न समस्याओं पर व्यापक बहस एवं छात्र हितैषी दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करने वाला छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही रहा। जातीयता, क्षेत्रीयता एवं राजनीति की विसंगतियों से आम विद्यार्थी को अलग रखने तथा उन्हें रचनात्मक दिशा देने का कार्य विद्यार्थी परिषद ने किया और वर्ष भर छात्र हितों के लिए संघर्षरत जुझारू छात्र संगठन होने का गौरव विद्यार्थी परिषद ने अर्जित किया। अन्य छात्र-युवा संगठनों में जहां छात्र-युवा—संघर्ष-वाहिनी एवं जनता युवा मोर्चा ने विश्वविद्यालयों एवं छात्रों की राजनीति से अपने को अलग रखने के फैसले को कार्य रूप दिया वहीं युवा जनता, एस० एफ० आई०, ए० आई० एस० एफ०, एन० एस० यू० आई०, युवा कांग्रेस आदि छात्र संगठन जातीयता एवं क्षेत्रीयता के दल-दल में इतने लिप्त एवं फंसे हुए रहे कि उनके लिए अपनी अलग से पहचान बनाना तक भी मुश्किल हो गया।

छात्रसंघ को भंग करने का प्रयास

राजस्थान के कुल तीन [illegible] विश्वविद्यालयों में हुए छात्रसंघ के चुनावों में विद्यार्थी परिषद की सम्पूर्ण विजय ने एक बार फिर विद्यार्थी परिषद को छात्रों का सबसे सशक्त एवं सुसंगठित प्रतिनिधि संगठन प्रमाणित कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी श्री सुशील [illegible] एवं श्री निर्मल नाहटा छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के दोनों पदों क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (महासचिव एवं मंत्री अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं) पद पर विजयी हुए। किन्तु हार से बौखलाए हुए मुट्ठीभर विरोधी छात्रों ने तुरन्त छात्र कल्याण अधिष्ठाता का लगातार ३६ घंटे घेराव कर, परिणाम अधिकारियों को तोड़कर, कार्यालय में तोड़फोड़ तथा दबाव से छात्रसंघ को रद्द करने का प्रयास प्रारम्भ किया। इसके बाद उपकुलपति के घेराव और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति पर प्रहार का मनमाना दौर प्रारम्भ हुआ। विश्वविद्यालय में अराजकता, एवं हिंसा का वातावरण बनाया गया। राजनैतिक हस्तक्षेप एवं दबाव ने पुलिस को पंगु बना दिया। रही-सही कसर तत्कालीन उपकुलपति डा० ओमप्रकाश की प्रशासनिक अक्षमता एवं एकपक्षीय दृष्टिकोण ने पूरी कर दी। उपकुलपति को विश्वविद्यालय छात्रसंघ को वर्ष भर के लिये स्थगित करने का एक सुनहरा अवसर हाथ लगा जिसका उन्होंने पूरा लाभ उठाया और छात्रों के लोकतान्त्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया। इसके बाद से ही राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ का विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका के माध्यम से चल रहा है। उदयपुर विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष चुनाव के दोनों पदों—अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी श्री चन्दसिंह कोठारी एवं श्री दरियावसिंह विजयी हुए। तोड़फोड़, मतपत्रों को फाड़ने एवं उपकुलपति के घेराव की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने का प्रयास यहां भी हारे हुए छात्र नेताओं ने कुछ जातीय राजनैतिक नेताओं की शह पर किया। किन्तु स्थानीय जिलाधीश की सूझ-बूझ एवं छात्रों के सामूहिक दबाव से छात्रसंघ को भंग करवाने का षड्यंत्र पूर्ण नहीं हो सका। जोधपुर विश्वविद्यालय में तो छात्रसंघ के चुनाव ही नहीं

With Best Compliments From

DUCHJ RAMAN STEEL CORPORATION

BOMBAY

With Best Compliments From

ASHISH UDYOG

BOMBAY

कराये गये जिसको लेकर छात्रों में काफी उत्तेजना रही और इसी विषय को लेकर दो कुलपतियों को छात्रों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदेश के विभिन्न कालेजों के छात्रसंघ के चुनावों में २१३ स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों की विजय ने आम छात्रों में विद्यार्थी परिषद की गहरी पैठ को साबित कर दिया है।

सीनेट और सिण्डीकेट के चुनाव

राजस्थान के सभी तीन विश्वविद्यालयों के प्रशासन में छात्रों के सहभाग का प्रावधान है किन्तु केवल राजस्थान विश्वविद्यालय में ही इस वर्ष सीनेट एवं सिण्डीकेट के लिए छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव हो पाये। उदयपुर एवं जोधपुर विश्वविद्यालय में कोई न कोई बहाना बनाकर अब तक चुनाव नहीं कराये गये है। राजस्थान विश्वविद्यालय सीनेट में विद्यार्थी परिषद ने १० में से ६ स्थान पर विजय प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। युवा जनता एवं सी० पी० एम० से सम्बन्धित आर०डी० एस० एफ० ने एक एक स्थान पर सफलता पाई। शेष दो स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। सिण्डीकेट के लिये हुए दो स्थानों के चुनाव में विद्यार्थी परिषद के श्री भरतलाल शर्मा विजयी हुए। अन्य एक स्थान निर्दलीय श्री मधुकर श्याम को प्राप्त हुआ। युवा जनता एवं आर० डी० एस० एफ० को यहां पूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा। सीनेट के चुनावों के परिणामों की शृंखला में ही राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रमुख छात्र नेता पर एक जाति विशेष के तथाकथित छात्रों द्वारा हुए हमले की घटना ने एक बड़ा रूप ले लिया और यह हमला विश्वविद्यालय को गुण्डागर्दी, अशान्ति एवं हिंसा से मुक्त करने के आन्दोलन के रूप में परिणत हुआ। मुख्यमंत्री, गृहमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से भी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बनाने में सहयोग की अपील की गई। इस सिलसिले में लगभग २०० छात्रों ने गिरफ्तारियां दीं। इससे छात्रों में पर्याप्त चेतना जागृत हुई।

छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन

छात्रों के कार्यक्रमों एवं प्रयत्नों को एक समन्वित रूप देने के उद्देश्य से गंगानगर एवं सीकर में प्रदेश के छात्रसंघों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मेलन हुए। गंगानगर का सम्मेलन उपस्थिति की कमी के कारण पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुआ किन्तु सीकर का सम्मेलन छात्रों की कुछ समान मांगों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने में सफल सिद्ध हुआ। शैक्षणिक परिवर्तन की आवश्यकता पर यहां विचार-विमर्श गहराई से हुआ और सम्मेलन ने शिक्षा में परिवर्तन के कुछ बिन्दु तय किये जिसमें शिक्षा के ग्रामोन्मुखी होने की आवश्यकता पर बल देते हुए व्यवसाय से सीधे जोड़ने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। शैक्षणिक समाज में व्याप्त जातिगत गुटबंदी एवं राजनीतिक प्रभाव से अलग रहते हुए शैक्षणिक समस्याओं के समाधान की विद्यार्थी की भूमिका को स्वीकार किया गया। माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने, पब्लिक स्कूलों की शिक्षण सुविधाओं को समाप्त कर समानता के पोषक आदर्श विद्यालयों की स्थापना की मांग को दोहराया गया। प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा छात्रसंघों के चुनाव कराये जाने एवं छात्रसंघों के संविधान में एकरूपता लाने की मांग की गई। सम्मेलन में कोई समान कार्यक्रम बनाकर उसे क्रियान्वित करने की योजना को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका।

रचनात्मक कार्यक्रमों के सिलसिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी एवं जनता युवा मोर्चा के अतिरिक्त अन्य संगठनों की कोई सक्रियता नहीं दिखाई देती। विद्यार्थी परिषद द्वारा "ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान" प्रकल्प का ४ से ७ जून तक जयपुर में इस प्रोजेक्ट में लगे देश भर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जनता युवा मोर्चा द्वारा राजस्थान सरकार के अंत्योदय कार्यक्रम में सहयोग एवं छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी द्वारा ग्राम विकास हेतु संकल्प की घोषणाएं की गई हैं।

शैक्षणिक परिवर्तन हेतु छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षा शास्त्रियों में जागृति एवं परिवर्तन हेतु संकल्प करने का एक बड़ा प्रयास विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया है। सभी छात्र-युवा संगठनों को इस हेतु एक मंच पर लाकर एक सशक्त वैचारिक आन्दोलन शुरू करने का फैसला राजस्थान के शिक्षा समुदाय के लिए आगामी सत्र में हलचल का प्रमुख विषय रहेगा और आने वाला वर्ष छात्रों के रचनात्मक कार्यक्रमों एवं मूल्यों पर आधारित वैचारिक आन्दोलनों का वर्ष होगा। □

शुभ कामनाओं सहित

गोपाल दास रामनाथ

६५, श्रद्धानन्द मार्ग, दिल्ली-११०००६

फोन { निवास : २२४८२२
कार्यालय : २६४१२८

दूरलेख : वि पी

संबंधित फर्म

गोपाल दास रमेश कुमार

चौक बिजली, हाल बाजार,
अमृतसर

दिल्ली विश्वविद्यालय : इमरजेन्सी जारी है

□ रजत शर्मा

सन १९७४ में डा० सरूपसिंह के इस्तीफे के बाद डा० रामचरण मेहरोत्रा को दिल्ली लाया गया। एक विज्ञान के प्रोफेसर को दिल्ली विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किये जाने पर खासा आश्चर्य व्यक्त किया गया था — एक तो दिल्ली का विद्यार्थी जे० पी० आंदोलन की चरम सीमाओं में देश भर को नेतृत्व दे रहा था और इससे पहले छात्र नेताओं के निष्कासन आदेश की वापसी को लेकर जोरदार आंदोलन चला था। ये दोनों बातें सरकार की बौखला-हट का कारण बनी हुई थीं। यूं तो डा० मेहरोत्रा जयपुर में भी अपने कारनामों के लिये जाने जाते रहे और लाख कोशिशों के बाद भी स्वयं को एक अच्छा प्रशासक सिद्ध नहीं कर पाए थे। यहां भी धीरे-धीरे यह साफ होता गया कि हमेशा की तरह एक बार फिर एक कठ-पुतला वाइसचांसलर राजधानी में टिका लिया गया है जिसकी डोर सरकारी हाथों में थी। बस तभी से सिर्फ डोर घुमाने वाले हाथ बद-लते रहे हैं, कठपुतले ज्यों के त्यों हैं।

पहले साल में ही डा० मेहरोत्रा समझ गए कि यहां आसानी से उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ और छात्र संघ के चुनावों में साफ तौर पर वही लोग भारी बहुमत से विजयी हुए थे जिनसे सर-कार बुरी तरह नाराज थी। जनमत विश्व-विद्यालय समाज के नेतृत्व के साथ था—एक स्वर से 'संपूर्ण क्रांति-जिंदाबाद' की गूंज उठ रही थी। छात्रसंघ ने 'पढ़ाई के साथ लड़ाई' का नारा दिया और ३१ अक्टूबर को विश्वविद्या-लय कैंपस में लोकनायक ने घोषणा कर दी, "आप में से जिन नौजवानों ने इन चलती हुई लहरों का मतलब नहीं समझा उन्हें ये लहरें बहाकर ले जाएंगी और फिर यह बेमतलब रह जाएगा कि किसने कौन सी परीक्षा पास की है और किसके पास कौन सी डिग्री है।"

डा० मेहरोत्रा अभी भी चुप्पी साधे बैठे थे पर तभी इशारा हुआ आकाओं का—राज्य सभा के कांग्रेसी सदस्य और तत्कालीन सह-उपकुलपति बी० पी० दत्त और शिक्षामंत्री नूरुल हसन का। डा० मेहरोत्रा के गिरोह की सलाह पर कैम्पस में खुफिया पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई। छात्रसंघ भवन पर कड़ी नजर रखी जाने लगी और विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर दबाव डाला जाने लगा कि छात्रों और अध्यापकों की गतिविधियों की नियमित सूचनाएं सरकार तक पहुंचाने में सहयोग दें। ४ नवम्बर को दिल्ली बंद का आह्वान किया गया था। एक रात पहले प्रमुख छात्र नेताओं के घरों पर पुलिस ने छापे मारकर उन्हें पकड़ने की असफल कोशिश की। लाख सिर मारने पर भी उपकुलपति आंदोलन के दबाव के कारण केवल छटपटा कर रह गए।

जब जब विश्वविद्यालय बंद का आह्वान किया जाता, कुलपति की ओर से पहले ही विश्वविद्यालय बंद कर दिया जाता। पूरी सर-कारी मदद के बावजूद डा० मेहरोत्रा छात्रों से टकरा-टकराकर पस्त होते रहे लेकिन यह आंख मिचौली ज्यादा दिन चल नहीं पाई।

जून ७५ में जब विश्वविद्यालय की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था आपातकाल के काले पंजों ने इसे गिरफ्त में ले लिया। २६ जून की सुबह तत्कालीन छात्रसंघ अध्यक्ष अरुण जेटली के नेतृत्व में इस जकड़ के खिलाफ जो आवाज गूंजी उसे सीखचों के पीछे अम्बाला जेल की कोठरी में धकेल दिया गया। डा० मेहरोत्रा का गिरोह अब पूरी फोर्स में था। अब उपकुलपति विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक पुलिस चौकी चला रहे थे। उनके ऑफिस में सरकार के लिए खतरनाक छात्रों और प्राध्यापकों के नाम-पतों की सूचियां धड़ाधड़ तैयार हो रही थीं। और खामोश सन्नाटों में तानाशाही का अट्टहास गूंज रहा था। १६ जुलाई को भयानक वातावरण में विश्वविद्यालय खुला। कितने ही खुफिया पुलिस के जवानों को प्रवेश देकर कक्षाओं में बिठा दिया गया। हर कालिज के बाहर रायफल लिये पुलिस तैनात कर आतंक का नाटक खेलने की तैयारियां पूरी कर ली गईं। लेकिन लोकतन्त्र के प्रहरी नौजवान कहीं न कहीं पर्चे बांट कर डा० साहब के मालिकों को नाराज करते रहे, घेरा कसता रहा, पहरा बढ़ता रहा। २६ जुलाई को विश्वविद्यालय बंद की आवाज उठी पर

उपकुलपति आर०सी० मेहरोत्रा

एक रात पहले सौ से अधिक प्राध्यापकों के दर-वाजे पर आधी रात को दस्तक हुई और वे कुछ समझें तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ठूंस दिया गया। इतने प्राध्यापकों की गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने चुन-चुनकर बदला लिया था। खुफिया पुलिस के रिकार्ड में केवल चालीस ऐसे प्राध्यापकों के नाम दर्ज थे। बाद में उपकुलपति की मदद से यह संख्या दो सौ तीस तक पहुंच गई। सिर्फ नाम-पते पहुंचाने तक ही नहीं बल्कि एक प्राध्यापक श्री मुरली मनोहरप्रसाद सिंह ने आरोप लगाया है कि डा० मेहरोत्रा के एक सहयोगी अधिकारी जो पुलिस से अपने संबंधों के लिए कुख्यात हैं तहकीकात करने के लिये सी० आई० डी० के लोगों के साथ तिहाड़ भी पहुंचे थे।

उपकुलपति के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधान-मंत्री और उनके पुत्र के ४-२० सूत्री कार्यक्रम के प्रचार की व्यापक योजनाएं तैयार की गईं। उपकुलपति डा० यू० एन० सिंह, डीन ऑफ कालिज श्री महेन्द्र सिंह और डीन स्टूडेंट्स वेल-फेयर डा० कुक्का को जेल में बंद छात्रों व प्राध्यापकों के विरुद्ध जनमत तैयार करने का काम सौंपा गया। जल्दी ही विश्वविद्यालय के

फैकल्टी क्लब को नसबन्दी कैंप में बदल दिया गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमान मेहरोत्रा ने ही की। और फिर एक दिन विश्वविद्यालय समाज का सिर शर्म से धरती में गड़ गया जब दिल्ली में नसबंदी की कुख्यात खलनायिका रुखसाना सुलताना के इशारों पर दुजाना हाउस में डा० आर०सी० मेहरोत्रा ने नसबंदी कैंप का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के एक प्रमुख कालेज की छात्राओं को वहां जाने के लिये विवश किया गया और फिर जो कुछ हुआ उसे सिर्फ समझा जा सकता है बयान नहीं किया जा सकता।

उपकुलपति के साथी अपने नेता को खुलकर प्रोत्साहन दे रहे थे। डीन ऑफ कालिज ने छात्राओं के कालिजों की प्रिंसिपलों की एक बैठक तत्कालीन युथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती अम्बिका सोनी के निवास पर आयोजित की। विषय था युथ कांग्रेस में छात्राओं को कैसे शामिल किया जाए। बीस सूत्री और चार सूत्री कार्यक्रमों का यशमान करने के लिये लगभग हर कालिज में समारोह आयोजित किये गए। श्रीमती गांधी के निकटस्थ यशपाल कपूर द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केन्द्रीय प्रचार विभाग की ओर से 'प्रधानमंत्री के असाधारण दस वर्षों' की स्तुति में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सह-उपकुलपति महोदय ने की।

देश में लोकतंत्र की सरेआम हत्या ने डा० आर०सी० मेहरोत्रा को प्रेरणा दी और जब चुने हुए छात्रसंघ के पदाधिकारी जेल में कैद थे एक विशेष आदेश जारी कर विश्वविद्यालय और कालिज छात्र संघ के चुनावों पर छुरी फेर दी। संजय जी पर अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने के लिये युथ कांग्रेस के नेताओं को छात्र संघों के स्थान पर बनी समितियों में थोप दिया गया। कालिजों के प्रिंसिपलों को सख्त हिदायत दी कि बिना विश्वविद्यालय से पास कराए किसी को मनोनीत न किया जाए। ऐसे सभी नामों की पुलिस की सहायता से जांच कराई जाती थी। समितियों के काले कारनामों की एक विस्तृत रिपोर्ट अलग से तैयार की जा सकती है जो विश्वविद्यालय के माथे पर कलंक के रूप में हमेशा याद की जाएगी।

उपकुलपति डा० मेहरोत्रा ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खुले आम नीलाम कर दिया। जेल में बंद विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि पीड़ा से कराह रहे थे और विश्वविद्यालय में जश्न जारी थे। जेल में बंद विद्यार्थियों ने जब पत्र लिखकर मांग की कि उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जाए तो डा० मेहरोत्रा ने सरकार के प्रति चापलूसी जतलाते हुए कोई उत्तर तक देने से इंकार कर दिया। जेल से पत्र आकर फाइलों में कैद होते रहे। आजादी के साथ-साथ छात्र नेताओं का शैक्षिक वर्ष भी छीन लिया गया।

आपातकाल में किए गए जुल्मों की कथा का एक बहुत लम्बा हिस्सा उन नियुक्तियों का है जो अपने आकाओं को खुश करने के लिये उपकुलपति ने की। तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रो० नुरूल हसन को इतिहास विभाग में एक नई विशेष पोस्ट पर नियुक्त किया गया। कांग्रेस

रजत शर्मा

समर्थित नेशनल फोरम ऑफ टीचर्स के नेताओं और सरकार के मंत्रियों के भाई-भतीजों की बढ़चढ़कर नियुक्तियां की गईं। प्रो० यू० एन० सिंह को प्रो-वाइस चांसलर, डा० मोंगा को प्रोक्टर, प्रसिद्ध कम्युनिस्ट डा० शर्मा को इतिहास विभागाध्यक्ष और अनेकों लोगों को नियमों को तोड़कर दुबारा नियुक्त कर दिया गया। वांछित योग्यता न होने पर भी जिन लोगों को कांग्रेसी साया सिर पर होने के कारण नियुक्त किया गया उनकी सूची बहुत लंबी है। इस सूची में खासतौर पर डीन ऑफ कालिज के भाई एन. एस. प्रधान को किरोड़ीमल कालिज में प्रिंसिपल बना दिया गया तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षद

विश्वविद्यालय समाज का सिर धरती में शर्म से गड़ गया जब दिल्ली में नसबंदी की कुख्यात खलनायिका रुखसाना सुलताना के इशारों पर दुजाना हाउस में उपकुलपति डा०आर०सी०मेहरोत्रा ने नसबंदी कैम्प का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के एक प्रमुख कालिज की छात्राओं को वहां जाने के लिए विवश किया गया और फिर जो कुछ हुआ उसका बयान नहीं किया जा सकता है।

चौधरी हीरा सिंह की पुत्री श्रीमती दमयंती शास्त्री, युथ कांग्रेस के खास-मित्र के दुलारे दीपक मल्होत्रा, एक भूतपूर्व कांग्रेसी संसद सदस्य के पुत्र सुधाकर पांडेय समेत अनेकों को प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सब वांछित योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे।

आपातकाल में डा० मेहरोत्रा के शासनकाल में ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जो तानाशाही के नमूने होने के बावजूद रोचक हैं। श्रीराम कालिज ऑफ कामर्स के प्रिंसिपल को सिर्फ इसलिये मीसा की धमकी दी गई कि उन्होंने दो छात्रों को अयोग्य होने के कारण प्रवेश देने से इंकार कर दिया। उन्हें लिखे एक पत्र में ये गैर कानूनी एडमिशन सार्वजनिक हित में करने को कहा गया था।

जाकिर हुसैन कालिज के पांच छात्रों को सिर्फ इसलिए निष्कासित कर जेल भेज दिया गया कि उन्होंने एक समारोह में दहेज प्रथा के समर्थन में हाथ उठा दिये थे। ऐसे ही न जाने कितने जुल्मों की गाथा फाइलों में दबी पड़ी है।

नई सरकार आए एक वर्ष हो चुका है। विश्वविद्यालय में अभी भी एमरजेंसी जारी है। पुराने ढर्रे पर नियुक्तियों में धांधली, छात्र-गतिविधियों में दखलंदाजी, प्राध्यापकों को धमकियां अभी भी जारी हैं। डा० मेहरोत्रा जो एक दब्बू किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं अपने खिलाफ कार्रवाही न होने से प्रोत्साहित हुए हैं। अपने खिलाफ जांच की मांग करने वालों से

शेष पृष्ठ २१ पर

राजस्थान विश्वविद्यालय : हमला करने वाले कौन हैं ?

केन्द्र और राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद छात्रों में एक बड़े परिवर्तन की आशा जगी थी पर उनकी आशाओं पर पानी फिर गया प्रतीत होता है। निर्णय लेने में प्रशासन की अक्षमता और शासन की उदासीनता के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर) का वातावरण निरन्तर बिगड़ता जा रहा है।

जुलाई '७७ में विश्वविद्यालय खुलने पर आपातकाल के भ्रष्ट और दोषी उपकुलपति तथा अन्य अधिकारियों को हटाने की छात्रों की सर्वप्रथम मांग उभरकर सामने आयी। कामर्स कालेज के प्रिंसिपल को विवश होकर त्यागपत्र देना पड़ा। आपातकाल के दोषी उपकुलपति **गोविन्द चन्द्र पाण्डेय** को त्यागपत्र देने के लिए छात्रों ने अपने आन्दोलन द्वारा मजबूर कर दिया। दूसरी घटना यह घटी कि राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर कुछ गुण्डों ने आक्रमण किया और इन्हीं गुण्डों ने बेमतलब हड़ताल का आवाहन किया जिसके असफल होने पर वे हिंसा पर उतारू हो गए। इससे विरोध प्रकट करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शिष्ट मंडल जब उपकुलपति से मिलने गया तब उन्हीं गुण्डे छात्रों ने उपकुलपति निवास से निकल कर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला किया और उपकुलपति महोदय अपने कमरे में बन्द होकर यह सारा घटनाचक्र देखते रहे। आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्होंने शिष्ट मंडल से मिलने से इनकार कर दिया। आक्रमणकारियों पर कार्रवाई करना तो दूर रहा, उपकुलपति **ओमप्रकाश माथुर** ने उल्टे विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा न लगने देने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। इससे अराजक तत्वों का हौसला और अधिक बुलन्द हो गया।

उल्लेखनीय है कि ओमप्रकाश माथुर के उपकुलपति काल में विश्वविद्यालय में यू० एन० एस० आई०, एस० एफ० आई०, आर० डी० एस० एफ०, यूथ कांग्रेस आदि राजनैतिक संगठनों की बैठकें, सम्मेलन तथा अन्य कार्यक्रम धड़ल्ले से होते रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को परिसर में सभा करने की खुली छूट उपकुलपति ने दे रखी है।

आर० एस० एस० की शाखा के सामने में ओमप्रकाश माथुर के खिलाफ राजस्थान की विधान सभा में भारी हंगामा हुआ। **श्री रामकिशनदास मुन्दड़ा** सहित अनेक विधायकों ने उपकुलपति को दण्डित करने की मांग की। गृहमन्त्री **श्री० केदार** ने दोषी छात्रों और उपकुलपति के विरुद्ध कार्रवाई करने का विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन भी दिया पर पूरी बात जहाँ की तहाँ ठप्प पड़ी है। आगे चलकर राजस्थान विश्वविद्यालय में इसके अनेक दुष्परिणाम सामने आये।

इसके बाद १५ अक्टूबर '७७ को विश्वविद्यालय छात्रसंघ का चुनाव था। अराजक तत्वों के हौसले पहले से बुलन्द थे ही। अतः चुनाव प्रचार में भी खुलकर दादागीरी और गुंडागर्दी हुई। जब विधि महाविद्यालय के अतिरिक्त सभी कालेजों की मतगणना हो चुकी थी और विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के लिए क्रमशः उम्मीदवार **सुनील भार्गव** और **निर्मल बाहेटा** काफी मतों से आगे थे तब चुनाव हार रहे उम्मीदवार **अजय सिंह** के समर्थकों ने विधि महाविद्यालय में मतपत्र फाड़ने शुरू कर दिये और लाठी, चाकू, रिवाल्वर से लैस तथाकथित छात्र उपद्रवकारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में गुंडागर्दी का नग्न तांडव शुरू कर दिया। इन सबके बावजूद जब चुनाव परिणाम घोषित होने ही वाले थे तब चुनाव अधिकारी का घेराव किया गया तथा उन्हें बाध्य कर चुनाव रद्द करने की मांग की गई। मजबूर चुनाव अधिकारी ने चुनाव रद्द कर दिये। अब तक उपकुलपति ने पुलिस को कार्रवाई करने हेतु आदेश नहीं दिये।

जिस कालेज के मतपत्र फाड़ दिए जाने का बहाना लेकर चुनाव रद्द किए गए, उसी कालेज के चुनाव परिणाम तो बाद में घोषित कर दिए गए पर विश्वविद्यालय छात्रसंघ का चुनाव परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया है।

इसी चुनाव का एक रोचक तथ्य यह है कि तत्कालीन उपकुलपति ने विधि महाविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव परिणाम के सम्बन्ध में अपने एक ही निर्णय को चार बार बदला। हुआ यह कि **राम प्रताप चौधरा** इस महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर विजयी हुए थे। उनके साथियों के बूथ के पहुंचने पर चुनाव परिणाम घोषित किया गया। लेकिन उनके विरोधी गुट के पहुंचने पर उसी परिणाम को उपकुलपति ने रद्द कर दिया। यह क्रम चौबीस घंटे में चार बार चला। पांचवीं बार चुनाव परिणाम घोषित करके उपकुलपति महोदय ने छुट्टी ले ली और शहर छोड़कर चले गये।

इस सब का चरम बिन्दु तब आया जब विश्वविद्यालय सीनेट के चुनाव परिणाम घोषित किये गए। विद्यार्थी परिषद के **अमिताभ हीरावत** को विजय मिली। इस समय विश्वविद्यालय छात्रसंघ के विजयी (?) अध्यक्ष श्री सुनील भार्गव पर हमला किया गया। नये उपकुलपति **वेद पाल त्यागी** का आगमन हो चुका था। विद्यार्थी परिषद ने उनका घेराव किया तथा दोषी छात्रों के तुरन्त निलम्बन की मांग की। एक छात्र के निलम्बन का आदेश देकर पूरी कारवाई सात दिन में करने का नये उपकुलपति ने विश्वास दिलाया पर कारवाई नहीं हुई। श्री सुनील भार्गव पर हमले के विरोध में एक दिन पूरी हड़ताल रही जिसका नेतृत्व विद्यार्थी परिषद ने किया था। हमलावर छात्रों को तुरन्त गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों का एक जुलूस राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहा था तो पुलिस ने उसे रोका। उस समय विद्यार्थी परिषद के २०० कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। हमले की जांच के लिए विश्वविद्यालय द्वारा **डा० इकबाल नारायण** की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उसकी न कोई रिपोर्ट आयी और न उसके द्वारा कोई कारवाई ही की गई। इसके बाद परीक्षाओं का प्रश्न सामने आया। परीक्षा की घोषित तिथियों को छात्रों की मांग पर आगे बढ़ा दिया गया। विधि-संकाय की परीक्षा २६ अप्रैल से बढ़ाकर १० मई कर दी गयी। कुछ छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को पुनः १० जून तक टाला गया जो अब एक अगस्त कर दी गई है। अब देखें इसके आगे क्या होता है।

□ **रामपाल सिंह**

पटना विश्वविद्यालय : तालाबन्दी और परीक्षा

परीक्षाओं को चौथी बार स्थगित किये जाने पर पटना विश्वविद्यालय के छात्र ग्रीष्मावकाश के बाद विश्वविद्यालय खुलते ही भड़क उठे। विश्वविद्यालय छात्रसंघ के प्रतिनिधि-मंडल ने ७ जुलाई को कार्यकारी उपकुलपति गणेश प्रसाद सिंह से मिलकर उन्हें अल्टीमेटम दिया कि यदि २४ घंटे के अन्दर विश्वविद्यालय की स्थगित परीक्षाओं को पुनः संचालित करने की घोषणा नहीं की गई तो छात्रसंघ सीधी कारवाई करेगा और विश्वविद्यालय के पठन पाठन को ठप्प कर देगा। छात्रसंघ ने शिक्षक संघ को भी चेतावनी दी कि वह अपना रवैया बदले क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार उन्हें शिक्षण और परीक्षाओं में निरीक्षण दोनों ही कार्य करने हैं।

अगले दिन की रात छात्रसंघ के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों तथा कार्यकारी उपकुलपति के बीच विचार-विमर्श हुआ किन्तु कोई निर्णय नहीं हो सका। छात्र इस बात पर दृढ़ थे कि परीक्षा भवन में मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा उनकी तलाशी न ली जाये जबकि शिक्षक जांच के लिए पुलिस एवं मजिस्ट्रेट तैनात करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच बैठक समाप्त हुई और छात्रों ने विश्वविद्यालय के कार्यालयों पर ताला लगा दिया। छात्रसंघ के अध्यक्ष अश्विनी कुमार चौबे का वक्तव्य था कि विश्वविद्यालय कार्यालय को तब तक खुलने नहीं दिया जाएगा जब तक परीक्षाओं के प्रारम्भ होने की तिथि निश्चित नहीं हो जाती। तालाबन्दी से ९ जुलाई की कक्षायें भी प्रभावित रहीं। बी० एन० कालेज में पढ़ाई पूरी तरह बन्द रही। अन्य कालेजों में भी कुछ ही कक्षायें लगीं।

विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव के० के० तिवारी ने बयान जारी किया कि शिक्षकों ने परीक्षाओं में निरीक्षण कार्य न करने का निर्णय किया है क्योंकि परीक्षा में कदाचार होता है तथा शिक्षकों पर प्रहार होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बिहार प्रदेश मन्त्री सुशील कुमार मोदी तथा संगठन मन्त्री चन्द्रेश्वर प्रसाद ने वक्तव्य देकर परीक्षाओं को चौथी बार स्थगित किये जाने पर रोष प्रकट किया और राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अविलम्ब शैक्षणिक अराजकता पर नियन्त्रण करे अन्यथा स्थिति विस्फोटक हो जायगी।

इसके बाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के एक सात सदस्यीय शिष्ट मंडल ने राज्यपाल जगन्नाथ कौशल से मिलकर बातचीत की। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वे परीक्षा कराने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक सप्ताह के अन्दर मुख्यमन्त्री कर्पूरी ठाकुर, उच्च शिक्षा मन्त्री ठाकुर प्रसाद सिंह तथा छुट्टी पर गये उपकुलपति अनुज कुमार धान से विचार-विमर्श करेंगे।

१० जुलाई को श्री अनुज कुमार धान और छात्रसंघ के बीच बातचीत से समस्या सुलझ गयी। उपकुलपति ने १३ जुलाई से पहले बी० एस० सी० तथा बी० ए० का परीक्षाफल घोषित करने की घोषणा की और कहा कि इन्टर तथा एम० एस० सी० की परीक्षाओं के तिथियों की घोषणा दो दिन के अन्दर कर दी जायगी। शिक्षक संघ ने परीक्षाओं में निरीक्षण कार्य करना स्वीकार लिया। शिक्षकों के सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करना उपकुलपति ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद छात्रसंघ ने विश्वविद्यालय के कार्यालयों पर से अपना ताला हटा लिया और विधिवत सारा कार्य प्रारम्भ हो गया है। अब तक यह प्रकाश में नहीं आया है कि विश्वविद्यालय के ग्रीष्मावकाश के बाद खुलते ही आखिर परीक्षायें स्थगित क्यों की गई जिसके कारण इतना हंगामा हुआ?

• विनय कृष्ण

बम्बई विश्वविद्यालय : भाषा की राजनीति

बम्बई विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाये रखने और सभी भाषाओं के छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी साहित्य का पर्चा लेने को मजबूर करने के लिए कुछ अंग्रेजीपरस्त अध्यापकों तथा अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं ने इन दिनों एक आन्दोलन खड़ा किया है, कुछ स्वार्थी लोग आजादी के तीस साल बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व और यथास्थिति बनाए रखने के लिए वही पुरानी दलीलें दे रहे हैं कि अंग्रेजी का स्तर गिर जाने से देश पिछड़ जाएगा। निश्चय ही इस आंदोलन के पीछे सुविधाभोगी अफसरशाह और कतिपय बुद्धि-विलासी व्यक्ति हैं।

इस कुत्सित आन्दोलन का इस समय बहाना यह है कि इस शिक्षा सत्र में बम्बई विश्वविद्यालय ने बी०ए० के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में भाषा के दो अनिवार्य पर्चों के अन्तर्गत अंग्रेजी का दूसरा पर्चा हटवा दिया है। इसका अर्थ यह है कि बी०ए० के प्रथम वर्ष में अंग्रेजी का एक पर्चा तो अनिवार्य रहेगा, लेकिन भाषा के दूसरे अनिवार्य पर्चे के अन्तर्गत छात्र को अंग्रेजी के स्थान पर कोई अन्य यूरोपीय या भारतीय भाषा पढ़नी होगी। अब तक भाषा के इस दूसरे पर्चे के अन्तर्गत भी छात्र अंग्रेजी ले सकते थे। इसके अलावा तीन ऐच्छिक विषयों के अन्तर्गत भी छात्र अंग्रेजी का एक पर्चा और ले सकते हैं। पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत बी०ए० प्रथम वर्ष का छात्र कुल छह पर्चों में तीन पर्चे अंग्रेजी के लेकर भारतीय भाषाओं की पूरी उपेक्षा कर सकता था। लेकिन नयी व्यवस्था में छात्र तीन की जगह दो पर्चे अंग्रेजी के ले सकेंगे और तीसरा पर्चा किसी यूरोपीय या भारतीय भाषा का अनिवार्य होगा। इस प्रकार अंग्रेजी का केवल एक पर्चा हटा देने पर अंग्रेजी परस्त बौखला उठे हैं और अंग्रेजी अध्यापकों ने आंदोलन की धमकी देकर अपनी मांगें बढ़ा-चढ़ा कर रखने का यत्न किया है।

वर्तमान व्यवस्था में बी०ए० के त्रिभाषायी पाठ्यक्रम में केवल प्रथम वर्ष के छात्रों को भाषा की शिक्षा लेनी होती है तथा शेष दो वर्ष में भाषा का कोई पर्चा नहीं होता। बी०एस०सी० और बी०काम० के छात्रों को भाषा का पर्चा लेना ही नहीं होगा। अंग्रेजी के अध्यापक अब यह चाहते हैं कि बी०ए० के तीनों वर्ष में तथा बी०एस०सी० और बी०काम० के छात्रों के लिए भी अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य की जाय। अंग्रेजी अध्यापक यह भी चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहे, हालांकि बम्बई विश्वविद्यालय कुछ वर्ष पूर्व ही यह निश्चय कर चुका था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के अलावा हिन्दी, मराठी और गुजराती भाषाएं भी हों। लेकिन अंग्रेजी परस्तों ने भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में लगातार रोड़े अटकाये हैं।

✲

उग्रपंथियों का शिकार मिथिला विश्वविद्यालय

दर्शन, ज्ञान-विज्ञान एवं प्राचीनता के संगम स्थल मिथिला के प्राचीन नगर दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए की गई ताकि मिथिला भविष्य में भी अपने नाम की सार्थकता को बनाये रखे। लेकिन आज बिहार मंत्रि मंडल के नियोजित जातिवादी दुष्चक्रों के कारण यह शहर जातिवाद की आग में जल रहा है।

बिहार सरकार की अदूरदर्शिता के कारण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस द्वारा अकारण १६ बार लाठीचार्ज, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र के छात्रों को बिल अधिकारियों द्वारा पीटा जाना, सी० एम० कालेज, मारवाड़ी कालेज एवं कुंअरसिंह कालेज में तत्कालीन एस० डी० ओ० भगवती शरण मिश्र द्वारा परीक्षा दे रहे छात्रों को घायल करना आदि उल्लेखनीय है। उपकुलपति द्वारा प्रधानाचार्यों, प्राध्यापकों, छात्रों, छात्र-प्रतिनिधियों, पत्रकारों आदि को आये दिन गाली दिया जाना आम बात हो गई है। इधर आरक्षण के पीछे चल रहे पूरे बिहार प्रदेश में जातिवादी कुचक्रों के कारण नगर के शिक्षक, छात्र, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, जनता पार्टी के नेता आदि सभी जाति के आधार पर अलग-अलग कई वर्गों में बंट गये हैं।

आज कुछ ज्वलन्त प्रश्न बिहार की सरकार से उत्तर मांग रहे हैं किन गुंडों ने निर्दोष छात्रों को मेहता छात्रावास से बाहर खींच-खींच कर पीटा था? मशरक बाजार एवं उसके एकमात्र छात्रावास पर दशकों से साम्यवादियों की आंखें टिकी हुई हैं, क्या यह घटना उसी का दुष्परिणाम नहीं है? विगत २७ अप्रैल को साइंस कालेज में बम फेंकने वाला कौन था और मिथिला विश्वविद्यालय छात्रसंघ के महासचिव चौधरी बैजू का इस घटना से कितना संबंध है? विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को बन्द कर देने हेतु क्या उग्रपंथी एवं राष्ट्रद्रोही तत्व प्रशासन को डरा धमका नहीं रहे थे? उपकुलपति निवास पर बम फेंकने वाला व्यक्ति कौन है और दरभंगा स्टेशन पर पकड़ा गया दूसरा व्यक्ति कौन है? उपकुलपति के कार्यालय के पास आयुर्वेद कालेज के छात्र जगदीश शाह पर प्राणघातक हमला करने वाले गुंडे छात्रों को चौधरी बैजू एवं उसके साथियों ने क्या प्रोत्साहित नहीं किया? लालबाग डिस्पेंसरी के निकट एक रिक्शे पर दो जीवित बम का पकड़ा जाना तथा बिना किसी पूछताछ के रिक्शे वाले को छोड़ दिया जाना क्या पुलिस द्वारा अराजकतावादियों को संरक्षण दिये जाने का प्रमाण नहीं है? लहेरिया सराय में एक छात्र की हत्या और प्रशासन की चुप्पी, मारवाड़ी कालेज एवं कुंअर सिंह कालेज के बीच जातीय दंगा, मारवाड़ी कालेज में आगजनी, छात्रावासों से अल्पसंख्यक छात्रों का भगाया जाना क्या उग्रपंथियों की सक्रियता और पुलिस की अक्षमता को साबित नहीं करता है?

मिथिला विश्वविद्यालय में आतंक के इस दौर के चालू रहते हुए छात्रों एवं अध्यापकों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे शान्त रहकर पठन पाठन का वातावरण बनाये रखेंगे।

गोरखपुर विश्वविद्यालय : महाविद्यालयों का बोझ

गोरखपुर विश्वविद्यालय का विगत शैक्षणिक सत्र तो जुलाई, १९७७ में ही प्रारम्भ हो गया था परन्तु वर्षान्त के बाद भी अब तक परीक्षाओं का सिलसिला प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि में चाहे जो भी कारण रहा हो पर विश्वविद्यालय प्रशासन की अनियमितता और अदूरदर्शिता भी कम नहीं रही है।

छात्रसंघ के चुनाव के पश्चात नये छात्रसंघ अध्यक्ष शीतल पांडेय ने बिहार की 'आरक्षण की राजनीति' के आधार पर आन्दोलन शुरू किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र और छात्रसंघ सामान्य तौर पर आरक्षण दिये जाने के विरुद्ध हैं। इस आन्दोलन के कारण विश्वविद्यालय छिटपुट रूप से लगभग दो महीने बन्द रहा और इसके बाद मई के दूसरे सप्ताह से ग्रीष्मावकाश हो गया। अब पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं की परीक्षायें ८ अगस्त से कराने की घोषणा हुई है।

अनियमितता का एक ही उदाहरण देना काफी होगा। शोध छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लगभग दो लाख रुपये विश्वविद्यालय को विगत सत्र के प्रारम्भ में ही दे दिया था पर न तो उक्त धनराशि का ही कुछ पता है और न छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले शोध छात्रों का अब तक चयन ही किया गया है।

विश्वविद्यालय की पत्रिका पिछले चार वर्षों से प्रकाशित नहीं हुई है। पत्रिका के कोष में विद्यार्थियों के पत्रिका शुल्क का लगभग पौने दो लाख रुपया जमा है। छात्र पत्रिका शुल्क की वापसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस सम्बन्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक अक्षमता के पीछे मूलभूत कारण यह है कि ८५ से अधिक महाविद्यालय उससे सम्बद्ध रहे हैं जिनमें विद्यार्थियों की कुल संख्या एक लाख से ऊपर है। फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ३२ महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का पिछले वर्ष निर्णय किया गया। लेकिन उन महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्यालय व्यवस्था का स्थानान्तरण अब तक नहीं हुआ है। उपकुलपति हरिशंकर चौधरी इस सम्बन्ध में केवल आश्वासन ही देते आ रहे हैं।

जुलाई के दूसरे सप्ताह में श्री महेश चन्द्र पाठक के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपकुलपति से मिलकर विश्वविद्यालय में आवश्यक सुधार के लिए एक १२ सूत्री ज्ञापन दिया। उपकुलपति ने परीक्षा सम्पन्न कराने और कार्यालयों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल से सहयोग मांगा जिसे विद्यार्थी परिषद के स्थानीय मन्त्री दिग्विजय सिंह एवं सेन्ट एन्ड्रूज महाविद्यालय के महामन्त्री अष्टभुजा शुक्ल ने सहर्ष स्वीकार किया है। परन्तु विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में वाइसचांसलर महोदय मौन हैं।

● अशोक कुमार सिंह

शिक्षा मन्त्रियों का दिल्ली सम्मेलन

विगत १३, १४, १५ जुलाई को दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन न तो कोई नवीनता लिए हुए था न ही इसे शिक्षा क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन होने है उनके बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये और फिर पूरी निष्ठा तथा संकल्प के साथ उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए। श्री देसाई ने बच्चों पर पाठ्य पुस्तकों का बोझ न डालने की राय दी। उन्होंने कहा शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थी को इस बात की पहचान कराना है कि समय और व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि शिक्षा संस्थाओं को सरकारी शिकंजे से मुक्त होना चाहिये।

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास करके यह निर्णय लिया गया है कि स्कूली शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तीन स्तरों में विभाजित होगी और कुल मिलाकर १२ साल चलेगी। स्नातक पाठ्यक्रम तीन सालों का रहेगा लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो दो साल व तीन साल का ऑनर्स कोर्स चला सकती है। सम्मेलन की राय थी कि राजनैतिक दलों और उनसे संबद्ध संगठनों को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अभियान में भाग लेने दिया जाय परंतु वे किसी प्रकार के सरकारी अनुदान के हकदार नहीं होंगे। स्वयंसेवी संगठनों को भी अनुदान राज्य सरकारों के जरिये ही दिये जायें। सम्मेलन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पर अपनी सहमति दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निर्णय को ध्यान में रखते हुए जुलाई के अन्त तक राज्यों से अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देने को कहा गया है।

□ रजत शर्मा

हरियाणा : दस धन दो पर बहस जारी

हरियाणा के शिक्षा शास्त्रियों तथा राज्य शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने हरियाणा सरकार से आगामी अप्रैल से राज्यों में १०+२+३ शिक्षा पद्धति लागू करने का आग्रह करते हुए सुझाव दिया है कि जब तक उच्चतर विद्यालयों में इस पद्धति की पढ़ाई और प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध नहीं हो जाता, उसे कालेजों में सम्बद्ध कराया जाये। इससे शिक्षा तो उचित प्रकार की होगी ही, गत तीन वर्षों से कालेजों में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या घट जाने से जो प्राध्यापक और प्रयोगशालाएं फालतू हो गयी हैं उनका भी सदुपयोग हो सकेगा। यह तथा नयी शिक्षा पद्धति के बारे में बहुत से अन्य सुझाव गुड़गांव में सम्पन्न एक उच्चस्तरीय शिक्षा सम्मेलन द्वारा दिये गए हैं।

सम्मेलन ने सुझाव दिया है कि +२ स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के सुप्रबन्ध के लिए राज्य के शिक्षा निदेशालय में एक विशेष, व्यावसायिक शिक्षा सेल खोला जाये जो अन्य कार्यों के अतिरिक्त उद्योग, कृषि, रोजगार, तकनीकी शिक्षा आदि विभागों का शिक्षा विभाग से निरन्तर तालमेल करायेगा। जब तक उचित प्रबन्ध नहीं हो जाता, +२ स्तर की परीक्षा पाठ्य विधि का निर्माण तथा उचित पुस्तकें लिखवाने का कार्य हरियाणा स्कूली शिक्षा बोर्ड करता रहेगा।

सम्मेलन में भाग लेने वालों में राज्य के शिक्षा निदेशक श्री ओ.पी. भारद्वाज और स्कूली शिक्षा निदेशक श्री धर्मवीर के अतिरिक्त स्थानीय राजकीय एवं सनातन धर्म कालेज के प्राचार्य क्रमशः डाक्टर विष्णु भगवान तथा महेन्द्र प्रताप कौशिक, राज्य शिक्षा संस्थान एवं विज्ञान संस्थान के निदेशक श्री बी०पी० बंसल एवं श्री इन्द्रजीतसिंह, सिरसा और गुड़गांव के जिला शिक्षा अधिकारी क्रमशः चौधरी धर्मसिंह ढिल्ला तथा कुमारी कांता राजदान तथा हरियाणा की प्रौढ़ शिक्षा विभाग अध्यक्ष डाक्टर (कुमारी) स्वर्ण आतिश ने भाग लिया।

सम्मेलन ने पहली समिति की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया कि बच्चा स्कूल में अधिक से अधिक तीन घंटे रहे। इसके विपरीत सुझाव दिया कि हरियाणा में स्कूली विद्यार्थियों को कम से कम पांच घंटे और दस मिनट स्कूल में रहना चाहिए। इस समय का किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, सम्मेलन ने इससे सम्बद्ध विस्तृत सुझाव दिया है।

सम्मेलन के अनुसार पहली कक्षा से ही वार्षिक परीक्षा, विद्यार्थी को देनी चाहिए। परन्तु पांचवी कक्षा से पूर्व किसी विद्यार्थी को फेल नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी पांचवी कक्षा में फेल हो जाए, उसे दो महीने के उपरान्त जिन विषयों में वह अनुत्तीर्ण होता है उनमें पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए। पांचवीं कक्षा की परीक्षा स्कूल स्तर पर न होकर 'क्लस्टर्स' स्तर पर होनी चाहिए। सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया कि वर्तमान पब्लिक स्कूल बन्द कर दिये जायें।

बुन्देलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा का सवाल

परीक्षा की तिथियों के सवाल को लेकर बुन्देलखंड विश्वविद्यालय (झांसी) के छात्र मार्च अप्रैल के महीने से ही उत्तेजित रहे हैं। विश्वविद्यालय के अध्यापक मई के महीने में परीक्षाओं में निरीक्षण का कार्य करने को तैयार नहीं थे और उपकुलपति का कहना था कि परीक्षाओं की व्यवस्था सम्बन्धी तैयारी विश्वविद्यालय पूरी नहीं कर सकता है। इस प्रकार लम्बे काल तक परीक्षा टलने की आशंका से छात्र क्षुब्ध हो उठे और विश्वविद्यालय का वातावरण गरम हो उठा। उपकुलपति जिनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई है, परीक्षाओं को अधिक से अधिक समय तक टालना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बुन्देलखंड कालेज के कुछ छात्रों को इकट्ठा करके उनसे परीक्षा टालने की मांग स्वयं करायी और विद्यार्थी परिषद के विरोध के बावजूद परीक्षा की तिथियां जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दी गईं। पर जुलाई में भी विश्वविद्यालय तैयार न था और अगस्त-सितम्बर में परीक्षा कराने की बात कही जाने लगी। उपकुलपति ने स्वयं परीक्षाओं के आरम्भ होने की तिथि १७ अगस्त घोषित की। इसके विरुद्ध विद्यार्थी परिषद ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर तथा कुलाधिपति, शिक्षामन्त्री, मुख्य मन्त्री आदि को ज्ञापन देकर जेहाद छेड़ा जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षा की तिथी पुनः एक जुलाई घोषित हुई। परीक्षायें तो प्रारम्भ हुई हैं पर छात्र बराबर आशंका की स्थिति में जी रहे हैं। एक स्थाई उपकुलपति की नियुक्ति ही बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की तात्कालिक आवश्यकता है।

□ सुरेश पचौरी

उत्तर प्रदेश : उपकुलपतियों का एक और सम्मेलन

लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश के उपकुलपति सम्मेलन के निर्णय के प्रति जो लोग बड़ी आशा लगाये बैठे थे उन्हें उससे निराशा ही हाथ लगी। उसके कुछ निर्णय तर्कसंगत हो सकते हैं पर समस्या का सही निदान करने में सम्मेलन बुरी तरह विफल रहा है। सम्मेलन की विफलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि बैठक के तुरन्त बाद ही कुछ उपकुलपतियों ने अपना असन्तोष व्यक्त करते हुए सरकारी निर्णय उन पर थोपने का आरोप लगाया, यह आरोप सही है या नहीं, यह एक अलग विषय है। पर इन उपकुलपतियों को यदि कोई बात विद्यार्थी समुदाय या शिक्षा के हित में नहीं लगती थी तो उन्होंने सम्मेलन में उसका खुला विरोध क्यों नहीं किया? इससे अलावे रही बात सम्मेलन के निर्णयों की। मोटे तौर पर उसके निर्णय इस प्रकार हैं— विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम ५५ प्र० श० अंक निर्धारित हो, छात्रसंघों के चुनाव अप्रत्यक्ष हों, किसी छात्र को विश्वविद्यालय में अधिकतम ७ वर्ष की अवधि तक ही अध्ययन की छूट हो (शोध कार्य छोड़कर), परिगणित— जन जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए ३० प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायं आदि।

जहां तक विश्वविद्यालयों में न्यूनतम ५५ प्रतिशत अंक की अनिवार्यता का प्रश्न है, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। उच्च शिक्षा का स्तर उठाने के लिए यह आवश्यक है। पर ऐसा करने के पूर्व इण्टर की परीक्षाओं में होने

शिक्षा मंत्री कालीचरण : शिक्षा में तानाशाही

वाली नकल व भ्रष्टाचार को रोकना आवश्यक है। अन्यथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उच्च अंक की अनिवार्यता अर्थहीन हो जायगी। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सामान्य लिपिक पदों के लिए न केवल इण्टर तक की शिक्षा पर्याप्त मानी जानी चाहिए अपितु उच्च शिक्षा इन पदों के लिए निषिद्ध बनाई जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष सरकार प्रत्येक छात्र पर लगभग १२०० रु० खर्च करती है। जनता की यह राशि केवल क्लर्कों के निर्माण में खर्च करना कहां तक उचित है?

दूसरी बात है छात्र संघों के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करने की। यह बात किसी से छिपी नहीं कि तथाकथित छात्र असन्तोष के पीछे मुट्ठी भर पेशेवर छात्र नेता और उन्हें समर्थन देने वाले कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ और अध्यापक हैं। अतः ७ वर्ष की अधिकतम सीमा-वाली बात तो ठीक है पर अप्रत्यक्ष चुनाव से कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रयोग में भ्रष्टता कम नहीं होती यह अपने देश के राजनीतिक जीवन का अनुभव है।

पिछड़े वर्गों को आरक्षण अवश्य देना चाहिये पर ऐसा करते समय उनके स्तर का ध्यान भी रखना होगा। प्रवेश के समय उन्हें ५ या १० प्रतिशत अंकों में छूट देना तो ठीक है पर यह कदापि उचित नहीं कि उनके लिए न्यूनतम कोई सीमा ही न रहे। जहां एक ओर यह आवश्यक है कि पिछड़े वर्गों का सामाजिक और शैक्षणिक स्तर उठाने के लिए उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं दी जाय वहीं यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शिक्षा के स्तर का ह्रास न होने पावे।

पर इतने मात्र से विश्वविद्यालय की अशान्ति का अन्त नहीं होगा। समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन, शिक्षितों को रोजगार और स्वार्थी राजनीतिज्ञों से विश्वविद्यालयों को मुक्ति की व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक इन ऊपरी उपचारों से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

शैक्षणिक सुधार के लिए विद्यार्थी परिषद का ज्ञापन

सेवा में
राज्यपाल महोदय,
उत्तर प्रदेश।
महामहिम,

उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक समस्याओं पर विचारार्थ आपके द्वारा आहूत उपकुलपति सम्मेलन को हम युक्तिसंगत समाधान खोज निकालने की आपकी शुभेच्छा का प्रतीक मानते हैं। इस अवसर पर जबकि उपकुलपतिगण शैक्षिक जगत विशेषतः विश्वविद्यालयों में संबंधित विषयों पर विचारविमर्श कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पक्ष प्रस्तुत करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। यद्यपि हम जनता सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति के मुखर विरोधी उपकुलपति श्री डी०डी० पन्त के संबंध में अपनायी गयी अन्यायमूलक नीति से क्षुब्ध हैं और राजनीतिक कारणों से नियुक्त एवं विविध अनियमितताओं के दोषी उपकुलपतियों की पदमुक्ति की मांग पर बरकरार हैं तथापि इस मंच पर हम अपना दृष्टिकोण इस आशा से प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह किसी ठोस, व्यावहारिक और सार्थक निष्कर्ष तक पहुंच सकने में सहायक होगा।

उत्तर प्रदेश का पिछला शैक्षिक सत्र (१९७७-७८) अराजकता एवं अव्यवस्था की स्थिति से गुजरा है। छात्र असन्तोष का मूल

कारण कुलपतियों की अक्षमता के साथ-साथ उनका आपात समर्थक रुख भी रहा है जिसके फलस्वरूप छात्रों से सीधे संवाद करने के स्थान पर अन्य शोषणीय तरीकों का आश्रय लिया गया। प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, भाई भतीजा-वाद एवं अनेक अनियमितताओं के गम्भीर आरोप हैं। इन आरोपों के साक्षी रूप में पक्के सबूतों से सम्पुष्ट होने के उपरान्त हम ऐसे कुल-पतियों की तत्काल पदमुक्ति की मांग कर चुके हैं। परिसर के अन्दर अशान्ति के लिए मूलतः उच्च शिक्षा का विसंगतिपूर्ण ढांचा, छात्रों और प्रशासन के मध्य संवादहीनता, राजनीतिक दलों का सीधे अथवा अपने युवा संगठन द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में अनुचित हस्तक्षेप एवं प्रशासन के प्रश्रय पर असामाजिक तत्वों की सक्रियता उत्तरदायी है। सरकारी दल भी दोहरे स्तर पर इस अपराध में हिस्से-दार है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि लोकतां-त्रिक संघर्ष की विजय की देन है, स्वयं लोक-तांत्रिक मूल्यों के प्रति ईमानदारी नहीं बरती है। हमारी केन्द्र एवं राज्य सरकार से मांग है कि छात्र समस्याओं के सम्बन्ध में निदानमूलक नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कारगर कदम उठायें जाय। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा ६ मार्च १९७५ को भारतीय संसद में प्रस्तुत जनता मांग पत्र में उल्लिखित शिक्षा सम्बन्धी मुद्दों पर जिनसे वर्तमान सर-कार प्रतिबद्ध रही है, शीघ्र निर्णय लिये जांय। जनता मांग पत्र के शिक्षा विषयक मुद्दे निम्न हैं :—

(१) शिक्षा को भारतीय चरित्र से अनु-प्राणित एक नये समाज के निर्माण का उपकरण बनाया जाए जो पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करे। (२) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की विषय वस्तु और स्तर को उन्नत करने एवं वर्तमान प्रचलित ढांचे को प्रत्येक स्तर पर सुधारने हेतु प्रभावकारी कदम उठाए जांय। (३) माध्यमिक स्तर से शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाय और ऐसी आर्थिक योजना निरू-पित की जाए ताकि शिक्षा आर्थिक सुरक्षा के रूप में नौकरी की गारन्टी प्रदान कर सके।

(शेष पृष्ठ ३० पर)

सरकारी हस्तक्षेप का मैं विरोधी हूं

शिक्षा क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का मैं शुरू से विरोधी रहा हूं. राज्य को चाहिए कि वह विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करे. किन्तु विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वह इसका उपयोग पूरे संयम और उत्तरदायित्व से करें। यदि राज्य हस्तक्षेप करता है तो इसका विरोध होना चाहिए, किन्तु स्वायत्तता के नाम पर विश्वविद्यालय भी राष्ट्र की जरूरतों की अन-देखा नहीं कर सकते हैं।

—प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई

विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी

—रामनरेश यादव

उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री राम नरेश यादव ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शांति स्था-पना के लिए विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के नाम जारी की गई एक अपील में यह चेतावनी दी है कि सरकार शिक्षा कार्य में रोड़े अटकाने वाली तथा प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने वाली कारवाइयों को निष्क्रिय होकर नहीं देखती रहेगी। यदि राज्य की जनता के हित में आवश्यक हुआ तो वह विश्वविद्यालय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने में भी नहीं हिचकिचायेगी और उस दशा में स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार आवश्यक अधिकार अधिग्रहण करने के उद्देश्य से नियमों में भी परिवर्तन कर सकती है। श्री यादव ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश में हाल में हुए उपकुलपतियों, शिक्षाविदों तथा छात्र नेताओं के जो सम्मेलन आयोजित हुए वे इस दिशा में एक उपयोगी कदम हैं और यह आशा की जाती है कि इन सम्मेलनों में जो सुझाव सामने आए हैं वे छात्रों की समस्याओं का एक स्थायी हल ढूंढने में सहायक होंगे।

विश्वविद्यालय सरकारी नियंत्रण में रहेंगे—राज्यपाल का अध्यादेश जारी

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गणपति राव देवजी तपासे ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश १९७८ जारी कर उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय अधि-नियम १९५८ तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्व-विद्यालय अधिनियम को संशोधित कर दिया है। इस अध्यादेश द्वारा चांसलर को (जो कि राज्यपाल हैं) किसी वाइसचांसलर द्वारा विश्व-विद्यालय के परिनियमों के उल्लंघन करने या अधिकारों का दुरुपयोग करने या दुर्व्यवहार करने पर उसे निष्कासित या निलम्बित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है।

इस अध्यादेश के अधीन चांसलर आवश्य-कता पड़ने पर किसी वाइसचांसलर को छः महीने की अवधि के लिए तदर्थ नियुक्त कर सकता है। यह अवधि दुबारा बढ़ायी जा सकती है किन्तु एक साल से अधिक नहीं होगी।

इसी अध्यादेश द्वारा चांसलर को आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय शिक्षक या अधिकारी को निलम्बित करने का अधिकार दिया गया है। निलंबन के पश्चात सक्षम अधिकारी उसके विरुद्ध जांचकर कार-वाई करेंगे।

शिक्षक : वेतनभोगी या बुद्धिजीवी

प्रो० ओम प्रकाश कोहली

शिक्षक की गणना बुद्धिजीवियों में होती है। शिक्षक, साहित्यकार और लेखक, डाक्टर, इंजीनियर, पत्रकार समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्य है। कलाकार भी बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवियों से समाज को विशेष अपेक्षा रहती है। समाज का मार्गदर्शन करना बुद्धिजीवियों का नैतिक दायित्व माना जाता है। बुद्धिजीवी समाज को बौद्धिक वैचारिक नेतृत्व देते है, वे समाज की आंखे होती है। जिस समाज में बुद्धिजीवी वर्ग मार्गदर्शन के अपने नैतिक दायित्व के प्रति उदासीन हो जाता है, वह समाज दिशाहीनता के अन्धकार में भटक जाता है।

क्या हमारा शिक्षक बुद्धिजीवी के नैतिक दायित्व का पालन कर रहा है? शिक्षकों का सीधा सम्बन्ध छात्रों से रहता है, जिनमें किशोर और युवा वर्ग भी शामिल है। शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने छात्रों का मार्गदर्शन कर उनमें योग्य संस्कारों और वृत्तियों का विकास करे, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का सन्तुलित विकास कर उन्हें व्यक्तित्व सम्पन्न बनाए। छात्रों के व्यक्तित्व के चारित्रिक और नैतिक पहलुओं को विकसित करने की जिम्मेदारी भी शिक्षक पर है। शिक्षक का काम शिक्षार्थी को जीवन-कला सिखाना है, न कि सिर्फ पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों और पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाना। परीक्षा के लिए शिक्षार्थी को तैयार करने के उद्देश्य से निर्धारित पाठ्यक्रम का शिक्षण तो शिक्षक से अपेक्षित कर्तव्यों और क्रियाकलापों का एक अत्यन्त छोटा अंश है। इसे ही शिक्षक का सम्पूर्ण कर्तव्य और दायित्व मान लेना शिक्षक की अवगणना और अवमानना होगी। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा परीक्षाभिमुख और डिग्री केन्द्रित हो गयी है। और शिक्षा के सच्चे उद्देश्य से उसका सम्बन्ध कट गया है। परिणामत: शिक्षक भी यह मान बैठा है कि उसका व्यावसायिक दायित्व छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना मात्र है। जीवन-कला सिखाना शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं रहा, फिर शिक्षक अपने दायित्व से स्खलित क्यों न हो।

आज हमारी शिक्षा-संस्थाओं का वातावरण अनेक विकृतियों का शिकार है। शैक्षिक वातावरण ध्वस्त हो गया है। अनुशासनहीनता जोरों पर है। छात्र न शिक्षकों को कुछ समझते हैं और न ही शिक्षा-संस्थाओं के अधिकारियों को। परीक्षा में नकल खुले आम चलती है। खुद शिक्षक नकल कराते हैं। छात्र शिक्षकों को एप्रोच करते हैं और शिक्षक उन्हें परीक्षा के प्रश्न-पत्र में रखे गए प्रश्न बता देते हैं। अनैतिक कार्य कराने के लिए शिक्षकों को एप्रोच करने में न छात्र हिचकते हैं और न ही अनेक शिक्षक ऐसा कार्य करने में हिचकते हैं। गलत तरीकों से परीक्षा में अंक बढ़वाए-घटवाए जा सकते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली लागू की, लेकिन शिक्षकों और छात्रों की मिली-भगत के कारण यह प्रणाली मजाक बनकर रह गयी। प्रवेश के मामले में भी कम भ्रष्टता नहीं है। कहीं-कहीं पैसे लेकर शिक्षक प्रवेश दिलाने में मदद करते हैं। शिक्षकों में उनकी अपनी राजनीति चलती है। अधिकांशतया शिक्षक-राजनीति नियुक्तियों के इर्द-गिर्द घूमती है। नियुक्तियों के मामले में खूब धांधली चलती है। कभी इसका आधार राजनैतिक होता है और कभी जातिवाद। नियुक्ति की वस्तुगत और प्रामाणिक प्रणाली के अभाव में इस क्षेत्र में मनमानापन करने की खूब गुंजाइश रहती है। कोई भी कुलपति या विभागाध्यक्ष अपने पद का नियुक्तियों के लिए 'उपयोग' करने में किसी दूसरे से पीछे नहीं रहता। शिक्षा संस्थाओं में शिक्षक जाति और राजनीति के आधार पर बटे रहते है। अधिकारी-समर्थक और अधिकारी-विरोधी, शिक्षकों के ऐसे गुट भी रहते है। अधिकारी— विभागों के अध्यक्ष, प्रिंसीपल, डीन, कुलपति—अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए कभी शिक्षकों के एक गुट का सहारा लेते हैं और कभी दूसरे गुट का। छोटी-मोटी सुविधाओं और प्रलोभनों के लालच में शिक्षकों का प्रो० अथारिटी गुट अधिकारियों की गलत नीतियों का अविवेक पूर्ण समर्थन करता है तो एंटी-अथारिटी गुट विरोध के

लेखक

लिए विरोध करता है। शिक्षकीय राजनीति शिक्षकों तक सीमित नहीं रहती, छात्रों में संक्रांत हो जाती है। विरोधी गुट के शिक्षकों के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ छात्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे शिक्षक राजनीति छात्र राजनीति से मिलकर विस्फोटक और विध्वंसक रूप धारण कर लेती है। शिक्षक राजनीति का एक महत्वपूर्ण आयाम अधिकारियों की राजनीति होता है। शिक्षकीय राजनीति के उत्तेजना भरे वातावरण में शैक्षिक कार्यक्रम और क्रियाकलाप उपेक्षित हो जाते हैं। शिक्षक संस्था में कम-से-कम समय बिताता है। क्लास-रूम के बाहर शिक्षक और छात्र के बीच जो जीवन्त सम्बन्ध रहना चाहिए, उसका हमारी शिक्षा-संस्थाओं में प्राय: अभाव है। क्लास ली और घर भागे, अधिकांश शिक्षकों की यही मनोवृत्ति रहती है। छात्रों से निकट व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करने और उनकी कठिनाइयों-समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक समझने और उनका योग्य समाधान करने की न शिक्षकों में रुचि है और न ही इस दिशा में कोई चेष्टा या प्रयास। अपवाद तो हर स्थिति में होते ही है, पर सामान्य स्थिति यही है। शिक्षक छात्रों से अलग-अलग रहता है। इस मन:स्थिति के कई कारण है। शिक्षक का अहम् एक कारण है, जिसकी वजह से वह अपने को छात्र से श्रेष्ठ और बड़ा समझकर घुलमिल नहीं

शेष पृष्ठ ३३ पर

वन्दे मातरम की गूंज——और——फांसी की वह रात

• राष्ट्र प्रकाश

भारत मां की गोद ने हजारों ऐसे लाल पैदा किए हैं जिन्होंने समय-समय पर इसकी सेवा एवं रक्षा हेतु अपने प्राणों की बलि तक चढ़ाने में तनिक भी देर नहीं की। इन सबकी गाथाएं अपने आप में अनूठी व प्रेरणादायक हैं। आज ऐसे सब चरित्र महापुरुष बनकर हमारे सामने आ गये हैं। जब उनके चरित्र और जीवनवृत्त का स्मरण करते हैं तो बरबस ही मुंह से निकल पड़ता है— धन्य-धन्य है भारत भू की धूल।

११ अगस्त १९०८ के दिन एक उन्नीस वर्ष के युवक को फांसी के फन्दे की ओर ले जाया गया। चेहरे पर मुस्कराहट होठों पर वन्दे मातरम का स्वर व हाथ में श्री भगवद्गीता लिए वह युवक फांसी पर चढ़ गया— इस आशा से कि मैं अपने देश को स्वतन्त्र कराऊंगा कौन जानता था कि यह बलिदानी एक दिन सबका आदर्श बनने वाला है और क्या इस युवक ने भी कभी सोचा होगा कि बलिदान के कारण मेरी पूजा होगी। उसने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। उसके मन में भारत मां की गुलामी के कारण एक तड़प थी। वह उस हालत को कैसे देख सकता था जब वन्दे मातरम कहने पर सजा मिलती हो। वह युवक थे खुदीराम बोस। जिन्हें यह देश ११ अगस्त को पुण्य श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।

बंगाल की भूमि में ३ दिसम्बर १८८९ को जन्मे खुदीराम बोस के सर से छः वर्ष की अवस्था में ही माता-पिता का साया प्रकृति ने हटा लिया। शायद इसमें भी नियति की ही इच्छा थी जिसके कारण बचपन से ही कठोर स्वभाव और कष्ट झेलना मानो उनका एक स्वभाव सा ही बन गया था। अपनी बहन के घर रहकर बचपन में ही खुदीराम बोस के मन में एक बेचैनी हर समय रहा करती थी। १९०५ का बंगाल विभाजन जोशीले युवकों के लिए आग में घी का काम कर रहा था। एक लहर पैदा हो रही थी। चारों ओर गिरफ्तारियों का बोलबाला था। ऐसे समय में खुदीराम बोस का सम्बन्ध क्रान्तिकारियों के एक गुप्त संगठन से जुड़ गया। देश के कोने-कोने में इस बंग-भंग का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। इसने भारत में राज करने वाले अंग्रेजों के मन में डर पैदा कर दिया और वे जान गये कि अब अधिक दिन वे भारत में नहीं टिकने वाले हैं। यही था बंगाल विभाजन का आन्दोलन जिसने बंकिम चन्द्र चटर्जी के आनन्दमठ के "वन्दे मातरम" गीत को आने वाली पीढ़ियों का प्रेरणा स्रोत बना दिया। हर एक देश-भक्त "वन्दे मातरम" का ही पाठ करता दिखाई देता था।

अमर शहीद खुदीराम बोस

१९०६ में मेदिनीपुर में एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन अंग्रेजों की ओर से हुआ था। प्रदर्शनी में कुछ इस प्रकार की फोटो और कलाकारी थी कि जिसके कारण भारतीयों पर अंग्रेजों की एक छाप पड़ सके और प्रभाव बन सके कि अंग्रेज भले ही विदेशी हैं लेकिन भारतीयों का उत्थान कर रहे हैं और इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार हो रहा था उसे इसके माध्यम से छिपाने का प्रयत्न था— प्रदर्शनी में सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए लोगों को जुटाया जा रहा था। काफी भारी भीड़ प्रदर्शनी को देखने के लिए आ रही थी। खुदीराम बोस भी प्रदर्शनी में पहुंचे, देखने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए कि यह सब ढोंग है। उन्होंने पर्चे हाथ में लिए हुए थे जिन पर "सोनार बांगला" और "वन्दे मातर..." के नारे लिखे हुए थे और अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों की दास्तान भी वे पर्चे बखूबी बोल रहे थे। खुदीराम बोस के पर्चे बांटते ही दर्शकों की भारी भीड़ में खलबली मच गयी और उन लोगों ने जो अंग्रेजों के भक्त थे और जिन्हें स्वतंत्र भूल चुका था, उन्होंने खुदीराम बोस को पकड़ने का प्रयत्न किया, डराया और धमकाया भी। लेकिन खुदीराम बोस बखूबी पर्चे बांटते हुए वहां से भाग निकलने में सफल हो गये। इस बीच एक पुलिस वाले ने उनका हाथ पकड़ लिया। खुदीराम बोस ने एक जोर का झटका देकर पुलिस वाले के नाक पर एक मुक्का जड़ दिया और वन्दे मातरम का उद्घोष करते हुए वहां से निकलने में सफल हो गये।

एक बार खुदीराम बोस एक मन्दिर में गये। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग मन्दिर के फर्श पर काफी समय से भूखे रहकर लेटे हुए हैं। खुदीराम ने पास के कुछ लोगों से पूछा कि ये लोग इस प्रकार से क्यों लेटे हुए हैं— तो एक ने उत्तर दिया कि ये लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं और इस विश्वास से यहां पर भूखे-प्यासे लेटे हुए हैं कि जब स्वप्न में इनको भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो इससे इनकी बीमारियों का अन्त हो जाएगा। खुदीराम ने कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा, "हां मुझे भी एक दिन भूख-प्यास छोड़कर मरना देना है।" इस पर एक व्यक्ति ने पूछा, "तुम्हें कौन सी बीमारी लगी हुई है?" खुदीराम ने हंसते हुए कहा, "क्या गुलामी से बढ़कर भी कोई भयंकर

बीमारी हो सकती है, मुझे इस गुलामी को हटा देना है।" इस समय खुदीराम बोस की आयु केवल १६ वर्ष की थी। भारत मां को दासता की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए यह बाल हृदय कितना व्यथित था— उसका इस घटना से बखूबी अन्दाज लगाया जा सकता है।

वन्दे मातरम की गूंज ने खुदीराम को प्रफुल्लित कर दिया था। बंगाल के विभाजन का जो विरोध हुआ था उसे खुदीराम ने अपनी आंखों से देखा था। जब उन्होंने "आनन्दमठ" पुस्तक पढ़ी तो उन्हें मानो रास्ता मिल गया। इस पुस्तक में उन्होंने पढ़ा कि किस प्रकार क्रान्तिकारी संगठित होकर अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनकी बहादुरी, कष्ट और निष्ठा ने तो खुदीराम का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि मुझे भी क्रान्तिकारी बनना है। और क्रान्तिकारियों से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी।

खुदीराम ने धीरे-धीरे हथियारों का इस्तेमाल करना भी सीखना शुरू कर दिया और "वन्दे मातरम" के प्रचार को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तय किया। जैसे-जैसे वन्दे मातरम का प्रचार अधिक होने लगा, अंग्रेज सरकार अधिक निर्दयीहोती गयी। लेकिन सभी सभाओं में वन्दे मातरम का उद्घोष होने लगा। जब भी दो देश भक्त मिलते तो नमस्कार के स्थान पर वन्दे मातरम का उद्घोष करते। जहां कहीं भी कोई वन्दे मातरम बोलता और पुलिस की नजर में आ जाता उसको बुरी तरह बेरहमी से पीटा जाता। अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचारों से भारतीयों का दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर 'स्वदेशी' आन्दोलन की लहर में विदेशी कपड़े, स्कूलों का बहिष्कार प्रारम्भ हो गया। अंग्रेज सरकार ने देश भक्तों की जहां अधिक गतिविधियां थीं, ऐसे आफिसर नियुक्त किये जो काफी निर्दयी थे और जो छोटी से छोटी बात के लिए भी घोर दंड देने में नहीं हिचकते थे। जार्ज किंग्सफोर्ड भी कलकत्ता के ऐसे ही निर्दयी मजिस्ट्रेटों में से एक था।

श्री विपिन चन्द्रपाल द्वारा शुरू किये गये अखबार "वन्दे मातरम" पर जिसका सम्पादन महर्षि अरविंद घोष कर रहे थे अंग्रेजों की आंखें थीं क्योंकि यह क्रान्तिकारियों के लिए प्रेरणास्रोत था। १९०६ में अंग्रेज सरकार ने

अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद

इस अखबार पर प्रतिबंध लगाकर मुकदमा शुरू कर दिया। कोर्ट में जब इसकी कार्यवाही चलती थी, हजारों युवक कोर्ट के बाहर खड़े होकर वन्दे मातरम के समर्थन में नारे लगाया करते थे, और पुलिस बुरी तरह से लाठी चार्ज किया करती थी। वैसे तो क्रान्तिकारी पहले से ही किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने की सोच रहे थे पर सुशील कुमार नामक युवक को निर्दयतापूर्ण दण्ड देने के कारण क्रान्तिकारियों ने उसको मार डालने की योजना बना ली। इसकी सूचना जब गुप्तचर विभाग तक पहुंची तो उन्होंने सरकार को सलाह दी कि वे किंग्सफोर्ड को इंग्लैंड भेज दें। सरकार ने इंग्लैंड भेजने की बजाय उसकी तरक्की करके मुजफ्फरपुर भेज दिया और मान लिया कि अब किंग्सफोर्ड सुरक्षित है, उसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्रान्तिकारी तो ठान बैठे थे कि ऐसे क्रूर व्यक्ति का खात्मा करना ही है। १९०८ में क्रान्तिकारियों ने तय किया कि किंग्सफोर्ड को गोली का निशाना बनाया जाए और खुदीराम बोस ने इस काम को पूरा करने का बीड़ा अपने हाथ में लिया। सभी खुदीराम के बारे में विश्वस्त थे। खुदीराम के साथ उनकी आयु के प्रफुल्ल चाकी को भी दो रिवाल्वर एक बम देकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर पहुंचकर दोनों ने एक धर्मशाला में शरण ली। उस स्थान का निरीक्षण किया जहां किंग्सफोर्ड रहता था और ३० अप्रैल १९०८ की रात में किंग्सफोर्ड के बगले से आती हुई बग्घी पर खुदीराम ने बम का धमाका कर दिया। क्रान्तिकारियों द्वारा फेंका गया यह पहला बम था। खुदीराम व प्रफुल्ल चाकी दोनों ही भाग निकले। किंग्सफोर्ड बच गया था क्योंकि वह बग्घी में नहीं था। इस बग्घी में तो किंग्सफोर्ड के मेहमान वकील कैनेडी की पत्नी व लड़की बैठी हुई थीं। दोनों का ही प्राणान्त हो गया।

खुदीराम रात भर भागते रहे और जब सुबह रुके तो२५ मील आगे निकल चुके थे। एक रेलवे स्टेशन पर कुछ खाने के लिए गये, शरीर तो टूट ही चुका था। दो महिलाओं की हत्या हो गई है—यह बात जब स्टेशन मास्टर ने उस दुकान पर आकर बतायी तो तुरन्त खुदीराम के मुख से निकला, "क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा है?" खुदीराम के इन शब्दों को सब लोगों ने सुना और सोचा कि हो न हो यही वह युवक हो जिसने बम मारकर हत्या की हो और सबने मिलकर पुलिस में खुदीराम को पकड़वा दिया।

दूसरी ओर प्रफुल्ल चाकी भी खुदीराम की तरह भाग निकले और कई दिनों तक पीछा करने के बावजूद पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे। प्रफुल्ल चाकी ने तय किया कि मैं जिन्दा अपना शरीर अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दूंगा

शेष पृष्ठ ३३ पर

पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक सेवा कार्य

● कुमारी ज्योति दाते

भारत में अनेक छात्र संगठन हैं पर उनमें से अधिकांश पर राजनैतिक दलों का प्रभाव होने के कारण वे संगठन रचनात्मक कार्यों से पृथक हैं। इसके विपरीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक स्वतन्त्र छात्र संगठन है जो अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये कार्यक्रम छात्र-छात्राओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। छात्राओं का सामाजिक सहभाग बढ़ाना विद्यार्थी परिषद का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए सेवा प्रकल्प योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय पुस्तक निधि, ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान, साक्षरता योजना, मेरा घर भारत देश आदि रचनात्मक प्रकल्प भी चलाये जा रहे हैं।

मराठवाड़ा के उस्मानाबाद जिले के लातूर नामक स्थान में विद्यार्थी परिषद ने पिछले वर्ष से १४ छात्रों के निवास स्थान की व्यवस्था की है जिनमें ५ हरिजन और २ वनवासी छात्र भी शामिल हैं। केवल २५ रुपये प्रति महीने में यह व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है। ये विद्यार्थी पालिटेकनिक कालेजों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आदि में अध्ययन करते हैं। इस होस्टल में एक पुस्तकालय भी है जिसमें ३०० से अधिक पाठ्यपुस्तकें हैं। सामाजिक समस्याओं से छात्रों को अवगत कराने की दृष्टि से प्रत्येक सप्ताह इस होस्टल में विद्वान व्यक्तियों के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।

परिषद के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से झुग्गी-झोपड़ी वाली बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों से मिलते हैं। शांति कालोनी का लातूर के कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया है और आन्ध्र के तूफान पीड़ितों के लिए सहायता राशि एवं सामग्री भी एकत्रित की।

लातूर में विवेकानन्द संस्कार केन्द्र स्थापित है। डा० बी० आर० मराठीय इसके अध्यक्ष और श्री शिवाजी राव पाटिल इसके संस्थापक हैं। केन्द्र द्वारा शिक्षण के विभिन्न प्रकल्प शुरू किए गये हैं जिनके द्वारा छात्रों में निहित प्रतिभाओं को विकसित किया जाता है। यह कार्य विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वयं की प्रेरणा से करते हैं। विवेकानन्द संस्कार केन्द्र के मंत्री श्री प्रकाश पाठक ने बताया कि केन्द्र के १२० फीट लम्बे और ८० फीट चौड़े स्थान में २५ छात्रों के रहने की व्यवस्था शीघ्र ही हो जायेगी। औरंगाबाद और नांदेड़ में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षणिक केन्द्र है। वहां के एक मेधावी छात्र को केन्द्र की ओर से डाक्टर बनाने की योजना है।

पुने जिले के चार छात्रों के रहने की व्यवस्था सोलापुर के होलाड बस्ती के चार परिवारों में की गई है। बम्बई के आसपास की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले कुछ छात्रों को महाविद्यालय में शिक्षा दिलायी जा रही है। शेर पाव में हरिजनों के लिए एक होस्टल है। उसमें रहने वाले मागास कातकरी समाज के लोगों को कलात्मक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ता सक्रियता से जुटी हुई है। पुने के कुलाबा क्षेत्र में श्री बापमारे पिछले साल से प्रौढ़ साक्षरता वर्ग चलाते हैं। पुने जिले में परिषद कार्यकर्ताओं ने १५० गावों का निरीक्षण किया और २१ केन्द्रों को चुनकर वहां सुधार कार्य करने की योजना बनायी है। महाराष्ट्र के हर जिले में २० कार्यकर्ताओं की एक टोली बनाकर गांवों व झुग्गी-झोपड़ियों में कार्य करने का निश्चय किया गया है। बंबई में एक वर्ग आयोजित कर इस कार्य के लिए छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित भी किया जायगा।

पूना में क्रांतिवीर चाफेकर की स्मृति में स्मारक बनाने के लिए १५० फीट लम्बी और २८ फीट चौड़ी एक जगह परिषद कार्यकर्ताओं ने ली। अब यहां वाचनालय, छात्राओं के निवास स्थान, क्रान्तिकारियों पर प्रेरणादायक पुस्तकों वाला पुस्तकालय भी चलाया जा रहा है। आपातकाल के दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने इन्स्टिट्यूट आफ एजूकेशन आफ पालिटिक्स एण्ड इकनामिक्स के डायरेक्टर डा० दांडेकर के मार्गदर्शन में सार्वजनिक कुओं का निरीक्षण किया। सर्वे में यह तथ्य सामने आया कि सरकारी योजना से बनाए गए ८० कुओं का अस्तित्व केवल कागज पर ही

शिरोड़े प्लाट की झुग्गी-झोपड़ी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षण कार्य

शेष पृष्ठ ३० पर

भेंट वार्ता केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री से अरुण जेटली की बातचीत

शैक्षणिक आचार संहिता के लिए सर्वदलीय सम्मेलन

शिक्षा क्षेत्र का पिछला वर्ष प्रायः सारे देश में ही छात्र-शिक्षकों के आन्दोलन का वर्ष रहा है। आपातकाल की समाप्ति और लोकतांत्रिक जनता सरकार की स्थापना के बाद ऐसे उप-कुलपतियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालयों के छात्र आन्दोलित रहे जिन्होंने आपातकाल के दौरान निरंकुश रहकर विद्यार्थियों और शिक्षकों पर अत्याचार किये। शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की मांग भी बड़े जोर-शोर से उठी। शिक्षा के प्रश्न पर प्रधान मन्त्री, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के बीच मौलिक मतभेद ने छात्रों को निराश किया। इसी बीच छात्रसंघों के वर्तमान ढांचे के औचित्य पर भी प्रश्न उठाए जाने लगे हैं और यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रसंघों का राजनैतिक महत्व कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इन सारी स्थितियों पर केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डाक्टर प्रताप चन्द्र चन्दर से बातचीत करने पर ऐसा लगा कि शिक्षा क्षेत्र में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए जनता सरकार भी उत्सुक नहीं है।

प्रश्न : जनता सरकार बनने के बाद से जो छात्र असंतोष दिखाई देता है उसके समाधान के लिए सरकार क्या कुछ करने वाली है?

उत्तर : हम शीघ्र ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुला रहे हैं ताकि सभी की सहमति से शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सामान्य आचार संहिता बनाई जा सके।

छात्र असंतोष केवल इसी वर्ष में बढ़ा हो, ऐसी बात नहीं है। १९७४ में छात्र असन्तोष के के ११,५०० मामले थे। १९७७ में इन मामलों की संख्या ७,५०० थी। १९७६ में छात्र असंतोष के मामले सबसे अधिक हुए हैं जबकि आपात स्थिति अपनी चरम सीमा पर थी। इस काल के दौरान ४७ प्रतिशत मामले हिंसक थे।

प्रश्न : इस असंतोष के पीछे कारण क्या है?

उत्तर : ज्यादातर कारण राजनीतिक हैं, जैसे विश्वविद्यालयों में जातिवाद को लेकर आन्दोलन होना। शैक्षिक समाज का इन समस्याओं पर कोई नियन्त्रण नहीं है। छात्र असंतोष के अन्य भी कारण हैं—वाइसचांसलरों का गलत रवैया, आपस में भेदभाव, प्राध्यापकों के बीच गुटबन्दी, शिक्षकों एवं छात्रों का समर्थन प्राप्त करने में ज्यादातर उपकुलपतियों की असमर्थता। कई स्थानों पर जायज मांगों को

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर

स्वीकार नहीं किया गया। सामूहिक नकल एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यह आम शिकायत रही है कि प्राध्यापक अपनी कक्षाओं में पाठ्यक्रमों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन सब समस्याओं को प्राथमिकता देकर सुलझाना होगा।

प्रश्न : छात्रसंघों के ढांचे में परिवर्तन के लिए कई स्थानों से आवाज उठ रही है। इस सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं?

उत्तर : प्रजातान्त्रिक देश में छात्रों में छात्रसंघ का निर्माण होना आवश्यक है। यह असंभव है कि प्रजातान्त्रिक देश में शिक्षक और विद्यार्थी राजनीति में न जायें परन्तु यह राजनीति शिक्षा परिसरों में नहीं की जानी चाहिए। मेरा चौधरी चरण सिंह से इस सम्बन्ध में मतभेद है कि छात्रसंघों की सदस्यता ऐच्छिक कर दी जाए। अप्रत्यक्ष चुनावों में कई बुराइयां हैं पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनावों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। विश्वविद्यालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों में विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए।

प्रश्न : शिक्षा के वर्तमान स्तर से क्या आप सन्तुष्ट हैं?

उत्तर : मैं यह नहीं मानता कि शिक्षा का पूरा स्तर खराब है। हमारे वैज्ञानिक, वकील एवं शिक्षाशास्त्री जो योगदान दे रहे हैं, उसे भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षा का हमारा सारा ढांचा खराब नहीं है फिर भी इसे काफी स्तर तक ऊंचा उठाया जा सकता है। हमें प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना होगा। शिक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वह आज नहीं है। छठवीं कक्षा के बाद ६० प्रतिशत, आठवीं के बाद ७५ प्रतिशत और दसवीं कक्षा के बाद ९० प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ना बन्द कर देते हैं और उच्च शिक्षा केवल ३ प्रतिशत लोगों को ही मिल पाती है। हमें पाठ्यक्रमों में विषय कम करने की भी आवश्यकता है। आज यह देखने में आ रहा है कि भाषा के कारण भी छात्र विषयों को ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए विषयों की भाषा क्षेत्रीय होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय प्राथमिक शिक्षा पर २०० करोड़ रुपये व्यय करता है। उच्च शिक्षा पर व्यय ३३ प्रतिशत से कम हो गया है किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षा का गुणात्मक स्तर नीचे आया है। शेष पृष्ठ ३० पर

परिचर्चा

राष्ट्रीय छात्र आंदोलन : आम सहमति के बिन्दु

प्रस्तोता : आनन्द भारती

छात्र आन्दोलन ग्रामोन्मुखी हो

—डा० सुखदा पाण्डेय
हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय
मन्त्री, जनता युवा मोर्चा, बिहार प्रदेश

राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शक्ति के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय और मजबूत संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा-शक्ति के रूप में जनता युवा मोर्चा एक राष्ट्र-व्यापी संगठन है। डॉ० सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में गठित इस युवा-शक्ति से यह विश्वास जमता है कि यह मोर्चा देश का सबसे बड़ा तथा ताकतवर युवा संगठन सिद्ध होगा। यहां तक कि यह संगठन राजनीतिक विकल्प भी बन सकता है। विभिन्न संगठनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरने की संभावना है, कोशिश चल रही है।

मैं आपके दूसरे प्रश्न को गलत मानते हुए इसे दूसरे ढंग से वाक्य-विन्यस्त कर उत्तर देना चाहूंगी। सच्चाई यह है कि छात्र आन्दोलन ने जयप्रकाश के वर्तमान लोकनायक रूप को उभारा, जिसे स्वयं जयप्रकाश नारायण ने मंचों से स्वीकार किया है। और छात्र आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिहार शाखा ने की, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। जब जयप्रकाश जैसे राष्ट्रनेता का नेतृत्व मिला तो छात्र आन्दोलन में एक नियंत्रण व्यवस्था और अनुशासन आया। उस समय छात्र शक्ति ने संघर्ष-समिति के शामियाने के नीचे एकजुट होकर काम करना आरंभ किया। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे वाला छात्र संगठन नहीं था। छात्र आन्दोलन में हजारों अच्छे कार्यकर्ता और बीसियों नेता पैदा हुए लेकिन जनता सरकार ने कुछ अच्छे छात्र-युवकों को छोड़कर बाकी सारे गलत लोगों को टिकट दिया। संघर्ष समिति के अनेक छात्र एम० पी०, एम० एल० ए० हो गए। जे० पी० आन्दोलन में छात्र-युवा शक्ति ने तात्कालिक संगठन का रूप अवश्य धारण किया, किन्तु उसमें कोई स्थायित्व नहीं आ सका।

जे० पी० आन्दोलन के मुद्दे निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो यह आन्दोलन राष्ट्रव्यापी और सफल नहीं होता। इन मुद्दों को राष्ट्रीय छात्र-युवा आन्दोलन कहना या बनाना उचित नहीं है। छात्र आन्दोलन और युवा आन्दोलन दो अलग-अलग मुद्दे हैं। दोनों के स्वरूप और संकल्प भिन्न-भिन्न हैं। छात्र-आन्दोलन को विश्वविद्यालय परिसर की समस्याओं तक ही सीमित रखना चाहिए। शैक्षिक स्तर, खेलकूद, सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान की समस्याओं से ही इनका संबंध होना चाहिए। अधिक से अधिक छात्र आन्दोलन को सामाजिक रचनात्मक कार्यों से ही संबद्ध किया जा सकता है। उनका उपयोग राजनीति के लिए करना न केवल बेमानी है, अन्याय भी है। राष्ट्रीय आन्दोलन के मुद्दों और राजनीति स्वच्छता के आन्दोलन के पहलुओं के लिए देश की युवाशक्ति को संलग्न करना मुनासिब होगा।

संपूर्ण क्रान्ति की सफलता युवा-शक्ति के हाथ में है और इसके लिए जनता युवा मोर्चा सक्षम और सक्रिय है। सम्पूर्ण क्रान्ति के दूसरे चरण का समर्थन करते हुए मैं यह भी प्रस्तावित करना चाहूंगी कि सभी छात्रेतर युवा संगठनों को एक मंच पर जोड़ा जाए। संपूर्ण क्रांति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के मुद्दे भी हैं जिनके लिए छात्रशक्ति की सक्रियता आवश्यक है। छात्रशक्ति को राजनीतिक मुद्दों के साथ जोड़ना उचित नहीं है। अतः छात्रशक्ति और युवाशक्ति को अलग-अलग मुद्दों पर लगाकर ही संपूर्ण क्रांति का अभियान सफल बनाया जा सकता है।

छात्र-युवा आन्दोलन की प्रहार दिशा न राजनीति है, न सरकार विरोधी। उन्हें राजनीति के मंच पर लाना, उन्हें निर्मूल करना होगा। अभी इस देश में आगामी सौ वर्षों तक अनवरत आन्दोलन की आवश्यकता है। सत्ता-परिवर्तन तो हुआ, किन्तु व्यवस्था वैसी ही बनी है। यह व्यवस्था इतनी भ्रष्ट और दासता-मूलक है कि उसमें आमूल और संपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। आन्दोलन के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। संपूर्ण देश सत्ताश्रित हो गया है। इस स्वरूप को बदलना होगा। विकेन्द्रीकरण का लोकतांत्रिक मूल्य ही देश को विकसित कर सकता है। कहीं संघर्ष समिति की आवश्यकता है तो कहीं असहयोग आन्दोलन की। कहीं सहयोग की भी आवश्यकता है तो कहीं क्रान्ति की। इसलिए संपूर्ण क्रान्ति के लिए अनवरत आन्दोलन का राष्ट्र स्तर पर संचालन आवश्यक है।

मेरी दृष्टि में छात्र आन्दोलन को विश्वविद्यालय परिसर के अतिरिक्त यदि रचनात्मक सामाजिक कार्यों में सक्रिय करना है तो वह क्षेत्र ग्राम ही हो सकता है, नगर नहीं। नगर तो प्रायः स्वचालित और स्वजाग्रत होता है, किन्तु ग्राम न केवल सुषुप्त है, बल्कि निरंजनहीन भी है। इसलिए छात्र शक्ति का सही क्षेत्र ग्राम-परिसर ही हो सकता है। महात्मा गांधी ने

ग्रामोदय का अभियान चलाया था। विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान के माध्यम से गांवों की ओर ध्यान दिया। जनता पार्टी ने अंत्योदय योजना के माध्यम से ग्राम विकास का संकल्प लिया है, किन्तु ये सारी योजनाएं आंशिक सफलता ही प्राप्त कर सकीं। देश की असली प्रतिनिधि आबादी का क्षेत्र ग्राम परिसर आज भी पिछड़ा, सोया, निरक्षर, अशिक्षित और उपेक्षित है। इसलिए छात्र-युवा आन्दोलन को ग्रामोन्मुखी बनाना ही उनकी सही दिशा और नियति हो सकती है। इस संकल्प की ओर जनता युवा मोर्चा ने अपने को जोड़ा है। गांवों में रचनात्मक काम करना घास कट पर काम करना है।

छात्र-युवा शक्ति को मैं संपूर्ण क्रान्ति और अनवरत आन्दोलन से अवश्य जोड़ना चाहूंगी, किन्तु इसकी कर्मभूमि दो ही हो सकती है—विश्वविद्यालय परिसर और ग्रामांचल। छात्रेतर युवा-शक्तियों की कर्मभूमि के अनेक क्षेत्र और आयाम हैं।

जे० पी० आन्दोलन के सभी मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं

● डा० राम वचन राय
हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय

मेरा विश्वास है कि छात्र-युवा शक्ति का राष्ट्रीय संगठन उभर सकता है, बशर्ते इस दिशा में सही कदम उठाया जाय। नये रचनात्मक बदलाव की शुरुआत यही कर सकता है। विभिन्न संगठनों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। लेकिन जब तक एक उद्देश्य सामने नहीं रखा जायगा तब तक संगठन मजबूत और प्रभावशाली नहीं होगा। राजनीतिक दलों के साथ जुड़े संगठन का यही हश्र होता रहा है कि वे अपने हित के लिए अपने युवा संगठन का इस्तेमाल करते हैं। हित सिद्धि के बाद अलग हो जाते हैं। जिस दिन विभिन्न संगठन यह महसूस कर लेंगे कि उनका 'इस्तेमाल' किया जा रहा है तब उन्हें नये विकल्प की तलाश होगी और वे अपने को बृहत्तर संगठन में बांधने की आवश्यकता महसूस करेंगे। इमरजेंसी में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता जेल में मिले। कल तक जो एक दूसरे से कतराते थे वे एकत्र आये। आपस में संवाद की शुरुआत हुई। अभी भी संगठन एक मंच पर आ सकते हैं, संवाद को दिशा देने की जरूरत है।

जे० पी० आन्दोलन में छात्र-युवाशक्ति का संगठित स्वरूप एक तात्कालिक आवश्यकता के रूप में उभरा था लेकिन वह बरकरार नहीं रह सका। छोटे-छोटे स्वार्थों के कारण बिखराव शुरू हो गया।

जे० पी० आन्दोलन के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे ही तो हैं। हर कोई महसूस कर रहा है कि सामाजिक जीवन ठीक नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, सामाजिक कुरीतियों का बवण्डर, नैतिक मूल्यहीनता समाज को जकड़े हुए है। किसी स्वस्थ सामाजिक चेतना का विकास नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर विचार की आवश्यकता है। इन मुद्दों को छात्र-युवा आन्दोलन का मुद्दा बनाया जा सकता है। छात्र-शक्ति ही इन मोर्चों पर लड़ सकती है। अब तक जो लड़ाइयां होती रही हैं उन्हें राजनीतिक दल अपने ढंग से लड़ते रहे और एक सीमा के बाद व्यवस्था से समझौता भी करते रहे। छात्र-शक्ति जोखिम उठाने के लिए तैयार है। आखिरी लड़ाई यही लड़ सकता है।

छात्र-युवा आन्दोलन को पुनः सक्रिय करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका उद्देश्य विधायक या सांसद बनाना नहीं सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना होगा। सम्पूर्ण क्रान्ति के पहले चरण की लड़ाई भी अधूरी है। मात्र सत्ता का हस्तान्तरण अपने आप में क्रान्ति नहीं, वह परिवर्तन भर है। क्रान्ति की राह लम्बी है।

पूछे गए प्रश्न

- छात्र-युवा शक्ति के किसी एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरने की क्या कोई संभावना है? जे० पी० आन्दोलन में छात्र-युवा शक्ति का कोई संगठित स्वरूप उभरा था?
- जे० पी० आंदोलन के मुद्दे राष्ट्रीय बन सकते हैं या नहीं? यदि हां तो क्या वे राष्ट्रीय छात्र-युवा आंदोलन के मुद्दे बनाए जा सकते हैं? यदि नहीं तो उनका क्या और कैसा संशोधन आप चाहेंगे?
- छात्र-युवा आंदोलन को पुनः सक्रिय किया जाय? जे० पी० के ताजा आह्वान के संदर्भ में आपके विचार (सम्पूर्ण क्रांति के दूसरे चरण) का क्या है?
- छात्र-युवा आंदोलन की प्रहार-दिशा अनिवार्यतः राजनीति होगी? क्या उसे सरकार के विरुद्ध अनिवार्यतः उठाना होगा? क्या छात्र-युवा शक्ति और राजशक्ति के सम्मिलित प्रयास का कोई स्वरूप उभर सकता है? और क्या यह प्रयास सफल होगा?
- अनवरत आन्दोलन की स्थिति से क्या आप सहमत हैं? सम्पूर्ण क्रांति के लिए अनवरत आन्दोलन पर आपके विचार?
- छात्र-युवा आन्दोलन का केन्द्र प्रायः नगर क्षेत्र हो जाता है। क्या इसे ग्रामोन्मुखी बनाया जा सकता है?
- छात्र-युवा शक्ति को सम्पूर्ण क्रांति—अनवरत आंदोलन—के संदर्भ में क्या आप परिभाषित करना चाहेंगे?

आज छात्रों को सामाजिक परिवर्तन में एक अहम् भूमिका निभानी है। आश्चर्य होता है कि जो लड़के सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा लगाते थे वे ही परीक्षाओं में छुरा रखकर नकल करते हैं। यह बात गहरी पड़ताल की है। अपने को बार-बार टटोलने की है कि हम आखिर ऐसे क्यों हो गये? इसलिए भी इस आन्दोलन को तेज करने की जरूरत है। क्रान्ति अपने आप में बृहत्तर प्रक्रिया और मंजिल है। आन्दोलन की सही दिशा से गुजरकर हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे। मेरे विचार से दूसरे चरण की शुरुआत इसी संकल्प के साथ हो सकती है।

आन्दोलन की प्रहार दिशा अनिवार्यतः राजनीति हो ऐसा मानना एकांगी दृष्टिकोण होगा। आम तौर से ऐसे आन्दोलन को सरकार के विरुद्ध मान लिया जाता है। यूं तो छात्र आन्दोलन की प्रहार दिशा राजनीति भी हो सकती है पर उसके साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक धरातलों पर भी यह लड़ाई लड़नी होगी। कभी-कभी सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध उठना होगा, लेकिन समझदारी आवश्यक है। छात्र-युवा शक्ति और राजशक्ति का एक सम्मिलित रूप उभर सकता है। दोनों का उपयोग सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में हो सकता है। सरकार सही फैसले कर कार्यक्रम निर्धारित करे और छात्र एवं युवक उनके कार्यान्वयन के लिए पहल करें। अब तक यह स्वरूप साफ उभर कर इसलिए नहीं आया कि सत्ता में आने के बाद राजनेताओं ने छात्र-युवा शक्ति की महत्ता को नजर-अन्दाज किया है और दोनों ने सतत संवाद कायम करने की कोई चेष्टा नहीं की है। सही ढंग से इस दिशा में प्रयास किया जाए तो युवा-शक्ति और राजशक्ति का एक सम्मिलित स्वरूप उभर सकता है और उसी से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

मैं मानता हूं कि सम्पूर्ण क्रान्ति की मंजिल दूर है। इसीलिए अनवरत आन्दोलन की अनिवार्यता से मैं सहमत हूं। छिटपुट आन्दोलन और आक्रोश की अभिव्यक्ति से उस महत उद्देश्य की उपलब्धि होने वाली नहीं है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि एक बार यह धारा मन्द पड़ने पर न जाने कितनी ही कुरीतियों का ढेर जमा होने लगता है और जगह-जगह स्वार्थों, अंधविश्वासों और भ्रष्टाचारों के मामले जमा होने लगते हैं। आन्दोलन की धारा इन्हें बहा ले जाती है। इसीलिए इसकी आवश्यकता है।

अब तक का अनुभव यही बताता है कि आन्दोलन का केन्द्र प्रायः नगर ही रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि छात्र आन्दोलन को ग्रामोन्मुखी बनाया जाय। गांव का आदमी भी राष्ट्रीय हलचल में हिस्सेदारी महसूस करें। यह सोच जब तक पैदा नहीं होगी तब तक छात्र-युवा आन्दोलन नगरमुखी बनकर अधूरा ही रह जाएगा।

छात्र-युवा शक्ति सम्पूर्ण क्रान्ति (?) के संदर्भ में लड़ाई का औजार बन सकती है। वह साधन का काम कर सकती है। उसे परिवर्तन का साध्यम बनाना होगा। अनवरत आन्दोलन में कभी-कभी शिथिलता की स्थिति भी आ सकती है। दरअसल वह निराशा की नहीं शक्ति संचय की स्थिति होती है। लड़ाई के दरम्यान ही किसी व्यक्ति का चरित्र परिभाषित होता है। संघर्ष के क्रम में चीजें साफ होती चलती हैं। संपूर्ण क्रान्ति के सन्दर्भ में भी इस शक्ति को एक औजार के रूप में ही देखता हूं जिससे परिवर्तन और पुनर्निर्माण की क्रियायें सम्पादित होंगी।

राज्य शक्ति और छात्र-युवा शक्ति का समन्वय हो

● कुमार कलानन्द मणि
राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी

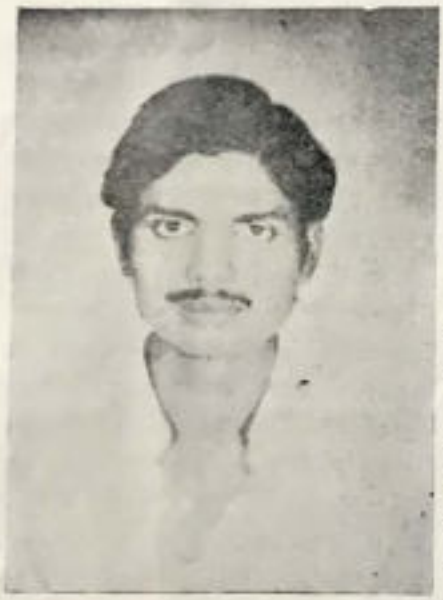

मैं यह मानता हूं कि आज राष्ट्रीय क्षितिज पर वही संगठन उभर सकता है जो आम जनता की समस्याओं की गहराई में उतर सके, जो उन समस्याओं से जूझने की तैयारी रख सके और जो अपने प्रयास से अपनी आस्था जनता में पैदा कर सके। आज इतने नारे लग चुके हैं कि सुन्दर से सुन्दर, लुभावने नारे आम जनता को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि दलीय राजनीति से प्रभावित अथवा सत्ता की राजनीति से संबद्ध छात्र युवा संगठनों ने अपने बारे में यही जताने का प्रयास अब तक किया है कि जनता हमें अपनाये, लेकिन उन्होंने कभी ईमानदारी से जनता को अपनाने की कोशिश नहीं की, उनकी आकांक्षाओं को परखने की कोशिश नहीं की। इस दिशा में वही संगठन विकसित हो सकता है, राष्ट्रव्यापी बन सकता है जो सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठा की आकांक्षा न रखता हो।

जे० पी० आन्दोलन की सबसे बड़ी असफलता मैं यह मानता हूं कि उतने बड़े आन्दोलन के बावजूद भी, जिसने जनता का अभिक्रम जगाया था, युवकों को जीवन की मूल समस्याओं की ओर आकर्षित किया था, कोई ऐसा सशक्त संगठन नहीं उभर सका जो एक दूरगामी लक्ष्य संपूर्ण क्रान्ति की ओर सम्मिलित रूप से आगे बढ़ सकता। आन्दोलन के समय छात्र-युवा शक्ति के रूप में निश्चय ही छात्र-संघर्ष समिति सत्ता से, नौकरशाही से, भ्रष्टाचार से, जूझने वाली एक मजबूत मोर्चा भर थी। पर उसके अन्दर निहित विभिन्न घटकों ने अपने-अपने संगठन को अन्दर ही अन्दर मजबूत करने का प्रयास किया। इस प्रयास ने उसके दूरगामी लक्ष्य पर दोहरी भूमिका या अधूरी निष्ठा को प्रदर्शित किया। आन्दोलन में व्यापक पैमाने पर निर्दलीय छात्र-युवा भी आये थे, जिनका पूर्व से किसी संगठन से कोई संबंध नहीं था। वह निर्दलीय शक्ति विभिन्न घटकों से नहीं, जोर न पाने के कारण अपने को असहाय सा, अलग-थलग सा पाती थी। उन्हें अपने घटक दलों या संगठनों से जोड़ने की साजिश में जे० पी० को निर्दलीय संगठन छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी का गठन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। संघर्ष वाहिनी—जिसकी भूमिका दोहरी न हो, संपूर्ण क्रान्ति के लिए जिसका पूर्ण समर्पण हो तथा उसमें उसकी पूरी आस्था हो। दुर्भाग्यवश वह संगठन भी अभी तक राष्ट्रव्यापी नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी घोषणा के थोड़े समय बाद ही आपातकाल लागू हो गया।

मैं इस बात की नितांत आवश्यकता महसूस करता हूं कि छात्र-युवा आन्दोलन को तब तक जारी रखा जाए, जब तक उन मुद्दों का साकार रूप हमें न दीखने लगे। जिन मूल प्रश्नों को लेकर जे० पी० आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था, जनता सरकार बनने के बाद भी वे आज यक्ष प्रश्न की तरह हमारे सामने हैं। जे० पी० ने तो इस प्रसंग के समाधान प्रयास को सतत् क्रान्ति का नाम दिया है।

अभी तक सत्ता के परिवर्तन में हमारा प्रयास ज्यादा लगा है, लेकिन अब जनता के

अधिकार को बचाना, जन असंतोष को संगठित कर आमूल परिवर्तन के लिए संघर्ष और रचना, दोनों पक्ष को एक साथ जोड़ते हुए सामूहिक प्रयास करना होगा। अर्थात जन-समस्याओं के विरुद्ध जनता को संगठित करना होगा। हमारे इस प्रयास से राज्य शक्ति के विकल्प के रूप में लोकशक्ति का अभ्युदय होगा। यही जे० पी० आन्दोलन के दूसरे चरण का तात्पर्य है।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि छात्र-युवा आन्दोलन की प्रहार दिशा अनिवार्यतः राजनीति होगी। साथ-साथ मैं यह भी मानता हूं कि यह परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है कि यह प्रहार राजनीति पर होगा या नहीं। संघर्ष वाहिनी यह मानती है कि इसकी प्रहार दिशा समाज के हर आयामों में होगी, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक या सरकारी क्षेत्र हो। परिस्थिति के अनुसार हम अपनी रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। समाज के नव-निर्माण के लिए राजशक्ति और छात्र-युवा शक्ति का सम्मिलित स्वरूप उभर सकता है। अगर प्रयास सही दिशा में गया तो परिवर्तन अवश्यंभावी है।

मैं यह मानता हूं कि छात्र-युवा आन्दोलन को ग्रामोन्मुखी बनाया जा सकता है, बशर्ते की हमारी रणनीति गांवों की समस्याओं से संबंधित हो, और उन आन्दोलनों में ग्रामीण युवकों की भागीदारी हो। अगर छात्र-युवा आन्दोलन को ग्रामोन्मुखी बनाना है तो हमें गांव में जाकर गांव की जिन्दगी के साथ तालमेल बैठाकर रणनीति तय करनी पड़ेगी।

छात्र-युवा शक्ति अगर सम्पूर्ण क्रान्ति में अपनी आस्था रखती हो तो उसे क्रान्ति के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास जारी रखना पड़ेगा। जे० पी० ने ५ जून ७४ की सभा में संपूर्ण क्रान्ति की घोषणा करते हुए कहा था। "मित्रो ! यह संपूर्ण क्रान्ति है, यह सतत क्रान्ति है और यह दूरगामी आन्दोलन है।"

परिचर्चा

शिक्षा में परिवर्तन क्यों होना चाहिए? क्या परिवर्तन होना चाहिए? और यह परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है? इस विषय पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' द्वारा परिचर्चा आयोजित है। इस परिचर्चा में पाठकों के विचार आमन्त्रित है। अधिक से अधिक २०० शब्दों में अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखकर या टाइप कराकर पासपोर्ट आकार के अपने एक चित्र के साथ १० अगस्त तक प्रेषित करें। प्राप्त उत्तर अक्टूबर अंक में प्रकाशित किए जायेंगे।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' हिन्दी मासिक
१६, बंगलो मार्ग, कमला नगर
दिल्ली—११०००६

सत्ता पर अंकुश रखने हेतु अनवरत आन्दोलन ★ राजाराम पाण्डे

उपाध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ

विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा हुआ है उसके और भी निखरने की संभावना है। सब संगठनों को मिलाकर एक मोर्चा बने, यह संभव नहीं, अगर बनता भी है तो वह स्थायी नहीं होगा। संगठनों में वैचारिक मतभेद इतना है कि वह एक मंच पर आ ही नहीं सकते। उन्हें अपने-अपने संगठनों को बचाने का लोभ है। संगठनों को जब तक जिन्दा रखने का सवाल मस्तिष्क में रहेगा तब तक दूसरों के साथ मिल भी नहीं सकते।

आपके सवाल से मेरा मतभेद है। यह जे० पी० का आन्दोलन नहीं था। यह छात्र आंदोलन था जिसने पहली बार कैंपस की समस्याओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय समस्याओं को उठाया। जे० पी० तो बाद में जुड़े। यह कैसे माना जाय कि यह जे० पी० आन्दोलन था? जे० पी० अगर आह्वान करते तो जे० पी० आन्दोलन कहा जा सकता था मगर यहां तो छात्रों ने ही जे० पी० का आह्वान किया था।

छात्र-युवा शक्ति का संगठित स्वरूप उभरा था, मगर वह परिस्थिति विशेष के कारण हुआ था। परिस्थिति ने उसे एक जगह जुट जाने के लिए विवश किया था। उस समय दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था।

आन्दोलन के मुद्दे राष्ट्रीय थे और अभी भी हैं। आज की सारी परिस्थितियां पहले की ही तरह हैं। कोई तब्दीली नहीं हुई है। जिन समस्याओं से हम पहले जूझ रहे थे वे समस्यायें बरकरार हैं। असमानता पूरी तरह उद्वेलित है। किसी भी समय विस्फोट हो सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता।

छात्र आन्दोलन को पुनः सक्रिय तो किया ही जाय, मगर उस आन्दोलन से आन्दोलन नहीं, उसके माध्यम से रचनात्मक पहलू को उजागर करने की आवश्यकता है। जयप्रकाश जी ने आह्वान किया है, सम्पूर्ण क्रान्ति के दूसरे चरण का। उसका अर्थ है—युवा वर्ग गांव की ओर जाय, वहां की समस्याओं को देखे, समझे और वहीं से एक आन्दोलन प्रारम्भ करे जो सही माने में ग्रामीण जनता का आन्दोलन होगा। ग्रामोत्थान की प्रक्रिया जब तक प्रारंभ नहीं हो जाती तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। सन् '४२ और उसके पहले ग्रामीण जनता के बीच से ही नेताओं ने आन्दोलन प्रारम्भ किया था जो देश की पूरी तस्वीर को बदलने में सार्थक हुआ। छात्र शक्ति के चेहरे पर ही समाज और देश की तस्वीर है उसे साफ करना बहुत जरूरी है। अभी तो पहला ही चरण पूरा नहीं हुआ है, दूसरा चरण तो बहुत दूर है।

छात्र आन्दोलन की प्रहार-दिशा राजनीति नहीं होगी—मेरी ऐसी व्यक्तिगत धारणा है। मगर परिस्थिति को देखना लाजिमी है। अगर राजनीति का रंग-रवैया पहले की तरह बरकरार रहा तो छात्रों को मजबूर होकर उस पर प्रहार करना होगा। छात्र-शक्ति और राजशक्ति के सम्मिलित प्रयास का स्वरूप उभर सकता है। दोनों अगर सम्मिलित होते हैं और गांवों की ओर जाते हैं तो गांवों के हालात बदल सकते हैं।

सतत क्रान्ति की बात माओ ने की थी। समाज के सभी तबकों के बीच सफल संवाद स्थापित करने, सत्ता पर अंकुश रखने और परिवर्तन की धारा को बनाए रखने के लिए अनवरत आन्दोलन की आवश्यकता है ताकि सामाजिक परिवर्तन में जंग न लग जाय, जड़ता न आ जाय।

छात्र आन्दोलन नगर से ही प्रारंभ होता है। परन्तु अब आन्दोलन की दिशा को नगर से हटाकर सच्ची संपूर्ण क्रान्ति के लिए ग्रामोन्मुखी बनाना होगा। और गांवों का यह आन्दोलन—

१. सामाजिक विषमता पर प्रहार—छुआछूत, निरक्षरता, असमानता, शोषण, और

२. जमीन का संघर्ष—बटाईदारी, मजदूरी के खिलाफ जोरदार संघर्ष का होगा। ●●

पृष्ठ १६ का शेष **विद्यार्थी परिषद का ज्ञापन**

साथ ही अध्यापन से इतर नौकरियों में विश्वविद्यालय डिग्री की बाध्यता को हटाया जाय। (४) देश व्यापी स्तर पर प्राइमरी शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। (५) शैक्षणिक संस्थाओं में सरकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाय। इन संस्थाओं के प्रबन्धकर्ता मूलतः अध्यापक समुदाय और विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक सहभाग से जुड़े रहने चाहिए।

इन दीर्घकालिक आधारभूत मुद्दों के अतिरिक्त छात्रों की तात्कालिक समस्याओं के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय लेकर प्रदेश के लगभग पौने तीन लाख विद्यार्थियों का भविष्य संवारने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। नये सत्र की शुरुआत का समय निश्चित किया जाए। नये सत्र में प्रवेश का उपयुक्त मानदण्ड निर्धारित किया जाए तथा इसके उल्लंघन को हर स्थिति में रोका जाए। विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था का पुनरावलोकन किया जाए।

हम निम्नलिखित मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं :—

(१) उत्तर प्रदेश की जनता सरकार अपने एक वर्ष के कार्यकाल (२३ जून, १९७७ से २३ जून, १९७८) के दौरान शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों एवं व्यापक शैक्षणिक अराजकता पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए एक श्वेतपत्र प्रकाशित करे। (२) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७४ को, जिसके आधार पर प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय संचालित हैं, शीघ्र निरस्त कर उसकी स्थानापन्न व्यवस्था के रूप में विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित "आगरा परिसंवाद" की संस्तुतियों को व्यवहार में लाया जाय। (३) विश्वविद्यालय की समस्याओं के निदान हेतु प्रशासन अध्यापक और विद्यार्थियों के सम्मिलित प्रयत्नों को सफलीभूत बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को दलीय व सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करके उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए। स्वायत्तता के प्रश्न पर शिक्षा क्षेत्र के सभी घटकों एवं संगठनों (छात्र व अध्यापक संगठन) की व्यापक सहमति के आधार से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। इसके अतिरिक्त परिसर की समस्याओं से सम्बन्धित सभी घटकों के मध्य मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए एक आचार संहिता का निर्धारण किया जाना चाहिए जिसे सभी पक्ष एक नैतिक बाध्यता के रूप में स्वीकार करें। (४) प्रदेश के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र काफी विलम्ब से चल रहे हैं। शैक्षिक सत्रों को नियमित करने तथा अब और अधिक विलम्ब न होने देकर शीघ्र परीक्षाएं प्रारम्भ करने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि परीक्षायें उस सीमित पाठ्यक्रम के आधार पर ही सम्पन्न करा ली जाय जिसका अध्यापन क्रम जुलाई मास तक पूरा हो सके। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं के समाप्त होने पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक ही केन्द्र पर निश्चित समय में करा लिया जाय (५) अखिल भारतीय स्तर के कुलपति सम्मेलन, जिसमें देश के ३५ कुलपतियों ने भाग लिया था, के इस विचार से हम अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि अगले ५ वर्ष तक अब और नये विश्वविद्यालय न खोले जांय।

✲

पृष्ठ २५ का शेष **भेंट वार्ता**

प्रश्न : शैक्षिक बजट के इस असन्तुलन के लिए क्या केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है?

उत्तर : यह आरोप हम पर लगाना ठीक नहीं, क्योंकि शैक्षिक स्तर क्षेत्रीय स्तर पर होना जरूरी है। हम राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इसका हल निकाला जा सके। शिक्षा का बजट यद्यपि बढ़ रहा है पर जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ रहा है। विभिन्न राज्यों में शिक्षा व्यय अलग-अलग है। औसतन प्रत्येक राज्य शिक्षा पर १७ प्रतिशत व्यय कर रहा है जबकि केन्द्र केवल ८ प्रतिशत व्यय करता है।

प्रश्न : हवाना में होने वाले विश्व युवक मेला में भाग लेने के लिए जो भारतीय युवक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसके सम्बन्ध में प्रतीत होता है कि सरकार में आन्तरिक मतभेद है? आपकी टिप्पणी?

उत्तर : इसका शिक्षा मन्त्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न : विश्वविद्यालयों को अधिकाधिक स्वायत्तता दिये जाने की मांग पर सरकार क्या करने की सोच रही है?

उत्तर : यह शैक्षणिक समाज पर निर्भर करता है कि स्वायत्तता को किस प्रकार कायम रख सकेंगे और अपनी समस्याओं के हल विश्वविद्यालय में ही निकालेंगे। जातीय और राजनीतिक आधार पर उपकुलपतियों की नियुक्ति करना अनुचित है।

✲

पृष्ठ २४ का शेष

पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक सेवा कार्य

है। १२०० छात्रों ने १० दिन में २५०० गावों में जाकर यह सर्वे किया। सामूहिक छात्र श्रमदान से ५० कुओं को सरकारी सहयोग से बनाने का निश्चय हो गया है। इसके लिए ५०,००० रुपये का एक ट्रस्ट बना दिया गया है।

आज का विद्यार्थी कल का नहीं, आज का नागरिक है—यह विद्यार्थी परिषद का दृष्टिकोण है। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान में छात्रशक्ति की प्रभावी भूमिका हो, यही दृष्टि रखकर महाराष्ट्र प्रदेश और पूरे देश में विद्यार्थी परिषद 'ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान' जैसे रचनात्मक प्रकल्प चला रही है।

✲

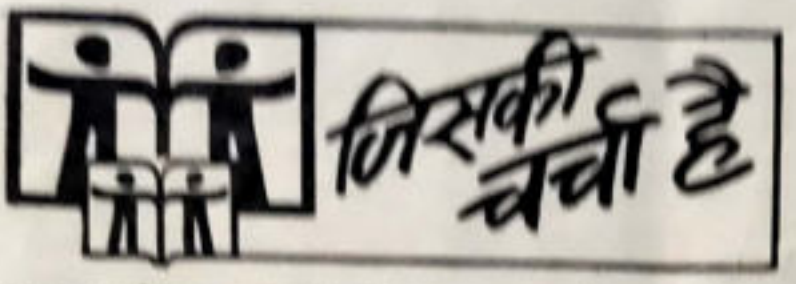

जिसकी चर्चा है

> तीसरी दुनिया के युवक आन्दोलन को भ्रष्ट और ध्वस्त करने तथा अपना पिछलग्गू बनाने में रूस और अमेरिका की रुचि अब छिपी नहीं रह गई है। सोवियत रूस तो इस काम के लिए तरह-तरह की चालें चल रहा है।

हवाना सम्मेलन : युवकों को पथभ्रष्ट करने का रूसी कुचक्र

तीसरी दुनिया के युवक आंदोलन को भ्रष्ट और ध्वस्त करने तथा अपना अपना पिछलग्गू बनाने में रूस और अमेरिका की रुचि अब छिपी नहीं रह गई है। सोवियत रूस तो इस काम के लिए तरह-तरह की चालें चल रहा है।

२८ जुलाई से ५ अगस्त तक क्यूबा की राजधानी हवाना में होने वाले युवक सम्मेलन के लिए भारत से ५० की युवक-युवतियों का प्रतिनिधिमंडल जाने की सूचना मिली है। इस प्रतिनिधि को मिली जानकारी के अनुसार इन सौ की लोगों के आने जाने का पूरा खर्च सोवियत रूस देगा। क्यूबा में निवास के दौरान वहां का खर्चा भी प्रतिनिधियों को नहीं देना पड़ेगा। भारत सरकार को भी इस प्रतिनिधिमंडल के लिए अनुमति के सिवाय कुछ नहीं देना है।

इस युवक सम्मेलन को सफल बनाने में सोवियत यूनियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उत्सुकता इसी बात से जाहिर हो जाती है कि अभी २२ मई से ५ जून तक आल इंडिया स्टूडेन्ट फेडरेशन (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का छात्र मोर्चा) के आमन्त्रण पर सोवियत रूस के लेनिनिस्ट यंग कम्युनिस्ट लीग का २४ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कामरेड सोबिर आकलीलोव के नेतृत्व में भारत आया। इस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, हैदराबाद, कालीकट और त्रिचूर का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में एक कु० नेस्काकोवा का वर्णन करते हुए भारतीय कम्युनिस्टपार्टी के छात्र और युवा संगठनों के मुखपत्र 'युथ लाइफ' जिसके संपादक कम्युनिस्ट एम०पी० श्री [illegible] हैं, ने लिखा है कि —"तीखे नाक और तीखी भौंहों पतले नीचे आंखों और भूरे बालों वाली नेस्काकोवा ने [illegible] का दिल चुरा लिया। मंच पर उसके मटकते कूल्हे और तेजी बालनृत्य की नायिका [illegible] की याद दिला रहे थे।"

उत्सव की तैयारी कराने के लिए आये हुए दल के सदस्यों का ऐसा परिचय ही उत्सव के वास्तविक उद्देश्यों और इरादों को साफ जाहिर कर देता है। आज जब तीसरी दुनिया के देशों के युवक अपनी सामाजिक, आर्थिक समस्याओं से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं—उस समय यह उत्सव उन्हें क्या मार्गदर्शन करेगा?

सोवियत रूस युवा सम्मेलनों का यह नाटक बहुत दिनों से कर रहा है। वैसे यह सम्मेलन 'विश्व जनवादी युवक संघ' नामक फर्जी संस्था के नाम से किये जाते हैं लेकिन उसका पूरा खर्चा रूस देता है। ये सम्मेलन केवल रूसी खेमे के कम्युनिस्ट देशों में ही आयोजित होते हैं। पहला सम्मेलन सन १९४७ में प्राग (चेकोस्लोवाकिया) में हुआ था। उसके बाद सन १९४९ में बुडापेस्ट (हंगरी), सन ५१ में बर्लिन (पूर्वी जर्मनी), सन ५३ में बुखारेस्ट (रोमानिया), सन ५७ में सोफिया (बल्गेरिया) और सन १९७३ में बर्लिन (पूर्वी जर्मनी) में हुआ था। हालांकि सोफिया सम्मेलन में १३० देशों ने भाग लिया था लेकिन अभी तक रूसी खेमे के देशों को छोड़कर अन्य देशों को इस लायक नहीं समझा गया कि वहां भी युवा सम्मेलन हो।

इस बार का युवा सम्मेलन क्यूबा में हो रहा है जिसकी अफ्रीका के संघर्षों में गतिविधियां यह साबित कर चुकी है कि वह सोवियत रूस के लिए मुखौटे का काम कर रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र और युवा संगठन इस सम्मेलन के स्थायी सदस्य हैं। जैसे-जैसे भारत में सत्ताधारी दलों में बदल होता है उसके अनुसार भारती प्रतिनिधियों का अनुपात बदलता है। सन ७३ के बर्लिन युवक उत्सव में भारत का प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन युवा कांग्रेसी 'हीरो' प्रिय रंजनदास मुन्शी के नेतृत्व में गया था। अब चूंकि जनता सरकार सत्ता में है इसलिए प्रतिनिधिमंडल का ढांचा जाहिरी तौर पर बदलेगा।

देश के युवा आंदोलन को भ्रष्ट और विकृत करने का यह कुचक्र भारत सरकार कब तक बरदाश्त करती रहेगी।

पृष्ठ ११ का शेष

दिल्ली विश्वविद्यालय: इमरजेंसी……

उन्होंने बदला भी लिया है। लेकिन लगता है अब पानी सर से गुजर चुका है। प्राध्यापक और विद्यार्थी दोनों राजधानी के इस विश्वविद्यालय के माथे से इस कलंक को धोने के लिये तत्पर हैं ताकि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को पुनर्जीवित तथा प्रतिष्ठा को कायम किया जा सके।

जनता सरकार आने के बाद से उपकुलपति भी नए मालिक ढूंढने में लगे हैं। लगता है कहीं न कहीं से सफलता भी हुई है पर देखना है कि उनकी ये नई तिकड़म कब तक टिकती है। ऊपर से चाहे कुछ भी हो एमरजेंसी के दस से रहने के बाद उन्हें तानाशाही और चापलूसी सिर्फ पसंद ही नहीं है उनकी आदत बन चुकी है। चुनाव हारने के बाद अब नई सरकार के नजदीकी लोगों को 'यूनिवर्सिटी नेक्सस' बनाया जा रहा है। डा० मेहरोत्रा किसी भी कीमत पर कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं चाहे वह कीमत विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा ही क्यों न हो।

अब विश्वविद्यालय खुलने पर होने वाले आंदोलन की आशंकाओं से भयभीत उपकुलपति दौरे बदल रहे हैं। बहुत से साथी उन्हें छोड़ गए हैं। स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। ★

TEXTILES, SUGAR,
INDUSTRIAL CHEMICALS,
ALCOHOLIC BEVERAGES,
VANASPATI, PVC, RAYON TYRE CORD,
FERTILIZERS,
ELECTRONIC CALCULATORS,
IRON CASTINGS.

IN THE SERVICE OF THE NATION

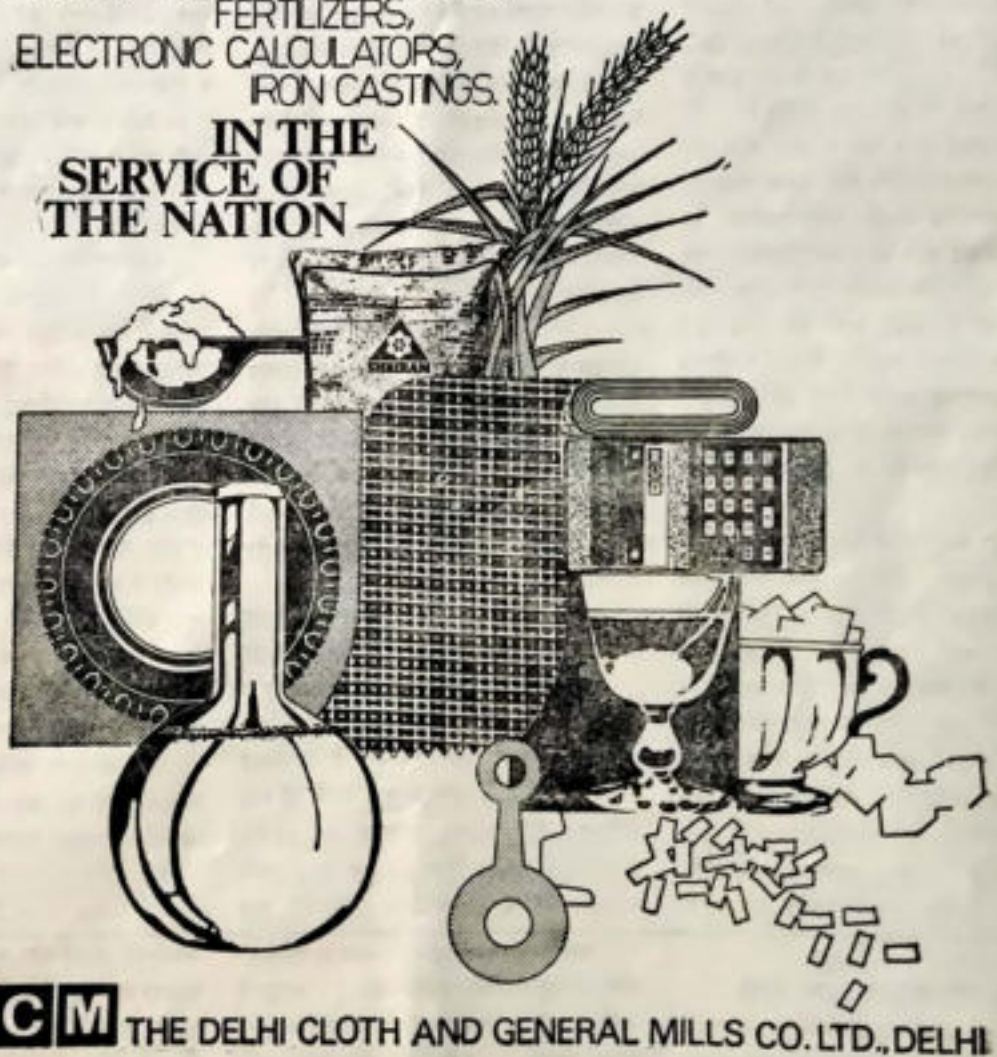

DCM THE DELHI CLOTH AND GENERAL MILLS CO. LTD., DELHI

शिक्षक ...... पृष्ठ २० का शेष

पाता। अपने को ऊँची भूमिका पर अधिष्ठित करके वह छात्रों को दूर-दूर से ही उपदेश और मार्गदर्शन देना चाहता है। दूसरा कारण शिक्षकों का यह भय है कि छात्रों के निकट सम्पर्क में आने पर कहीं उनकी अपनी कमजोरियां और व्यक्तित्व का खोखलापन अनावृत न हो जाए। शिक्षक छात्रों की आलोचना से और आलोचक दृष्टि से बचने के लिए अपने को अलग-थलग रखता है। आज का छात्र-श्रद्धालु नहीं आलोचक भी है। शिक्षक की हीन भावना शिक्षक को छात्र से जुड़ने नहीं देती।

शिक्षक और छात्र के बीच की यह संवादहीनता हमारे शिक्षा क्षेत्र की कटु वास्तविकता है। संवादहीनता के कायम रहते शिक्षक छात्रों का मार्ग दर्शन करने के अपने दायित्व को कैसे निभाए? इसके लिए शिक्षक को आत्मविश्लेषण और आत्मावलोकन करना होगा। शिक्षक मात्र वेतनभोगी नहीं; शिक्षण मात्र व्यवसाय नहीं। शिक्षा का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। सेवा की भावना और दृष्टि न रहने पर शिक्षण आर्थिक प्रक्रिया या व्यवसाय बनकर रह जाता है। शिक्षक का दर्जा गिर जाता है। वह उदर जीवी बन जाता है, बुद्धिजीवी नहीं रहता। शिक्षक को उदर जीवी बनने से बचना होगा। उसे बुद्धिजीवी ही रहना होगा।

शिक्षक और छात्र का रिश्ता वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येता का होना चाहिए। शिक्षक भी एक अर्थ में विद्यार्थी ही होता है क्योंकि सिखाने की प्रक्रिया वास्तव में सीखने की प्रक्रिया ही होती है। छात्रों से संवाद स्थापित करने के लिए शिक्षक को अपने अहम् भाव से भी छुटकारा पाना होगा और अपने हीनताभाव से भी। ऊँची भूमि पर खड़े होकर और दूर-दूर रहकर वह छात्रों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। छात्रों को अनुशासनहीन और गैर-जिम्मेदार समझकर उनसे कटकर चलने से भी मार्गदर्शन नहीं हो सकेगा। इसके लिए तो शिक्षक को छात्र का मित्र बनना होगा, बन्धु बनना होगा। किसी एक ही मिशन की पूर्ति में लगे हुए लोगों में जो सहयोग और सहकार की भावना पाई जाती है, वैसी भावना आए बिना शिक्षक छात्र के प्रति अपना योग्य अवदान नहीं कर सकता। किसी संस्था या संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता का नए या कनिष्ठ कार्यकर्ता के प्रति जो भाव रहता है, वह भाव रखकर ही शिक्षक छात्रों को जीवन-कला सिखा सकता है। इस भाव के अभाव में शिक्षक मात्र वेतन भोगी कर्मचारी बनकर रह जाएगा, मार्गदर्शन करने वाला बुद्धिजीवी नहीं। शिक्षक के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अपने बुद्धिजीवी व्यक्तित्व को बचाए रखने की और बुद्धिजीवी के नाते अपने नैतिक दायित्व का पालन कर सकने की है।

□□□

वन्देमातरम की वह गूंज......

पृष्ठ २३ का शेष

और पुलिस से मुठभेड़ करते हुए जब उनके रिवाल्वर में आखिरी गोली बची तो उसने अपने आपको शहीद कर लिया। पुलिस ने प्रफुल्ल चाकी का सर काट लिया और मुजफ्फरपुर ले गये। खुदीराम को भी पुलिस के संरक्षण में मुजफ्फरपुर ले जाया गया। हजारों लोग इस युवक का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए। वे देखना चाहते थे कि कौन है वह युवक जिसने अंग्रेजी राज्य पर पहला बम फेंक कर भारतीयों के मन की बात की है। खुदीराम वन्दे मातरम का उद्घोष करते हुए पुलिस की वैन में चढ़े। कितना भावनात्मक दृश्य था वह लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक नौजवान को जनता निहार रही थी जिसने बहादुरी के काम में अगुवाई की थी।

कोर्ट की दो महीने की कार्यवाही का नाटक चला। मजिस्ट्रेट ने खुदीराम को फांसी की सजा सुना दी और पूछा, "क्या तुम्हें कुछ कहना है?" लेकिन मजिस्ट्रेट स्तब्ध रह गया जब खुदीराम ने कहा, "हां मुझे उपस्थित जन समुदाय को बम बनाने के बारे में जानकारी देनी है।" वैसे तो खुदीराम को ब्रिटिश कोर्ट से किसी भी प्रकार की न्याय की आशा नहीं थी पर कालीदास बोस नाम के एक वकील ने, जो खुदीराम की पैरवी कर रहे थे, हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पर मोहर लगा दी और फांसी का दिन ६ अगस्त से ११ अगस्त कर दिया।

फांसी से एक दिन पहले की एक घटना है जो खुदीराम बोस की मनःस्थिति का अच्छा खासा चित्रण करती है। इस दिन खुदीराम को आम खाने के लिए दिया गया। खुदीराम ने आम खा लिया और गुठली निकालकर आम को उसी स्थिति में रख दिया। बाद में डाक्टर आये और उन्होंने खुदीराम से कहा कि तुमने आम नहीं खाया और आम को उठाने का प्रयत्न किया तो खुदीराम के मजाक के कारण डाक्टर दंग रह गये कि कल फांसी होने वाली है और आज यह हास्य। ऐसे थे खुदीराम जो अन्तिम समय में भी हिम्मत से डटे रहे और यह सोचते हुए शहीद हो गये कि जितनी जल्दी शहादत होगी उतनी ही जल्दी पुनः जन्म होगा और मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए फिर लड़ाई लड़ूंगा। अगले दिन खुदीराम हंसते-हंसते मातृभूमि की बलिवेदी पर चढ़ गये और इतिहास में अमर हो गये।

खुदीराम ने जो बम फेंका उससे किंग्सफोर्ड नहीं मरा। लेकिन जिस दिन खुदीराम शहीद हुए उस दिन से किंग्सफोर्ड के दिमाग की शान्ति खत्म हो गई। हर समय मृत्यु के डर का घेरा उसको परेशान करता था और अन्त में परेशान होकर उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मंसूरी में रहने लगा। अन्त में वह स्वयं भय और आतंक की स्थिति में मर गया।

खुदीराम तो शहीद हो गये लेकिन अपने पीछे एक ऐसी कतार बना गये जो ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने में तब तक लगी रही जब तक अंग्रेजी शासन समाप्त नहीं हो गया। किंग्सफोर्ड ने अपने पद से त्यागपत्र दिया तो अंग्रेजों ने भारत का त्याग किया। खुदीराम के बलिदान से सरकार इतनी भयभीत हो गयी कि लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं को काले पानी की सजा देकर अण्डमान भेज दिया गया। सुभाषचन्द्र बोस जैसे नेताओं के प्रेरणा स्रोत भी खुदीराम थे। कहते हैं कि खुदीराम के बलिदान दिवस पर सुभाषचन्द्र बोस ने अपने स्कूल में हड़ताल करवायी थी।

अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और युवा आंदोलन

जग मोहन मलिक

आधुनिक विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य समस्याएं काफी वर्षों से छात्र-युवा संगठनों की रुचि तथा गतिविधियों का केन्द्र रही हैं। इन समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण युवा संगठनों के स्वरूप, उनकी राजनीतिक विचारधाराओं, युवा जगत की प्राथमिकताओं, युवा संगठनों की गतिविधियों के प्रकार और उद्देश्यों एवं प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के द्वारा निर्धारित होता है।

विश्व की जटिल समस्याओं को परस्पर सहयोग से सुलझाने के लिए "शीत-युद्ध" के दौरान भी पूर्व-पश्चिम के युवा समुदाय को निकट लाने के लिए अनेक द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्रयास किए गए। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में युवा वर्ग की भूमिका पर विचार-विमर्श करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन की परम्परा का श्रीगणेश हुआ। इस तरह के विचार-विमर्श के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है और विशेषतया पिछले १० वर्षों में विभिन्न सम्मेलनों तथा विचारधाराओं को मानने वाले तथा परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों से प्रेरित अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-युवा संगठनों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस प्रकार के परस्पर सहयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा मिलती है। यूरोपियन सुरक्षा तथा सद्भावना की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सन १९७२ में हेलसिंकी में आयोजित 'युवक-सम्मेलन' युवा समुदाय द्वारा राष्ट्रों के बीच शान्ति व सहयोग स्थापना की ओर किए जा रहे प्रयासों का ज्वलंत प्रमाण है। उस गोष्ठी में एक-दूसरे से भिन्न सैकड़ों युवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने मतभेदों को समझौते द्वारा दूर किया तथा एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आधारभूत सिद्धान्तों को एक प्रस्ताव के रूप में अनुमोदित किया।

इतिहास साक्षी है कि अन्तर्राष्ट्रीय छात्र मंच की स्थापना के लिए कुछ प्रयास किए गए थे परन्तु इन प्रयासों के जिस प्रकार से विचारात्मक अर्थ लगाए गए अथवा राजनीतिक हितों को दृष्टि में रख कर जिस प्रकार उन्हें लागू किया गया, उनके कारण ये प्रयास एक 'शक्ति समूह' के प्रयास बनकर रह गए जो विश्व में अपना प्रभुत्व कायम कर रहा हो। एक तरफ तो विभिन्न देशों के छात्र-युवा संगठन अपनी विचारधाराओं से भिन्न अन्य संगठनों के साथ अपने सम्बन्धों में आक्रामक, प्रचारात्मक तथा नकारात्मक रवैया अपनाते हैं, दूसरी ओर, अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छात्र तथा युवा संगठन (वर्ल्ड फैडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ, इन्टरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन, दि कौंसिल ऑफ यूरोपियन नेशनल यूथ कमेटीज, इन्टरनेशनल फैडरेशन ऑफ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूथ इत्यादि) अपनी शक्ति के बलबूते पर युवा जगत के विभिन्न मुद्दों पर मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।

आज के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-युवा संगठन दो विचारधाराओं के आधार पर बंटे हुए विश्व के 'शक्ति-समूहों' की राजनीतिक गुटबाजी के हाथों खिलौना मात्र बनकर रह गए हैं जिन्हें अपनी-अपनी विचारधारा का प्रसार करने का माध्यम बनाया जाता है। कम्युनिस्ट गुट का 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ' इसका एक उदाहरण है जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन को बड़े देशों की स्वार्थ पूर्ति के लिए नियोजित ढंग से तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं।

और, इस तरह से विभिन्न युवा संगठनों के आपसी सम्बन्धों में भी गुटबंदी के कारण दरारें आ गई हैं। एक ओर, सम्पर्क तथा विचार-विमर्श के लिए अब वातावरण अधिक शैक्षणिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय संगठन परस्पर सहयोग बढ़ा रहे हैं परन्तु दूसरी ओर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं—जैसे कि निरस्त्रीकरण तथा मानवाधिकार के प्रश्न—जहां पर काफी समय से असहमति, विद्वेष तथा शंकाओं के कारण सहयोग नहीं हो पाया। यही वह क्षेत्र है जो विभिन्न संगठनों के दृष्टिकोण तथा उनकी गुट नीतियों को प्रदर्शित करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-युवा आन्दोलन ने अपनी गतिविधियों में नए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना करने के लिए संघर्ष छेड़ने जैसे आधारभूत विषयों की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया है। नए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना को प्रायः एक आर्थिक संदर्भ में देखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप सारी चर्चा "अमीर-गरीब", "समान-असमान" अथवा "विकसित-विकासशील" जैसे शब्दों के जंजाल में उलझ कर रह जाती है।

इस दृष्टिकोण का प्रभाव यह पड़ा कि अन्तर्राष्ट्रीय युवा संगठन एक सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक गुट निरपेक्ष नीति की कल्पना करने में असफल सिद्ध रहे। विकसित राष्ट्रों के युवा संगठन अक्सर गुट निरपेक्षता की नीति को कोई महत्व नहीं देते। यही नहीं, यहां तक कि गुटनिरपेक्ष तथा विकासशील राष्ट्रों के युवक संगठन भी गुट निरपेक्षता की नीति की शक्ति तथा प्रभाव से अनभिज्ञ हैं।

लगभग सभी अन्तर्राष्ट्रीय युवा सहयोग दो दिशाओं में प्रवाहित है: प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रों से और राष्ट्रीय संगठनों से। परन्तु दोनों दिशाएं राजनीतिक वातावरण तथा कूटनीतिक दावपेचों से प्रभावित होती हैं। युवा वर्ग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से किये गये प्रयास लगभग नगण्य हैं। इसका प्रमुख कारण शायद राष्ट्रीय छात्र-युवा संगठनों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच सीधे संपर्क के उपयुक्त साधनों की कमी है जो कि आज तक सदस्य राष्ट्रों की सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-युवा केन्द्रों के द्वारा संचालित किया गया है।

आज एक नए अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की अद्भुत दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है जो सभी शक्ति-समूहों (पावर ब्लाक्स) को नकारता है तथा राष्ट्रों, जातियों, रंगभेदों, द्वीपों, दर्शनों और विचारधाराओं से ऊपर उठा हुआ है। एक ऐसे दर्शन का हम विकास करें जो मानवकल्याण को सम्मान के साथ, व्यवस्था के साथ स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय सम्मान को अन्तर्राष्ट्रीय बंधुत्व के साथ जोड़ता है। तभी हम पायेंगे कि हमने वस्तुतः एक "अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन" की स्थापना की है। ★

हवाना सम्मेलन : के०जी०बी० का एक आपरेशन

जग मोहन मलिक द्वारा

क्यूबा की राजधानी हवाना में २८ जुलाई से विश्व युवक मेला का आयोजन किया गया है। क्यूबा में यह जोरों से प्रचार किया जा रहा है कि भारत की जनता पार्टी सरकारी स्तर पर एक प्रतिनिधि मंडल हवाना सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेज रही है। जनता पार्टी के कई नेताओं ने कम्युनिस्ट सम्मेलन के साथ जनता पार्टी के गठजोड़ की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के महामन्त्री श्री मधुलिमये ने वक्तव्य जारी कर स्पष्ट किया है कि सत्तारूढ़ पार्टी का क्यूबा जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल से कोई संबंध नहीं है। प्रधान मन्त्री सचिवालय द्वारा पूछताछ करने पर श्री मोरारजी देसाई को बताया गया कि पार्टी अपना कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज रही। शिक्षा मन्त्री डाक्टर प्रतापचन्द्र चन्दर ने बताया है कि प्रतिनिधिमंडल का शिक्षा मन्त्रालय से भी कोई संबंध नहीं है। परन्तु डा० सुब्रमण्यम स्वामी ने हवाना में सम्मेलन के आयोजकों द्वारा वितरित साहित्य प्रधान मन्त्री को दिखाया जिसमें दर्शाया गया है कि जनता पार्टी अपना युवक प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेज रही है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हवाना सम्मेलन की आड़ में सोवियत कम्युनिस्ट लाबी द्वारा 'तीसरी दुनिया' के देशों के छात्र आन्दोलनों को प्रभावित करने के घृणित प्रयासों की कड़ी निन्दा की है। यह सर्वविदित है कि इस तरह के सम्मेलन प्रति चार वर्ष पश्चात एक कम्युनिस्ट देश में आयोजित होते हैं। पिछले दो सम्मेलन बर्लिन (पूर्वी जर्मनी) तथा सोफिया में किए गए थे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्री महेश शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि भारत सरकार को इस सम्मेलन में कोई भी प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि हवाना सम्मेलन छात्र जगत को संगठित करने का एक स्वयंसेवी तथा गुट निरपेक्ष प्रयास नहीं है, बल्कि बड़े राष्ट्रों द्वारा छात्र आन्दोलन को दिग्भ्रमित, दूषित तथा पथभ्रष्ट करने वाले राजनीतिक षडयन्त्र का एक हिस्सा है। भारत जैसे लोकतान्त्रिक व गुट निरपेक्ष देश को इस कम्युनिस्ट साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। जनता सरकार, जो कि सही अर्थों में वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने को वचनबद्ध है, से आशा है कि वह एक सही दृष्टिकोण अपनायेगी। श्री महेश शर्मा ने सन्देह व्यक्त किया है कि शिक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के कुछ अफसरों ने इस सारे मामले को बड़ी चालाकी से तोड़-मरोड़ दिया है। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि भारत सरकार हवाना युवक सम्मेलन के प्रति अपने रवैये को स्पष्ट करे। विद्यार्थी परिषद बड़े राष्ट्रों द्वारा भारत में छात्र आन्दोलन को पथभ्रष्ट कर उसमें फूट डालने की घृणित हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी तथा अपनी पूरी शक्ति से उनका विरोध करेगी।

जनता युवा मोर्चा ने हवाना सम्मेलन का बहिष्कार करने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल से जनता युवा मोर्चा के सदस्यों को अलग करने के निर्णय का कारण बताते हुए जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद सदस्य डा० सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि हवाना सम्मेलन मात्र एक के० जी० बी० आपरेशन है। इस सम्मेलन में भारत की उपस्थिति को अफ्रीका में क्यूबा के सैनिक हस्तक्षेप को भारत सरकार की स्वीकृति के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा जबकि इसके विपरीत भारत सरकार अफ्रीका महाद्वीप में सभी विदेशी सेनाओं की उपस्थिति के सख्त विरुद्ध है। इसलिए जनता युवा मोर्चा ने कम्युनिस्टों द्वारा आयोजित 'यूथ फैस्टीवल' के दोहरे उद्देश्यों का पर्दाफाश करने का निर्णय किया है।

उल्लेखनीय है कि विश्व की दोनों बड़ी ताकतें भारतीय राजनीति में गहरी रुचि लेती हैं। हवाना के इस कम्युनिस्ट युवक सम्मेलन के आयोजक इस देश की कम्युनिस्ट शक्तियों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं जिनके सहयोग तथा अपने गुप्तचर माध्यमों से वह हवाना सम्मेलन में भाग लेने वाले छात्र-युवा नेताओं का चुनाव करते हैं। केवल ए० आई० एस० एफ० (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा) तथा एस० एफ० आई० (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्रशाखा) ही इनके वास्तविक तथा स्थायी अतिथि रहते हैं। वामपंथी दलों, कांग्रेस तथा दूसरे दलों के अवसरवादी तत्वों को ही आज तक ऐसे सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता रहा है पर इस बार जनता पार्टी से भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजने की पेशकश की गई है। परन्तु निमंत्रण केवल 'युवा जनता' को ही मिला।

यह चिंता का विषय है कि बड़ी शक्तियां विशेषतया अमेरिका और सोवियत संघ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए छात्र आन्दोलन में फूट डालने का प्रयास कर रही हैं। सोवियत संघ ने विशेषकर पिछले दस वर्षों में इस दिशा में अपनी गतिविधियों को अनुचित व घिनौने तरीके इस्तेमाल कर कई गुना बढ़ाया है। बड़ी मात्रा में कम्युनिस्ट साहित्य मुफ्त या सस्ते दामों पर बांटने के अतिरिक्त कम्युनिस्ट अपने हितों की रक्षा के लिए छात्र गतिविधियों में भी नियोजित ढंग से घुसपैठ करते रहे हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वे छात्र नेताओं को विदेश यात्रा का प्रलोभन देने में भी नहीं हिचकिचाते।

हजारों छात्रों ने चीन छोड़ा

चीन ने अपने एकमात्र भूतपूर्व यूरोपियन कम्युनिस्ट मित्र देश अल्बानिया को हर प्रकार की सैनिक तथा आर्थिक सहायता बन्द कर दी है। इसके परिणामस्वरूप चीन में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र काफी बड़ी संख्या में चीन छोड़कर स्वदेश लौट रहे हैं। लगभग ३५०० अल्बानियन छात्र जुलाई के तीसरे सप्ताह तक पेकिंग से स्वदेश रवाना हो चुके हैं तथा शेष छात्र तथा प्रशिक्षणार्थी अगले सप्ताह तक अल्बानिया की राजधानी टिराना लौट जायेंगे। उल्लेखनीय है कि चीन में सत्ता परिवर्तन के बाद अल्बानिया के माओवादी नेता चेयरमैन हुआकुओ फेंग की माओ विरोधी नीतियों से रुष्ट हो गए हैं तथा दोनों देशों के सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं।

स्वाधीनता दिवस पर

दिशा श्री अरविन्द का राष्ट्र के नाम सन्देश

पन्द्रह अगस्त १९४७, स्वतन्त्र भारत का जन्म दिन है। एक पुराने युग की समाप्ति और नये युग का प्रारम्भ हो रहा है। किन्तु एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में हमें यह सन्धि भी प्राप्त हुई है कि हम अपने जीवन और कर्तव्य से, सम्पूर्ण मानव जाति के राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भविष्य की दृष्टि से प्रारम्भ होने वाले नये युग का आविर्भाव कराने का गौरव भी इस दिन को प्रदान कर सके।

१५ अगस्त मेरा जन्म दिन है। अब इस दिन ने स्वयं इतना महत्व प्राप्त कर लिया है कि यह बात मेरे लिए स्वाभाविक ही गौरवास्पद है। यह केवल एक संयोग मात्र है, ऐसा नहीं मानता। जिस ईश्वरीय शक्ति ने मेरे जीवन के प्रारम्भ काल से ही मेरा प्रत्येक पग ईप्सित मन्तव्य की ओर अग्रसरित करने में मेरा मार्ग दर्शन किया उसी महान सत्ता ने कार्य पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई है, ऐसा मैं मानता हूं। अपने जीवन में जो सांगठनिक आंदोलन करने का निश्चय किया था वे सभी कार्य सचमुच ही आज के दिन से अपने ध्येय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पहले ये सभी आंदोलन मुझे अव्यावहारिक स्वप्नवत लगते थे।

इस विश्वव्यापी आंदोलन में स्वाधीन भारत बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। शायद वह संसार को नया नेतृत्व भी प्रदान कर सके।

मेरा पहला स्वप्न यह था कि एक क्रांतिकारी आंदोलन प्रारम्भ कर भारत को स्वाधीन किया जाय। भारत आज स्वतन्त्र हो रहा है किन्तु उसे अखण्ड बनाना होगा। एक क्षण ऐसा भी आया जब यह लगने लगा था कि ब्रिटिश शासन आने के पूर्व विभिन्न राज्यों के बीच चलने वाली खींचतान की स्थिति कहीं स्वाधीनता की प्रक्रिया में पुनः प्रारम्भ न हो जाय। यह आशंका सदैव से अब समाप्त सी हो गयी है और अधूरी ही क्यों न हो किन्तु एक विशाल और शक्तिमान एकता की आधारशिला शीघ्र ही प्रस्थापित की जा सकेगी। उसी प्रकार संविधान परिषद ने बुद्धिमत्तापूर्वक जो प्रगतिशील मार्ग स्वीकार किया है उससे यह संभावना भी बलवती हो गई है कि दलित वर्ग की समस्या का हल भी बिना कटुता अथवा विद्वेष उत्पन्न किये ही सरलता पूर्वक हो सकेगा। किन्तु हिन्दू और मुसलमानों के पुराने जातीय द्वेष ने और भी भयंकर रूप धारण कर उसके आधार पर देश का स्थायी विभाजन करने की स्थिति निर्माण कर दी थी। ऐसी आशा करनी चाहिए कि सद्य: स्थिति से स्वीकार की गई यह बात स्थायी सत्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं की जायेगी और उसे एक तात्कालिक घटना से अधिक महत्व नहीं दिया जायेगा। यदि यह विभाजन बना रहा तो भारत अत्यधिक शक्तिहीन हो जायेगा। वह लंगड़ा-लूला हो जायेगा। गृहयुद्ध की आशंका भी सदैव बनी रहेगी। नये आक्रमण और विदेशी शासन की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। भारत का आंतरिक विकास और वैभव भी उससे अवरुद्ध रहेगा। राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति भी दुर्बल रहेगी। भारत का भविष्य संकटापन्न बना रहेगा। यह अशुभ आशंका यथार्थ नहीं बननी चाहिए। भारत का विभाजन समाप्त होना ही चाहिए। आइये, हम आशा करें कि भारत का विभाजन स्वाभाविक रूप से ही समाप्त हो जायेगा। केवल शक्ति और समन्वय ही नहीं अपितु समान कृति की आवश्यकता दिनोंदिन अधिकाधिक अनुभव की जायेगी तथा संगठित और एक ही कार्य करने की प्रेरणा एवं उसकी पूर्ति हेतु अपनाये गये साधनों से यह विभाजन समाप्त होगा। यह एकता किस रूप में स्थापित होगी इसका व्यावहारिक महत्व भले ही हो पर मूलतः बाह्यस्वरूप का प्रश्न महत्व का नहीं है। किसी भी साधन से क्यों न हो-किसी भी मार्ग से क्यों न हो यह विभाजन समाप्त होना ही चाहिए— एकता भी उत्पन्न होनी ही चाहिए। यह एकता अवश्यमेव प्रस्थापित होगी। भारत की भावी महानता के लिए इस एकता की नितांत आवश्यकता है।

मेरा दूसरा स्वप्न यह था कि एशिया महाद्वीप की जनता का उत्थान होकर वह स्वाधीनता प्राप्त करे तथा मानव समाज की प्रगति में अपना योगदान करने के लिए वह पुनः अग्रसर हो। एशिया अब जागृत हो चुका है। उसका अधिकांश भाग स्वाधीन हो चुका है या स्वाधीनता के पथ पर पर्याप्त आगे बढ़ चुका है। किन्तु अभी भी सीमित या पूर्ण गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए कुछ देश स्वाधीन होने के लिए छटपटा रहे हैं। इस संबंध में थोड़ा सा ही काम शेष रह गया है और आज नहीं तो कल वह भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। इस क्षेत्र में भी हिन्दुस्तान को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस भूमिका को निभाने की जो तत्परता आज दिखाई देती है उससे इसके भावी परिणाम और राष्ट्र-कुल में भारत को कौन सा स्थान ग्रहण करना संभव होगा— इसकी कल्पना अवश्य ही की जा सकती है।

मेरा तीसरा स्वप्न यह था कि संपूर्ण मानव जाति का सुधार कर उसे संतेज एवं उदात्त जीवन प्रदान करने हेतु आवश्यक जागतिक एकता की सुदृढ़ नींव डाली जाय। आज उस दिशा में मानवता ने बढ़ना प्रारम्भ किया है। एक अपरिपक्व क्रम से ही क्यों न हो परसंगठन प्रारम्भ हो रहा है। अपेक्षित कठिनाइयों से संघर्ष प्रारम्भ हुआ है। कुछ गति आई है। यह हलचल भविष्य में अधिक तीव्र होगी और अपना ईप्सित लक्ष्य प्राप्त करके रहेगी। इस क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका प्रारम्भ की है। इसदृष्टि से यदि भारत वर्तमान परिस्थिति की यथार्थता अथवा निकट-काल की संभावनाओं तक ही अपनी दृष्टि सीमित न रखते हुए भविष्य की ओर अपनी दृष्टि केन्द्रित करे और उसे निकट लाने के लिए अपने कौशल्य को विकसित करे तो राष्ट्र कुल में भारत की उपस्थिति को एक महान अर्थ प्राप्त हो सकेगा उसमें आज की धीमी और भय-ग्रस्त राजनीति समाप्त होकर प्रगति की गति तीव्रतर हो सकेगी। संभव है कोई प्रसंग विशेष इस प्रगति को

शेष पृष्ठ ४१ पर

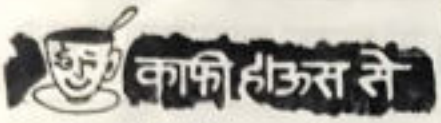

काफी हाऊस से

हम किसी से कम नहीं !

गाजियाबाद में छात्राओं ने एक बार फिर समान अधिकारों के लिये स्वर बुलन्द किया है। यहां एक कालिज की छात्राओं ने मांग की है कि उन्हें नकल करने दी जाय अथवा परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा छात्रों को उनके दम के बल पर पहले से ही प्राप्त है। एक छात्रा ने परीक्षा हॉल में छुरा निकाल कर यह भी सिद्ध कर दिया कि वे भी अब पीछे नहीं है। निरीक्षकों ने मांग की है कि पुलिस को परीक्षा भवन में भी तैनात किया जाए। समझा जाता है कि विश्वविद्यालय निरीक्षकों को परीक्षाभवन के बाहर और पुलिस को भीतर तैनात करने पर विचार किया जा रहा है।

हाय ! हवाना

पता चला है कि हवाना में होने वाले कम्युनिस्टों के इन्टरनेशनल यूथ फेस्टिवल में जाने वाले गुट में शामिल होने के लिये युवा संगठनों के भीतर भारी उखाड़-पछाड़ चल चुकी है। युवा जनता के अध्यक्ष मायाकृष्णन जिन्हें 'तैयारी समिति' का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रधानमंत्री के निकट होने के कारण युवा जनता ने चौधरी साहब के समर्थकों के नाम को तेजी से सेंसर कर दिया था। कांग्रेस (इ) और कांग्रेस के युवा व छात्र संगठनों में भी इस बात को लेकर हुई बैठकों में मार-पीट की खबरें मिली है। विदेशमंत्री ने अपना प्रभाव इस्तेमाल कर कुछ कुछ पाने की कोशिश की लेकिन फिर भी यह 'हाय ! हवाना' फेस्टिवल ही बन गया था।

छात्रसंघ प्रत्याशियों की मुसीबत

अ० भा० विद्यार्थी परिषद के चुनाव न लड़ने के फैसले से विश्वविद्यालयों में भारी उथल-पुथल मची है। चर्चा है कि कहीं फैसला बदल गया तो ? सत्ता के चापलूस संगठन परिषद को केवल अपने ही आइने में देख रहे है। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि देश के दो तिहाई विश्वविद्यालयों पर एकदम कब्जा रखने वाला संगठन सत्ता के मोह को छोड़ सकता है। जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में भी इस बात पर विचार किया गया है कि परिषद की अनुपस्थिति में चुनाव लड़ा जाए। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हालांकि बैठक में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है तो भी भीतर ही भीतर यह फैसला भी लिया गया है कि 'मोर्चा' जहां प्रभावी है वहां किसी और नाम से चुनाव लड़ेगा। यह गुपचुप फैसला विरोधी खेमों में भारी उथल-पुथल और चर्चा का विषय है।

एम० बी० बी० एस० स्नातक डिग्री नहीं ?

गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद यह निर्णय करने में असमर्थ रही कि मेडिकल साइंस की एम० बी० बी० एस० डिग्री स्नातक डिग्री है या नहीं और क्या इस डिग्रीधारी व्यक्ति को ग्रेजुएट माना जा सकता है ? यह समस्या पैदा तब हुई जब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के इन्स्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस के एक लेक्चरार ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के ला कालेज में एडमीशन के लिए आवेदन किया। उल्लेखनीय है कि एल०एल०बी० में प्रवेश लेने के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है। उक्त डाक्टर के एडमीशन का मामला अब तक रुका पड़ा है। ❋

कविता

मेरे शुभ चिंतक

एक टूटी खाट को
पूरी तरह उधेड़ कर
नए सिरे से बुनना
जब भी चाहा है मैंने
मेरे हाथ जकड़ लिए गए हैं
अपने ही लोगों की हथेलियों के बीच
जो मेरे शुभ चिंतक हैं
भोले शुभ चिंतक मेरे
बार-बार धमकाते हैं
कि रस्सियों की उधेड़-बुन में
कोमल हथेलियाँ छिल जाएंगी
खून की गर्म धार में
शुभ-रेखाएं पिघल-पिघलकर
बह जाएंगी।
कितना अनसुलझा है यह प्रश्न आज भी
कि हाथ की रेखाएं हम खुद बनाते हैं
या हस्त-रेखाओं के अनुसार ही
बनते चले जाते हैं,
भोले शुभचिंतक मेरे
हँसते-खिलखिलाते हैं
यह जानते हुए भी
कि कहीं हमने अपने कद के मुताबिक
खाट बुननी चाही थी
और अब खाट की सीमाओं में
खुद को बाँध बैठे हैं।
ये मेरे शुभचिंतक हैं !

□ विवेकानन्द
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

अधिकार और कर्तव्य

अधिकार में
चूंकि कार छिपी है
इसलिए सबको
इससे प्यार है
कर्तव्य से
चूंकि व्यय की
बू आती है
शायद इसलिए
दुनिया इससे
मुंह छिपाती है।

□ अनिल कुमार 'मधुकर'

फिर से बसन्त ला दो

पतझड़ को भगा कर
फिर से बसन्त ला दो।
मत रखो अन्तर इतना
सेतु एक बीच बना दो।
बीती बातों को—
हृदय से भुला दो।
एक बार फिर
उसी प्रकार मुस्कुरादो,
मत जाओ अब इतना गहरा
कि लग जाए होंठों पर पहरा।
आओ आकर
उस जड़ को ही जला दो;
पतझड़ को भगा कर
फिर से बसन्त ला दो। □ सुनील जेरथ

खेल संसार

भारत में १९८५ में विश्व टेबल टैनिस प्रतियोगिता

भारत को ३८वीं विश्व टेबल टैनिस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जिम्मेदारी सौंपे जाने की सम्भावना है। यह प्रतियोगिता १९८५ में होगी। यह जानकारी टेबल टैनिस संघ के अध्यक्ष श्री टी० डी० रंगारामानुजम ने दी है। भारत ने बम्बई में १९५२ में १९वीं विश्व प्रतियोगिता तथा १९७५ में कलकत्ता में तेतीसवीं विश्व प्रतियोगिता आयोजित की थी। इनमें क्रमश: १९ व ६४ देशों की टीमों ने भाग लिया था। ३५वीं प्रतियोगिता अगले प्योंगयंग (उत्तर कोरिया) तथा उसके पश्चात १९८१ में चीन में होगी। १९८३ की प्रतियोगिता जापान को दी गयी है।

राष्ट्रमंडलीय खेलों के लिए ६० सदस्यों का भारतीय दल

भारतीय ओलिम्पिक संघ के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ओ० पी० मेहरा के नेतृत्व में भारतीय ओलिम्पिक संघ का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय शिक्षामन्त्री डा० प्रताप चन्द्र चन्दर से एडमंटन दल के सभी ६० सदस्यों को सरकारी खर्च पर भेजे जाने की मांग कर रहा है। अभी तक के फैसले के अनुसार सरकार ने केवल ५३ सदस्यों के आने-जाने का मार्ग व्यय करने की सहमति प्रदान की है। इन ५३ सदस्यों में ४१ प्रतियोगी, १० प्रशिक्षक, मैनेजर तथा दो अन्य अधिकारी शामिल हैं। पांच प्रतियोगियों तथा दो अधिकारियों को इस शर्त पर मंजूरी दी गयी है कि वे अपने खर्चे से एडमंटन जा सकते हैं। समझा जाता है कि शिक्षा मन्त्रालय अपने इस रुख पर दृढ़ है कि अगर दल की संख्या में वृद्धि करनी ही हो तो खिलाड़ियों को बढ़ाया जा सकता है, अधिकारियों को नहीं। संभवत: इसीलिए सरकार अपना भी प्रेक्षक एडमंटन भेजने में रुचि नहीं रखती, हालांकि आयोजकों से इस आशय का निमंत्रण उसे अलग से मिला है। सरकार ने एडमण्टन के राष्ट्रमण्डलीय खेलों में भाग लेने के लिए ६० सदस्यों के दल को वहां जाने की अनुमति दे दी है। ये खेल ३ से १२ अगस्त तक होंगे। सरकार दल के सदस्यों के मार्ग व्यय का ८५ प्रतिशत भार वहन करेगी। शेष राशि खेलों के आयोजक देंगे। सरकार द्वारा लगभग पांच लाख रुपया खर्च होगा। एथलेटिक्स के खिलाड़ियों की सूची निम्नलिखित है : पी० गणशेखरन, शिवनाथ सिंह, मोहिन्दर सिंह गिल, सतवीर सिंह, गिरीश पटेल, सुरेश बाबू, प्रवीन कुमार व बहादुरसिंह। टीम के साथ एक मैनेजर व प्रशिक्षक होगा।

खेल परिषद का पुनर्गठन

□ संदीप भार्गव

राजस्थान में पहले जनता वर्ष में खेलों की हालत कोई सन्तोषजनक नहीं रही। पिछले वर्ष न तो कोई योजनाबद्ध रूप से खेलों के विकास के लिए काम हुआ न ही प्रस्तावित धनराशि का कोई सदुपयोग हो सका। अनुदानों का तो कुछ पता ही न था। और पिछले दो महीनों में तो यह हालत हो गई थी कि परिषद का काम लेखाधिकारी सम्भाले हुए थे। प्रशिक्षकों को कोई पूछने वाला ही नहीं था। उनकी तो मौज थी। परिषद के अध्यक्ष राजसिंह दो महीने तक लन्दन में थे। उनकी अनुपस्थिति तथा परिषद के उपाध्यक्ष का एक गैर खेल अधिकारी होने के कारण खेलों का हाल बेहाल था। पिछली 10 जून को परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया था। 12 जून को उसका पुनर्गठन होना था। शिक्षामंत्री श्री भंवरलाल शर्मा ने पुनर्गठन का मामला मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री इस दुविधा में पड़े थे कि परिषद का अध्यक्ष राजसिंह को बनाया जाये अथवा नहीं। चूंकि राजसिंह बंबई के रहने वाले हैं इसलिए उनके लिए खेलों को पूरा समय दे पाने का सवाल था। कई अटकलों के बाद 3 जुलाई को खेल परिषद का पुनर्गठन हुआ। नई परिषद बनने से राजस्थान के खिलाड़ियों में नई आशाओं का संचार हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार ने वास्तव में परिषद की शुद्धिकरण का प्रयास किया है, उसे चिनौनी राजनीति से दूर रखने का प्रयत्न किया है।

पुनर्गठन में छ: नये सदस्य लिये गये हैं। तथा पुरानी परिषद में से सात नाम गायब हो गये हैं। इन सात नामों में से तो कुछ लोग राजस्थान में रहते ही नहीं थे। जैसे गुरु हनुमान। इस बार एथलेटिक्स और वालीबाल को भी परिषद में स्थान दिया गया है। एथलेटिक्स में राजस्थान के प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री रामसिंह लिये गये हैं। इससे लगता है कि खेलों के विकास के लिए वास्तव में वे ही लोग काम करेंगे जो लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं। वालीबाल के बुजुर्ग प्रशिक्षक 70 वर्ष के हाफिज अब्दुल गफूर को भी परिषद में स्थान दिया गया है। परिषद के शुद्धिकरण में सरकार सफल हुई है। हालांकि पुनर्गठन से पहले शिक्षा मंत्री का कई बार घेराव हुआ। कुछ लोग तो दिल्ली के चक्कर काटने लगे थे। यहां तक कि एक सज्जन ११ विधायकों की सिफारिश भिजवाकर अपने आपको परिषद का सदस्य समझ बैठे थे, फिर भी ऐसे लोगों को परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। ऐसे लोगों के कारण ही पिछले तीन चार वर्षों से राजस्थान में खेलों का हाल बेहाल था। जिला खेल परिषदों की स्थिति तो काफी डांवाडोल हो गयी थी। खेल प्रेमी शिक्षा मंत्री ने जिला परिषदों में भी खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की है।

अफसोस यह है कि इस बार छात्रों को खेल परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। होना यह चाहिये था कि तीनों विश्वविद्यालयों के खेल बोर्डों के अध्यक्षों को परिषद में लिया जाता ताकि छात्रों का सही मानों में प्रतिनिधित्व हो सके। लेकिन कुल मिलाकर परिषद में सही लोगों को लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। देखना यह है कि बम्बई में प्रवास करने वाले परिषद के अध्यक्ष राजसिंह राजस्थान के खेलों के लिए कितना समय दे पाते हैं तथा नये व अनुभवहीन उपाध्यक्ष सांसद नाथूसिंह, जिनका खेलों से पुराना सम्बन्ध नहीं रहा है, के कन्धों से वह कितना भार हलका कर पाते हैं।

हलचल

अंत्योदय सम्पूर्ण क्रांति का दूसरा चरण

जयप्रकाश नारायण ने राजस्थान में शुरू किये गए अन्त्योदय कार्यक्रम को सम्पूर्ण क्रांति के दूसरे चरण का एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। जनता सरकार के एक वर्ष का शासनकाल पूरा होने पर राजस्थान की जनता के नाम भेजे गये एक संदेश में श्री नारायण ने कहा है कि उन्हें यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान सरकार ने लगभग डेढ़ लाख निर्धनतम परिवारों को अपनी विकास योजना में शामिल किया है और उन्हें प्राथमिकता दी है। श्री नारायण ने कहा है सरकार ने यह एक अद्भुत कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हर साल गांव के पांच निर्धनतम परिवारों का चयन किया जायेगा। मुझे बताया गया है कि ८० हजार परिवारों के लिए जीविकोपार्जन के साधन जुटाये गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष महात्मा गांधी की समाधि पर जनता पार्टी के नेताओं ने शपथ ली थी कि वे अन्त्योदय कार्यक्रम चलायेंगे।

गान्धीजी ने हमेशा अन्त्योदय पर जोर दिया था। आजादी के बाद ही यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना चाहिए था, किन्तु श्री जवाहरलाल की आधुनिकीकरण की योजना के कारण गांवों की उपेक्षा होती रही।

श्री नारायण ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया है वह कठिन अवश्य है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद वह इस कार्य को पूरा करेगी। उन्होंने राज्य के युवकों एवं छात्रों से अपील की है कि वे गरीबों के उत्थान के इस बुनियादी कार्यक्रम में जुट जायें। उन्होंने केन्द्र सरकार और विशेष रूप से योजना आयोग से भी अपील की है कि वे अन्त्योदय कार्यक्रम को अपनी योजना में स्थान दें।

श्री जयप्रकाश ने कहा कि उनका स्वास्थ्य इजाजत देता तो वे स्वयं राजस्थान जाकर अन्त्योदय कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देते। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत और स्वास्थ्य-मन्त्री श्री त्रिलोकचन्द ने मुझे अन्त्योदय कार्यक्रम की प्रगति की जो जानकारी दी है उससे मुझे खुशी हुई है।

यह खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार अपने बजट का ६४ प्रतिशत गांवों के विकास हेतु खर्च कर रही है। उन्होंने राजस्व अभियान के अन्तर्गत किसानों के जमीन सम्बन्धी नौ लाख मामलों को गांवों में निपटाने के प्रयास पर भी बधाई दी है।

स्वीडी अर्थशास्त्री मिर्डाल का कथन : शिक्षा पर चर्चा बहुत लेकिन सुधार नहीं

विख्यात स्वीडी अर्थशास्त्री श्री गुन्नार मिर्डाल का मत है कि भारत में शिक्षा के बारे में चर्चा तो ईमानदारी से तथा बड़ी गहराई से हुई है, किन्तु इस क्षेत्र में सुधार बहुत ही कम हो सका।

शीघ्र ही विमोचित होने वाली पुस्तक 'दि सोशियल कान्टेक्ट आफ एज्यूकेशन' में छपे उनके लेख में उक्त धारणा प्रतिपादित है। यह पुस्तक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री जे. पी. नाईक के सम्मान में है।

स्वीडी अर्थशास्त्री का कहना है कि अन्य गरीब देशों की भांति ही भारत में भी छात्रों की उपस्थिति नियमित नहीं है तथा कई छात्र बीच में ही शिक्षा को छोड़ देते हैं। इन सब कारणों से शिक्षा क्षेत्र में साधनों का बहुत अधिक अपव्यय होता है।

भारत में विद्यमान आर्थिक-सामाजिक वर्गीकरण के कारण प्रशासकों शिक्षकों तथा छात्रों के निहित स्वार्थ हैं। जो स्कूली प्रणाली चली आ रही है उसके कारण उच्चवर्गीय परिवारों की विशेष स्थिति बनी हुई है। यह वर्ग अपनी उस स्थिति कोछोड़ने को कतई तैयार नहीं है।

विकास को गति देने के लिए यहां की शिक्षा बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। यहां शिक्षा विकास में बाधक ही है।

स्वाधीनता के बाद आवाज उठायी गयी कि सारी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाय। किन्तु ऐसा किया नहीं गया। श्री मिर्डाल ने शिक्षा आयोग १९६६ के 'शानदार प्रतिवेदन' को उद्‌धृत किया है। इस प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इन्दिरा गांधी का प्रमाण पत्र सही नहीं

श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने स्वतन्त्रता सेनानियों वाला ताम्रपत्र प्राप्त करने के लिए जेल का जो प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था, वह सही नहीं पाया गया।

राज्य के पर्वतीय विकास और राजनीतिक पेंशन राज्यमन्त्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने संवाददाताओं से कहा है कि श्रीमती गांधी ने नैनी (इलाहाबाद) जेल का नौ महीने बन्द रहने का प्रमाणपत्र दिया था। सुविज्ञ सूत्रों से यह पता चला है कि श्रीमती गांधी केवल दो-ढाई महीने ही जेल में रहीं। गर्भवती होने के कारण उन्हें पेरोल पर छोड़ दिया गया था।

२३ लाख रुपये की पुस्तकों की समस्या

अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के सम्मेलन में एक दिलचस्प, लेकिन हिन्दी-प्रेमियों को निराश कर देने वाला तथ्य सामने आया। पता चला कि नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य अकादमी द्वारा हिन्दी में प्रकाशित २३ लाख रुपये की पुस्तकें नहीं बिक रहीं।

शिक्षा मन्त्री डा० चन्द्र ने पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों की भाषा की पुस्तकों में लाने की बात सम्भवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कही।

छः करोड़ वयस्कों को पढ़ाने की योजना

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने आगामी पांच वर्ष में साढ़े छह करोड़ लोगों को साक्षर करने के विशाल वयस्क शिक्षा कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी है। इस पर कुल मिला कर छह अरब रुपये खर्च होंगे। पिछले तीन वर्षों के शिक्षा प्रसार अभियान में यह सबसे बड़ा और व्यापक अभियान है। इसमें १५ से ३५ वर्ष के बीच की आयु के लोगों को साक्षर बनाया जाएगा।

वयस्क शिक्षा का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम २ अक्तूबर को गान्धी जयन्ती के दिन से प्रारम्भ होगा, ग्रामीण विकास और वयस्क शिक्षा का तालमेल बैठाकर चलने वाला कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित होगा। इसका आधा व्यय भी राज्य सरकारें उठायेंगी।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने वयस्क शिक्षा में स्वयंसेवी संगठनों के व्यापक सहभाग की नीति को भी स्वीकार किया। स्वयंसेवी संगठनों के चयन की कसौटी के लिए निर्देशक सिद्धांत तैयार कर लिए गये हैं। भूतपूर्व शिक्षामंत्री डा. वी०के०आर० वी० राव की अध्यक्षता में इस योजना की तैयारी के लिए एक समिति बनायी जा चुकी है।

पश्चिम बंगाल आदर्शवाद की लड़ाई का मुख्य युद्धस्थल होगा

—डा० सुब्रमण्यम स्वामी

कलकत्ता में स्थापना दिवस समारोह में भाषण करते हुए डा० सुब्रमण्यम स्वामी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पश्चिम बंगाल शाखा द्वारा कलकत्ता में आयोजित परिषद के ३० वें स्थापना दिवस समारोह में संसद सदस्य डा० सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल आदर्शवाद की लड़ाई का मुख्य "युद्धस्थल" होगा। भारत में मार्क्सवाद के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि यहां वर्ग संघर्ष नहीं है। हमारी संस्कृति मानवतावाद की संस्कृति है। बेकारी की समस्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर यह समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए निजी प्रयासों को तेज करना होगा। नौकरी की नहीं, निजी रोजगार की मनोवृत्ति बढ़ानी होगी। पाखंड की भावना खत्म करने पर जोर देते हुए डा० स्वामी ने कहा कि भारत द्वारा विश्व का पथ प्रदर्शन अनिवार्य है। पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद सब विफल हुए हैं। अतः अब भारत द्वारा नैतिक मूल्य बोध का नेतृत्व जरूरी हो गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बंगला साहित्य अकादमी के सचिव श्री विनय सरकार ने की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जनता पार्टी के नेता श्री काशीकान्त मैत्र ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने आदर्शानुसार राजनीति करनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद के प्रादेशिक अध्यक्ष डा० ध्यानेश नारायण चक्रवर्ती ने आपातकाल एवं तानाशाही से मुक्ति में विद्यार्थी परिषद के योगदान का उल्लेख किया। श्री विनय सरकार ने छात्रों के कर्तव्य पर प्रकाश डाला। प्रदेश सचिव श्री पार्थ बन्दोपाध्याय ने विद्यार्थी परिषद द्वारा रचनात्मक कार्यों को विशेष महत्व देने की दृष्टि से छात्रसंघ चुनावों से दूर रहने एवं सम्पूर्ण छात्रशक्ति को संगठित करने की नीति की घोषणा की। 'आनन्द बाजार पत्रिका' के सहसम्पादक श्री रवीन्द्र मोहन बन्दोपाध्याय ने परिषद के रचनात्मक कार्यों को सराहा। अन्त में 'ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान' के प्रमुख कार्यकर्ता डा० देवेश विश्वास ने धन्यवाद ज्ञापन किया। स्थापना दिवस के इस समारोह में विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मन्त्री श्री लक्ष्मीनारायण भाला पूरे समय तक उपस्थित रहे।

सिलीगुड़ी

पश्चिम बंगाल में अन्यान्य स्थानों पर मनाये गये कार्यक्रमों में उल्लेखनीय है—सिलीगुड़ी स्थित उत्तर बंग विश्वविद्यालय के प्रांगण में मनाया गया कार्यक्रम। प० बंगाल विधान सभा सदस्य प्रो० विष्णुकान्त शास्त्री इसके प्रमुख वक्ता थे। छात्र नेता पवित्र झा एवं स्वपन राय चौधरी ने भी भाषण दिया। सिलीगुड़ी कालेज के आचार्य डा० सितांशु भूषण दास सभापति थे। डा०एस० आर गुप्त, श्री परितोष साहा, अशोक भट्टाचार्य, गौतम चक्रवर्ती आदि ने गीत एवं काव्यपाठ कर कार्यक्रम में विविधता निर्माण की एवं श्री विवेकानन्द चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

मालदा

मालदा के कार्यक्रम में प्रा० विमल बिहारी चालित एवं श्री सुधांशु ज्योति राय तथा श्री आशिष कुमार दास आदि ने भाषण दिए। प्रा० विष्णुकांत शास्त्री प्रधान वक्ता के रूप में उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने शिक्षा क्षेत्र के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रसंघों के चुनाव न लड़ने के निर्णय को एक असाधारण कदम बताया।

मेदिनीपुर

मेदिनीपुर, बरहमपुर एवं हावड़ा के परिषद कार्यक्रम में गोष्ठियों का आयोजन किया गया एवं विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार इन विचार गोष्ठियों में प्रकट किए।

वाराणसी

वाराणसी में विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति शिक्षा जगत से संबंधित लोगों के लिए स्वयं में एक चुनौती है। आपने शैक्षणिक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिन्ता प्रकट की तथा कहा कि विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए समर्थ है। आचार्य मिश्र ने विद्यार्थी परिषद के 'ज्ञान-शील-एकता' की व्याख्या गीता के उद्धरणों से करते हुए कहा कि ज्ञान की निर्मलता और महत्ता बिना आचरण के नहीं तथा आचरण युक्त ज्ञान एकता के लिए उपयोगी है।

दिल्ली

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित स्थापना दिवस समारोह में संसद सदस्य सुन्दरसिंह भंडारी मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता दिल्ली के भूतपूर्व मेयर लाला हंसराज गुप्त ने की। विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मन्त्री श्री गोविन्दाचार्य मुख्य वक्ता थे।

जयपुर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित स्थापना दिवस समारोह में सुप्रसिद्ध साहित्यकार डा० लक्ष्मी नारायण लाल तथा संसद सदस्य नाथू सिंह उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने कार्यक्रम में उपस्थित परिषद के ३०० कार्यकर्ताओं तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जब देश के अधिकांश छात्रसंघों पर विद्यार्थी परिषद का कब्जा है ऐसी स्थिति में छात्र संघों के चुनाव न लड़ने का निर्णय करके विद्यार्थी परिषद ने एक असाधारण कदम उठाया है। इन्होंने कहा कि इस शताब्दी में हर कार्य में राजनीति हावी है। ऐसे समय में गैर राजनीतिक संस्थाओं को कार्य करना मुश्किल होता जा रहा है। डा० लाल ने परिषद के तीन सूत्र, ज्ञान, शील, एकता की व्याख्या की और कहा कि शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान विद्यार्थी परिषद को ही करना है।

WITH BEST COMPLIMENTS

FROM

HINDUSTAN TEXTILE EXPORTS

BOMBAY

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

जय टायर एण्ड रबर इण्डस्ट्रीज

कारखाना :

इण्डस्ट्रियल इस्टेट, महेशपुर

पो० आ० वाराणसी कैण्ट

कार्यालय :

पिपलानी मार्केट, कबीर रोड

वाराणसी

जयको साइकिल ट्यूब

एवं

सुपर जयदीप रिक्शा ट्यूब

के विक्रेता

फोन : आफिस : ५२५३५
फैक्टरी : ५२५३६
निवास : ६६८०९

श्री अरविन्द ..... पृष्ठ २१ का शेष

अवरुद्ध करने का प्रयास करे अथवा किये हुए संपूर्ण प्रयासों पर पानी फेरने में भी सफल हो जाय। किन्तु अंतिम विजय के बारे में कोई संदेह नहीं। मानवीय एकता-प्रगति की एक आवश्यकता है। तदनुरूप प्रगति अनिवार्य है। विभिन्न राष्ट्रों को भी उसकी उतनी ही आवश्यकता है। इस मानवीय एकता के अभाव में छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता का किसी भी क्षण अपहरण हो सकता है। बड़े सशस्त्र राष्ट्रों का जीवन भी असुरक्षित रहता है अतः एकता सभी के हित में है। मानव की युद्ध-पिपासा और क्षुद्र स्वार्थ ही इस एकता में सबसे बड़ी बाधायें हैं। किन्तु नैसर्गिक आवश्यकता और ईश्वरीय इच्छा के सम्मुख ये सब बाधायें अधिक काल तक टिक नहीं सकती। फिर भी केवल बाहरी ढांचा ही पर्याप्त न होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मनोवृत्ति व दृष्टिकोण का विकास करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं आंदोलन गतिमान होने चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति को दो या अधिक देशों का नागरिकत्व प्रदान करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने अथवा एकता के सुदृढ़ करने वाले अन्य उपायों को अपनाया जाय। उस स्थिति में राष्ट्रवाद को 'पूर्णता' प्राप्त हो सकेगी। उसका सैनिक स्वरूप निरुपयोगी हो जावेगा और उपरोक्त बातें उसके अस्तित्व की सुरक्षा और दृष्टिकोण के विपरीत दिखाई नहीं देंगी। समस्त मानवता एक भावना की नवचेतना से आप्लावित हो उठेगी।

मेरा एक और भी स्वप्न था। वह यह कि भारत अपनी आध्यात्मिक वसीयत संपूर्ण विश्व को प्रदान करे। यह प्रवाह पहले से ही प्रारम्भ हो चुका है तथा यूरोप व अमरीका में भारतीय ज्ञान के प्रकाश का विस्तार तीव्र से हो रहा है। इस प्रकाश का विस्तार इसी गति से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मानवता को ग्रसने के लिए काल अपने जबड़े फैलाता जायेगा वैसे-वैसे अधिकाधिक राष्ट्र भारत की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगेंगे और केवल हमारी आध्यात्मिक शिक्षा को ही नहीं अपितु योग एवं अध्यात्म साधना को भी अंगीकार करने लगेंगे।

मेरा अंतिम स्वप्न था उत्क्रांति के ऊपरी सोपान पर चढ़ना। एक उच्च व विशाल चेतना में मानव का उत्थान किया जाय और अनादिकाल से—जबसे मानव व्यक्तिगत पूर्णत्व और परिपूर्ण समाज का विचार करने और उसके स्वप्न संजोने लगा, तबसे आज की किंकर्तव्य विमूढ़ता और निराशा के गर्त में डूबने तक की स्थिति से संबंधित सभी समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाय। यही मेरा स्वप्न था। यह स्वप्न आज भी मेरी व्यक्तिगत आशा और कल्पना के रूप में विद्यमान है। भारत के साथ ही पश्चिमी जगत में भी कुछ दूरदर्शी लोगों का इस ध्येय के प्रति आकर्षण धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। इस मार्ग की कठिनाइयां अन्य मार्गों की कठिनाइयों से कहीं अधिक भयंकर हैं। किन्तु संकट आते ही इसलिए हैं कि मानव उस पर विजय प्राप्त करे और यदि ईश्वरीय इच्छा का अधिष्ठान उसे प्राप्त हो तो उसमें विजय भी निश्चित ही होगी। इस प्रकार की उत्क्रांति अध्यात्म व अन्तर्ज्ञान से ही संभव हो सकेगी। उस उत्क्रांति का प्रणेता भी भारत ही रहेगा। उसका कार्य-क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व भले ही हो पर उसका केन्द्र भारत ही होगा।

भारत के इस स्वाधीनता दिवस का उपरोक्त अर्थ ही मुझे अभिप्रेत है। यह आशा कितने प्रमाण में और किस रीति से पूर्ण हो सकेगी यह बात भी नये स्वतन्त्र भारत पर ही अवलम्बित है।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

GHANSHYAM DASS KRISHAN KUMAR

AUTHORISED DEALERS OF

Nettle Fold Products

all kinds of

IRON, BRASS MACHINE SCREW, WOOD SCREW ALLEN BOLT, NAILS

MERCHANT AND GENERAL ORDER SUPPLIERS

3480, HAUZ QAZI, DELHI-110006

Phone : 264019

दृष्टिकोण

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन का आधार

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन विश्व जनमत की वर्तमान अवस्था के सन्दर्भ में और विशेषकर विश्व छात्र समुदाय के मत के संदर्भ में अवलोकन ही है। आधुनिक विश्व एक अनवरत तनाव की अवस्था में है। द्विपक्षीय झगड़ों, आन्तरिक लड़ाइयों आदि से विश्व वर्गों, समूहों एवं विभिन्न गठजोड़ों में बंट चुका है। विश्व कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति संरचना के आधार पर सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इससे प्रभुत्व तथा राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भों में शोषण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की जन्य शक्तियों ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं और मानवीय गरिमा को पदच्युत करके महत्वहीन बना दिया है और विश्व भर की सरकारों और जनता ने मानवीयता पर किये जा रहे इस प्रहार पर अपनी प्रतिक्रिया ईमानदारी से नहीं बल्कि सुविधानुसार व्यक्त की। इस प्रक्रिया में मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के सत्य को सदा हानि पहुंची है और ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व मत इस बारे में चिन्तित ही नहीं है।

हम देखते हैं कि सरकारें उचित या अनुचित ढंग से इन मौलिक विषयों पर ऐसा रूख अपनाती हैं जो उनकी अपनी विचारधाराओं के विपरीत है। वस्तुतः हमने शक्तिशाली लोकतन्त्रीय सरकारों द्वारा लोकतन्त्र के नाम पर नग्न तानाशाही और क्रूरता का समर्थन करने का दृश्य देखा है। सभी सामाजिक कम्युनिस्ट तानाशाह सरकारों की स्थापना लोकतन्त्र के नाम पर की गई थी और लोकतन्त्र के नाम पर ही उनका निरन्तर पोषण हो रहा है। यहां तक कि हमारे देश की भूतपूर्व तानाशाह प्रधानमन्त्री भी लोकतन्त्र की दुहाई देती थी। मैं यहां उस दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी सरकार को अपनाना चाहिए। मैं विश्व की जनता के संदर्भ में बात कर रहा हूं।

यही समय है कि विश्व समुदाय इस तथ्य को स्वीकार करे कि प्रत्येक व्यक्ति ने सम्मान और स्वतन्त्रता के अविभाज्य मौलिक अधिकारों के साथ जन्म लिया है। यह महत्वहीन है कि इन अधिकारों को किसी देश के संविधान में स्थान मिला है या नहीं। यह भी महत्वहीन है कि किसी एक निश्चित समय पर किसी देश के लोगों के पास उन अधिकारों को लागू करने एवं उनकी रक्षा करने का तन्त्र उपलब्ध है अथवा नहीं। किसी देश के राजनीतिक ढांचे में किसी तकनीकी अथवा वास्तविक त्रुटियों के रहने पर भी प्रत्येक व्यक्ति में ये अधिकार निहित होते हैं। यही समय है कि सभी यह स्वीकार करें कि इन अधिकारों की सुरक्षा एवं आदर का प्राविधान होना चाहिए।

प्रो० बाल आप्टे

क्या विश्व जनमत इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई योगदान दे सकता है? इसका उत्तर निश्चित रूप से सकारात्मक है। इस दिशा में विश्व जनमत को तैयार करने का सम्मिलित प्रयास किया जाना चाहिए। हमारा विश्वास है कि विश्व का छात्र समुदाय इस विषय में अत्यन्त प्रभावी भूमिका निभा सकता है। विश्व भर के छात्र एक पृथक सामाजिक वर्ग के रूप में उभरकर सामने आये हैं और पिछले २० वर्षों में छात्रों की कार्यशीलता ने उनके अपने-अपने देशों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह युवा समुदाय इस आन्दोलन की अग्रिम पंक्ति में रह सकता है।

विश्व जनमत के निर्माण के लिए एक "विश्व छात्र मंच" की स्थापना उचित होगी। इस मंच का सरकारों से और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से कोई संबंध नहीं होगा। यह मंच सभी प्रकार के वर्गों एवं संगठनों की राजनीति से ऊपर रहेगा। यह मंच युवा एवं शिक्षित वर्ग की चेतना को ललकारेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र मंच की स्थापना के लिए कुछ प्रयास पहले भी किये गए थे पर जिस तरह के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद से इन प्रयासों को प्रेरणा मिली, वह स्वयं अपने उद्देश्यों और प्रयासों में असफल रहा। इन प्रयासों के जिस प्रकार से विचारात्मक अर्थ लगाये गये अथवा राजनीतिक हितों को दृष्टि में रखकर उन्हें लागू किया गया, उनके कारण यह प्रयास एक "शक्ति समूह" के प्रयास बन गए जो विश्व अथवा विश्व के किसी एक भाग में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा हो। हम इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद को अस्वीकार करते हैं जो बाह्य नियन्त्रण को स्थापित करता हो क्योंकि यह उन आधारभूत मूल्यों के पूर्णतः विरुद्ध है जिनका हम समर्थन करते हैं अर्थात 'व्यक्ति का सम्मान'। हम किसी भी प्रकार के एकाधिकारवाद या साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता में हमारा विश्वास है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रीयतावादी संगठन है। यह संगठन अनुभव करता है कि विश्व की सभी राष्ट्रीयतावादी शक्तियां एक ऐसे विश्व का निर्माण कर सकती हैं जहां व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा हो, व्यक्तिगत सम्मान का आदर हो और व्यक्ति के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों का उपयोग किया जाए।

क्या हम विश्व भर के छात्र ऐसी घोषणा कर सकते हैं कि मौलिक स्वतन्त्रताएं अपरिवर्तनीय हैं? क्या हम सिद्ध कर सकते हैं कि समतापूर्ण समाज की स्थापना मानवीय अधिकारों की सुरक्षा से विरोध नहीं रखती? क्या हम सिद्ध कर सकते हैं कि मनुष्य की रोटी और कपड़े की आवश्यकताओं को उचित ढंग से पूरा करते हुए ऐसी उचित परिस्थितियां भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं जिसमें स्वतन्त्रता तथा विरोध रखने का अधिकार प्राप्त हो? क्या हम इस धारणा का पर्दाफाश कर सकते हैं कि किसी विकासशील देश के लिए रोटी और स्वतन्त्रता साथ-साथ नहीं रह सकते?

With

B
e
s
t

Compliments

From

★

AEVEE IRON & STEEL WORKS (P.) LTD.

★

ELDEE CHAMBERS, 3, BROACH STREET

BOMBAY-400 009

साक्षरता का सवाल

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सामाजिक रूपरेखा की चर्चा करते हुए कहा है कि हम निरक्षरता को समाप्त करेंगे— **"पाँच से दस वर्ष के भीतर निरक्षरता को समाप्त कर दिया जाएगा।"** इस दिशा में कुछ हुआ हो, ऐसा दीखता तो नहीं है और यदि कोई योजना बनी भी हो तो वह साक्षरता की परम्परागत योजना है। उस पर अमल कठिन है, और उसका कोई सार्थक परिणाम होने वाला नहीं है। साक्षरता के सवाल को पूरी शिक्षा योजना के सन्दर्भ में देखा जाए तो यह तथ्य मिलेगा कि इसे दूर करना करीब-करीब असंभव है। **आज स्थिति यह है कि अधिकांश लोगों की कीमत पर थोड़े से लोग पढ़ रहे हैं।** पढ़ाई का तरीका ऐसा है जो समाज से हमारे जीवन सम्पर्क की जड़ निरन्तर काटता जाता है। एक पढ़ा-लिखा युवक आज सबसे ज्यादा परजीवी है। **शिक्षण का यही तरीका लेकर साक्षरता के जो प्रयोग हुए हैं उनका अनुभव यही आया है कि गांव में जो थोड़ा-बहुत सीखते हैं उनका एक अलग ही वर्ग बन जाता है।** वे एक नये 'लिमिटेड' तैयार हो जाते हैं। साक्षरता के दो उद्देश्य है—सामान्यतः लिखना-पढ़ना आ जाये और अपने आस-पास की सामाजिक, राजनैतिक घटनाओं की समझ पैदा हो सके। **संक्षेप में कहें तो आज साक्षरता की दृष्टि यह होनी चाहिए कि निरक्षर व्यक्ति में वह सामाजिक बोध जगा सके।** निरक्षरता भी दो प्रकार की है —अक्षरों की निरक्षरता और जीवन की निरक्षरता। **जिन्होंने अक्षरों को पहचाना ही नहीं वे भी निरक्षर हैं और जो अक्षर पहचानने की मशक्कत में जीवन पहचान न सके, वे भी निरक्षर हैं।** दोनों के लिए योजना बननी चाहिए और बन सकती है। साक्षरता का व्यापक अभियान चलाया जाये—एक साथ पूरे देश में या अलग-अलग प्रान्तों में कम-से-कम तीन महीने का एक दौर चलाया जाये। **एक-एक गांव की जिम्मेदारी देकर एक-एक टोली बनायी जाये जिसमें शिक्षक भी शामिल रहें।** हर टोली अपना-अपना गांव संभाले और वहां **गांव की सफाई** और **सुलभ शौचालय** तथा **निरक्षरता-निवारण** के ही कामों में जुटे। इसी काम के लिए योजनापूर्वक विश्वविद्यालय-महाविद्यालय के शिक्षण कार्यक्रमों में कुछ बदल किये जायें। साधन सरकार जुटाये, स्वयंसेवी संस्थाएं दें। भोजन की व्यवस्था गांवों के ऊपर भी रह सकती है। इससे शिक्षण दोनों प्रकार का होगा—गांव की समस्याओं के सामने आकर पढ़ने-पढ़ानेवाले समझ सकेंगे कि जीवन की समस्या क्या है। गांव की सफाई और शौचालय की व्यवस्था से उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, वे सीख सकेंगे। गांव वाले उनके साथ इसमें शामिल होकर उत्साहित और आलोकित होंगे। दूसरी तरफ साक्षरता के लिए वर्ग चलाने पड़ेंगे। **दोनों पक्ष की निरक्षरता दूर होगी।** शिक्षा का आज का सुविधाभोगी ढांचा भी धक्के खायेगा। अभियान अवधि के प्रारम्भ और आखिर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, ग्रामीणों की निरीक्षण टोलियां घूमकर प्रगति का अनुमान करेंगी और आगे के लिए योजना में आवश्यक फेरबदल करेंगी। अपने देश की विशाल जनसंख्या और जड़ प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ढांचा ऐसे हिम्मती कदम के बगैर हिलने वाला नहीं है। निरक्षरता दूर करने के लिए व्यापक जनशक्ति का ऐसा उपयोग आवश्यक है।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक, अरुण जेटली द्वारा मॉडर्न प्रिंटर्स, के-३०, नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२ में मुद्रित तथा ई/२६२, नारायण विहार, नई दिल्ली-११००२८ से प्रकाशित।